दीक्षांत
Education Centre

दीक्षांत समसामयिकी

जुलाई 2022

क्या है खास....

- भारत-स्वीडन उद्योग संक्रांति वार्ता
- नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFM)
- अग्निपथ योजना
- भारत-आसियान सम्मेलन और इसके निहितार्थ
- भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)
- G7 शिखर सम्मेलन
- मंकीपॉक्स
- दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना 'फ्रंटियर'
- वैश्विक पहल 'पर्यावरणीय जीवनशैली-लाइफ अभियान'
- गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022
- राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022
- यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

करेंट अफ़ेयर्स की बेहतर तैयारी हेतु
दीक्षांत एप पर
निःशुल्क साप्ताहिक करेंट अफ़ेयर्स
टेस्ट में अवश्य भाग लें।

दीक्षांत ऐप डाउनलोड
करने के लिए
QR Code स्कैन करें।

VISIT US: DIKSHANTIAS.COM
9312511015
8851301204
FACEBOOK.COM /DIKSHANT.IAS.7
YOUTUBE.COM /DIKSHANTIAS
TWITTER.COM /DIKSHANTIAS
INSTAGRAM.COM /DIKSHANTIAS
T.ME/ DIKSHANTIAS

दीक्षांत
Education Centre

68th BPSC PRE+MAINS

सामान्य अध्ययन

ऑनलाइन/ऑफलाइन

- दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की टीम द्वारा
- 600 घंटे का कक्षा कार्यक्रम
- अद्यतन पाठ्यक्रम सामग्री (40 बुकलेट)
- डेली टेस्ट (150 टेस्ट) + यूनिट टेस्ट - 16 टेस्ट
- वर्क बुक - 8
- करेंट अफेयर्स एवं बिहार स्पेशल की विशेष कक्षाएँ
- डाउट क्लियरेंस हेतु विशेष मेन्टर की व्यवस्था

नामांकन प्रारंभ / **सीमित सीटें**

Fee
~~₹75,000~~
₹30,000
only

*Inaugural fee for first 200 students

कक्षा जारी @6 PM

TO REGISTER INSTALL DIKSHANT APP/ ADD.: 289, DHAKA JOHAR, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09, CALL : 7428092240

दीक्षांत समसामयिकी

जुलाई, 2022

दीक्षांत
Education Centre

मुख्य संपादक
डॉ. एस एस पाण्डेय

डायरेक्टर
शिप्रा पाण्डेय

कार्यकारी संपादक
राकेश पाण्डेय

सह-कार्यकारी संपादक
साकेत आनंद

प्रबंधन परामर्श
शंकर भारती, मरीना

सम्पादन सहयोग
विपिन, नीरज, वंदना गुप्ता, विकास तिवारी, मो. शोएब, अजय द्विवेदी, संतोष अभिजीत, प्रकाश जायसवाल, मनोज सिंह, विशाल, कुणाल, सोनम रावत

टाइप सेटिंग व डिज़ाइनिंग
सूर्यजीत, पूजा, सुनील, शकिबा सोनू, प्रवीण, जितेन्द्र

****

- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाइटों से गैर-व्यवसायिक एवं शैक्षणिक उद्देश्य से लिये गये हैं और हम इसके लिये उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

IAS   DIKSHANT   दीक्षांत Education Centre   PCS
18 वर्षों से ईमानदार प्रयास

FREE COACHING & Scholarship Programme

GENERAL STUDIES
NEW FOUNDATION BATCH
ENGLISH MEDIUM
5 JULY 6 PM

सामान्य अध्ययन
नया फाउंडेशन बैच
हिन्दी माध्यम
5 JULY 6 PM

सीमित सीटें...   नामांकन प्रारंभ   जल्दी करें...

Online Course हेतु Google Play Store से Dikshant Education के App दीक्षांत को Download करके अपना रजिस्ट्रेशन करायें

विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें... 7428092240
289, DHAKA JOHAR, NEAR DUSSEHRA GROUND, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09

प्रधान कार्यालय
303, जैना बिल्डिंग एक्सटेंशन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
मोबाइल: 7428092240, 9312511015, 8851301204
ई-मेल: dikshantias2011@gmail.com, वेबसाइट: www.dikshantias.com

भोपाल शाखा
प्लॉट न. 48, 3rd फ्लोर, सरगम टॉकीज के पीछे, जोन-2, एमपी नगर, भोपाल
मोबाइल: 9301110498, 8982208515

अनुक्रम

न्यूज एक्सप्लेनर

- भारत-स्वीडन उद्योग संक्रांति वार्ता 6
- इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 8
- इथेनॉल सम्मिश्रण 10
- रिमोट वोटिंग 13
- नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFM) 16
- भारत-आसियान सम्मेलन और इसके निहितार्थ 19
- भारत में आकाशीय बिजली गिरने की समस्या 22
- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक 25
- अग्निपथ योजना 27

राष्ट्रीय घटनाक्रम

- आदिवासियों की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोकथाम लगाने वाले कानूनों को निरस्त करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका 31
- सोशल मीडिया नियमों में संशोधन का प्रस्ताव 32
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से जुड़े नियमों में परिवर्तन 32
- धर्मांतरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी 33
- श्रेष्ठ योजना 34
- सामरिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण 35
- दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए का दुरुपयोग और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय 35
- एनडीपीएस को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने की योजना 36
- इंडिया चाइल्ड वेल-बीइंग रिपोर्ट 2021 37
- भारत एनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी 37
- चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 'गैर-मौजूद' दलों को हटा दिया 37
- एमओएचयूए ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए 'निपुण' (एनआईपीयूएन) परियोजना शुरू की 38
- साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया 38
- केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हित में निष्पक्ष विज्ञापन के लिए नए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए 38
- रामकृष्ण मुक्काविल्ली यूएनजीसी द्वारा वैश्विक एसडीजी पायनियर के रूप में नामित होने वाले पहले भारतीय बने 39
- सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा 39
- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति का शुभारंभ किया 39
- अमित शाह ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) का उद्घाटन किया 40
- भारतीय वायु सेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा 40
- ई-संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया 40
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट 40

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

- इज़राइल-संयुक्त अरब अमीरात मुक्त व्यापार समझौता 42
- भारत-इज़रायल रक्षा सहयोग 42
- भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वीं बैठक 43
- भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 44
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र 45

- G7 शिखर सम्मेलन 46
- चीन ने आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के प्रस्ताव को बाधित किया 48
- मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किये जाने हेतु डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन बैठक 49
- यूरोपीय संघ ने यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया को सदस्यता के लिए 'उम्मीदवार' का दर्जा दिया 50
- जी20 की 2023 में बैठकों की मेजबानी करेगा जम्मू और कश्मीर 50
- गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए 50
- जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। 51
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की 51
- यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर भारत-प्रायोजित प्रस्ताव का अनुमोदन किया 51
- इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड को यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया 51
- 'भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030' के लिए संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर 52
- बिम्सटेक ने ढाका में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया 52
- संयुक्त राष्ट्र तुर्की का आधिकारिक नाम बदलकर 'तुर्किये' करने पर सहमत हुआ 52

अर्थ जगत

- भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक का प्रतिनिधित्व करेगा 53
- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 54
- विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की रिपोर्ट: 'गोल्ड रिफाइनिंग एंड रीसाइक्लिंग' 54
- मई 2022 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त) 24% बढ़ा 54
- रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना 55
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'स्टार्टअप फॉर रेलवे' नामक एक अभिनव नीति शुरू की 55
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने पीएलएफएस चौथी वार्षिक रिपोर्ट जारी की 55
- फिच रेटिंग्स ने भारत के रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव में बदला 56
- पीएसबी के लिए ईज़ 5.0 (EASE 5.0) 'कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा' निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया 56
- एनएचएआई ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 56
- भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रैंक में एक स्थान का सुधार 57
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एफएसएसएआई का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया 57
- एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट प्रकार का सौर संयंत्र मारुती सुजुकी द्वारा अपनी मानेसर सुविधा में स्थापित किया गया 57
- भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% किया 58
- आईआईएम अहमदाबाद ने छह राज्यों के लिए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक (ALPI) लॉन्च किया 58
- वित्त वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.7 फ़ीसदी तक कम हुआ 58
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी 4.1% की दर से बढ़ी 59
- भारत की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में पूर्व-कोविड स्तर से नीचे बनी हुई है 59
- सरकार ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा 59
- पीएमईजीपी योजना 13,554 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 26 तक बढ़ा दी गई 59
- आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई के आईटी संसाधन 'महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' घोषित 60
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। 60
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में प्रवास 2020-21 रिपोर्ट जारी की 61

विज्ञान एवं तकनीकी

- इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम 'सूर्य नूतन' 62
- दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट के साथ अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया 62
- फ्रेंच गयाना के कौरू से जीसैट-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 62
- कृषि मंत्री ने जानवरों के लिए देश की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया 62

- अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का उद्घाटन 63
- चीन ने चंद्रमा का नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया 63
- भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा बेंगलुरु में शुरू की गई 63
- भारत में एक नई टेलिस्कोप सुविधा सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्रग्रह जैसी वस्तुओं की पहचान करने में मदद करेगी 64
- दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना 'फ्रंटियर' 64

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

- जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए जैव विविधता नीति 65
- पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को लेकर उच्चतम न्यायालय का निर्णय 65
- वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है 67
- वैज्ञानिकों ने भारतीय जल में पहली बार अजूक्सैन्थेलेट कोरल (azooxanthellate coral) की चार प्रजातियों की खोज की 67
- मंगोलिया के खुव्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया 67
- महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड (MSBWL) ने 12 नए संरक्षण रिजर्व और तीन वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी 67
- मेघालय के री भोई जिले में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है। 68
- अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान सबसे नीचे 68
- दुनिया की पहली फिशिंग कैट की जनगणना चिल्का में हुई 68
- पीएम मोदी ने 5 जून 2022 को एक वैश्विक पहल 'पर्यावरणीय जीवनशैली-लाइफ अभियान' की शुरुआत की 69
- दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया 69
- 2017 में पाए गए एक गेको (छिपकली) की अब एक नई प्रजाति के रूप में पहचान की गई 69
- एनटीपीसी ने नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की 69
- इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना 70
- केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'लीडर इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट' कार्यक्रम की शुरुआत की 70
- पर्यटन मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रैटजी फॉर सस्टेनेबिल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिल ट्रैवलर शुरू की है 71
- कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर 71
- विद्युत मंत्रालय ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 को अधिसूचित किया 71

खेल जगत

- एशियन कप क्वालीफिकेशन के बाद भारत फीफा रैंकिंग में दो पायदान ऊपर 72
- 2026 फीफा विश्व कप तीन अलग-अलग देशों द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला विश्व कप होगा 72
- नीरज चोपड़ा ने फ़िनलैंड में 2022 कुओर्टेन खेलों में स्वर्ण पदक जीता 72
- राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंडमास्टर बनें 72
- चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर 73
- अवनि लेखारा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता 73
- भारत ने कजाखस्तान के अल्माटी में बोलाट तुर्लिखानोव कप में दूसरा स्थान हासिल किया 73
- फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने पुरुषों का खिताब जीता और इगा स्विएटेक ने महिलाओं का खिताब जीता 74
- भारत ने फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराकर पहली बार आयोजित एफआईएच हॉकी 5एस चैंपियनशिप जीती 74
- साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने बोलट तुर्लिखानोव कप में स्वर्ण पदक जीते 74
- भारत ने जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता 75
- भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता 75

राज्यनामा

- मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना 76
- गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना 76
- पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित 76

- हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया 77
- सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को अपने आधिकारिक राज्य तितली के रूप में घोषित किया 77
- ओडिशा में एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव 'सीतल षष्ठी' मनाया जा रहा 77
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया 77
- बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की घोषणा की 78
- स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया 78
- तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस (डब्ल्यूएनटीडी) पुरस्कार मिला 78

विविध

महत्त्वपूर्ण दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022: 23 जून 79
- विश्व वर्षावन दिवस: 22 जून 79
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: 21 जून 79
- विश्व शरणार्थी दिवस 2022: 20 जून 79
- विश्व महासागर दिवस 2022: 8 जून 80
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस: 7 जून 80
- विश्व पर्यावरण दिवस: 5 जून 80

नियुक्ति

- दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त 81
- लिसा स्टालेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनीं 81
- प्रमोद के मित्तल 2022-23 के लिए सीओएआई के नए अध्यक्ष बने 81
- सरकार ने रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में नामित किया 81
- राजदूत रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त 82
- मयंक अग्रवाल प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त 82
- एस एल थाओसेन को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया 82
- तपन डेका आईबी के नए प्रमुख नियुक्त 82

पुस्तकें और लेखक

- प्रधानमंत्री ने 'भारतीय संविधान: अनकही कहानी' नामक पुस्तक का अनावरण किया 83

पुरस्कार और सम्मान

- ओडिशा ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता 83
- सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए 83
- योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 84
- अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों में 'शेरशाह' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता 84
- प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया 84

निधन

- प्रसिद्ध उर्दू विद्वान गोपी चंद नारंग का निधन 84
- आईएनए दिग्गज अंजलाई पोन्नुसामी का निधन 85
- पंडित भजन सोपोरी का 02 जून 2022 को निधन 85

PRACTICE SET

- यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 86

भारत-स्वीडन उद्योग संक्रांति वार्ता

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, पर्यावरण	**तृतीय प्रश्नपत्र :** पर्यावरण प्रभाव आकलन

प्रसंग

- भारत और स्वीडन ने अपनी संयुक्त पहल 'लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन' (Leadership Group for Industry Transition- LeadIT) के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में स्टॉकहोम में "उद्योग संक्रांति वार्ता" की मेजबानी की।
- ज्ञातव्य है कि लीडआईटी पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है, जो वैश्विक जलवायु कार्य में प्रमुख हितधारक हैं और जिन्हें विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- इस उच्चस्तरीय संवाद ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 'स्टॉकहोम + 50': सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ धरती, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर' में योगदान दिया है। साथ ही, इसने सीओपी 27 के लिए एजेंडा निर्धारित किया है।

लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की गतिविधियां

- उद्योग संक्रमण ट्रैकर एक ऑनलाइन डेटाबेस है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उद्योग संक्रमण रोडमैप प्रदर्शित करता है।
- ट्रैकर यह बताता है कि किन देशों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उद्योग संक्रमण रोडमैप हैं।
- ट्रैकर की कार्यक्षमता उपयोगकर्ताओं को उद्योग संक्रमण रोडमैप के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने की अनुमति देती है, जिसमें उनके द्वारा लक्षित औद्योगिक मूल्य श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों, डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य और रोडमैप को लागू करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों, नीतियों और वित्तीय निवेश शामिल हैं।
- उद्योग संक्रमण ट्रैकर का उद्देश्य राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की ओर उद्योग संक्रमण में वैश्विक प्रगति का एक व्यापक अवलोकन करना है, विशेष रूप से 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन।
- ट्रैकर को उद्योग संक्रमण की स्थिति की कल्पना और पता लगाने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया गया है।

- इसके प्राथमिक दर्शक सरकारी अधिकारी और उद्योग क्षेत्र से जुड़े पेशेवर समूह हैं।
- ट्रैकर विश्व भर में मौजूदा उद्योग संक्रमण रोडमैप की विविधता को प्रदर्शित करके अपने विशिष्ट लक्ष्यों, जरूरतों और क्षमताओं के अनुरूप अपने स्वयं के डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप को डिजाइन करने के लिए देश और कंपनी के प्रयासों को समर्थन प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)

- यूएनईपी एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है, जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम के पर्यावरणीय आयाम के कुशल कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने को प्रतिबद्ध है।
- 1960 और 1970 के दशक में बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) आदि के अनुरूप पर्यावरण संबंधी चिंताओं के लिए कानूनों और विनियमों के बारे में विचार करने हेतु उत्प्रेरित किया है।
- इन चिंताओं को 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है) में संबोधित किया गया था। सम्मेलन ने स्टॉकहोम घोषणा (मानव पर्यावरण पर घोषणा) को आत्मसात किया गया।
- सम्मेलन के परिणामस्वरूप इन चिंताओं के लिए एक प्रबंधन निकाय का गठन भी हुआ, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा गया।
- यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है और इसका नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक करता है।

स्टॉकहोम+50

- स्टॉकहोम+50 का आयोजन स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाना है।
- यह मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी विदित) के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित किया जा रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा इस अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन करेगी।
- यह ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है, जब विश्व स्टॉकहोम घोषणा के 50 वर्षों के बाद भी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अपशिष्ट, प्रकृति और जैव-विविधता संकट का सामना कर रहा है।
- कोविड -19 महामारी प्रभाव का स्थायी निदान भी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं में से एक होगी।

स्टॉकहोम 1972

- यह पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की पहली घोषणा थी।
- स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में 5-16 जून तक आयोजित किया गया।
- इस बैठक में पर्यावरण और विकास से संबंधित 26 सिद्धांतों वाली एक घोषणा पर सहमति बनी।
- सम्मेलन से उभरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर्यावरण की रक्षा के लिए गरीबी उन्मूलन की मान्यता है।
- विदित है कि 1967 में एक शोध अध्ययन ने CO_2 स्तरों के आधार पर वैश्विक तापमान का वास्तविक अनुमान व्यक्त करते हुए यह भविष्यवाणी की गई थी कि मौजूदा स्तर से CO_2 के दोगुने होने से वैश्विक तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।
- स्टॉकहोम सम्मेलन का विचार सबसे पहले स्वीडन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसलिए इसे "स्वीडिश इनिशिएटिव" भी कहा जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है

नेट जीरो

- नेट जीरो से आशय सभी देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कार्बन न्यूट्रैलिटी अर्थात कार्बन के उत्सर्जन में तटस्थता लाना है।
- विदित है कि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई देश कार्बन के उत्सर्जन को शून्य पर पहुंचा दे (जो कि असंभव है) बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को यथासंभव शून्य के करीब लाने का प्रयास करना है। उदाहरण के लिए महासागरों और जंगलों द्वारा वातावरण से किसी भी शेष उत्सर्जन को फिर से अवशोषित कर लेना।
- अन्य शब्दों में, कोई देश वातावरण में कार्बन आधारित ग्रीनहाउस गैसों का जितना उत्सर्जन कर रहा है, उतना ही उसे सोख और हटा भी रहा है। अर्थात उसकी तरफ से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का योगदान न के बराबर हो। इसी को नेट जीरो के रूप में संदर्भित किया जाता है।

महत्त्व

- वैज्ञानिक दृष्टि से जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने और रहने योग्य ग्रह को संरक्षित करने के लिए, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आवश्यकता है ।
- वर्तमान में पृथ्वी पहले से ही 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म है और उत्सर्जन में वृद्धि अनवरत जारी है।
- ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पेरिस समझौते के अनुरूप उत्सर्जन को 2030 तक 45% तक कम करने और 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने की आवश्यकता है।

शुद्ध शून्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

- दुनिया में जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों (कार, बस, जहाज, आदि) और फ्रिज, एसी में बढ़ते सीएफसी के उपयोग के कारण ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी ज्यादा हुआ है। इस बढ़ते उत्सर्जन को हरे-भरे जंगलों के जरिए कम किया जा सकता है। पेड़ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वे ग्रीनहाउस गैसे उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र लगभग तीन-चौथाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्रोत है और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने की कुंजी भी है।
- प्रदूषणकारी कोयले, गैस और तेल से चलने वाले संयंत्रों को अक्षय स्रोतों से रूपांतरित करना यथा पवन या सौर ऊर्जा, नाटकीय रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा।

नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना क्यों आवश्यक?

- गत दो वर्षों से नेट जीरो के लक्ष्य पर लगातार बल दिया जा रहा है।
- विकसित देशों का कहना है कि अगर 2050 तक इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया, तो 2015 में हुए पेरिस समझौते को पूरा नहीं किया जा सकेगा।
- इस समझौते का लक्ष्य सदी के मध्य तक पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने से रोकना है।
- हालांकि, अभी जिस तरह से उत्सर्जन का स्तर जारी है, उससे सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

भारत का लक्ष्य

- ग्लासगो, स्कॉटलैंड में संपन्न शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश की स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा के अनुपात में उल्लेखनीय रूप से सुधार करने और 2070 तक शुद्ध शून्य होने के लिए भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों की घोषणा की।
- COP26 में भारत ने साहसिक निकट अवधि और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की।
- 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, जो वर्तमान में कोयले की स्थापित क्षमता के दोगुने से अधिक है। फलतः ऊर्जा क्षेत्र के त्वरित परिवर्तन के लिए विकल्प तैयार करना आवश्यक है।
- अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार, 2030 तक 50% बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आएगा और 450 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ा दिया गया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशन में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित पहल की जा रही है:

- "सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास" की परिकल्पना दिसंबर, 2014 में की गई थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2014-15 से शुरू होने वाले आगामी 5 वर्षों के भीतर 20,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखते हुए कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।
- यद्यपि, इसके अंतर्गत स्थापित क्षमता को 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दिया गया है। इन पार्कों को वर्ष 2023-24 तक स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- इस योजना में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचना को बनाने के उद्देश्य से देश में विभिन्न स्थानों पर सौर पार्क स्थापित करने में राज्यों/केंद्रों को सहायता देने की परिकल्पना की गई है।
- सौर पार्क उपयुक्त विकसित भूमि, पारेषण प्रणाली, पानी की पहुंच, सड़क संपर्क, संचार नेटवर्क आदि प्रदान करते हैं। इस योजना में व्यापक पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की सुविधा और गति प्रदान की गई है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना का उद्देश्य देश में सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि करना है।
- राष्ट्रीय हरित ऊर्जा गलियारा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित अक्षय ऊर्जा के संचरण के लिए ग्रिड से संबद्ध नेटवर्क है।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति के अंतर्गत अनिवार्य रूप से एक संरचना स्थापित करके व्यापक पैमाने पर पवन-सौर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना है।
- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति भारतीय समुद्र तट के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास करना है।
- भारत के सौर परिवर्तन (सृष्टि) योजना के लिए सतत रूफटॉप का कार्यान्वयन सुनिश्चित करके देश के भीतर सौर ऊर्जा संयंत्र रूफटॉप परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए लाभार्थी को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है।

स्रोत: द हिन्दू

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : पर्यावरण	**तृतीय प्रश्नपत्र :** पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण, ई-अपशिष्ट प्रबंधन

प्रसंग

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र (जो 2016 के नियमों का भाग नहीं था) प्रस्तुत करके पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रोत्साहित करने, एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किए गए ई-कचरे की मात्रा को प्रमाणित करने और कचरे के पुनर्चक्रण के लिए कंपनी के साथ सीधे अनुबंध करने की मंशा से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशन में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के मसौदे का अनावरण किया गया।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- आगामी पांच वर्षों में भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन कंपनियों में से एक दिल्ली-एनसीआर-मुख्यालय अटेरो रीसाइक्लिंग (मुख्यालय-दिल्ली-एनसीआर) ने अपनी लिथियम आयन-बैटरी अपशिष्ट रीसाइक्लिंग सुविधाओं के विस्तार में करीब 1 अरब डॉलर का निवेश करने की संभावना व्यक्त की है।
- ज्ञातव्य है कि इसका 70% से अधिक यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया में परिचालन स्थापित करने के लिए है, जो आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती हिस्सेदारी पर आधारित लिथियम-आयन बैटरी को रीसायकल करने के लिए है।

लीथियम ऑयन बैटरी

- लीथियम ऑयन बैटरी एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी है। इस बैटरी के अनावेशित होते समय इसमें लिथियम आयन इसके ऋणाग्र से धनाग्र की तरफ प्रवाहित होते हैं तथा बैटरी के आवेशित होते समय इसके विपरीत चलते हैं।
- ये बैटरियाँ आजकल के उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक सामानों में प्रायः उपयोग की जाती हैं और पोर्टेबल इलेक्ट्रानिक युक्तियों के लिये सबसे लोकप्रिय रिचार्जेबल बैटरियों में से एक हैं।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में लिथियम-आयन बैटरी को रसायनशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे दुनिया को जीवाश्म ईंधन से मुक्ति के साधन के रूप में उल्लेखित किया जाता है।

मसौदा नियम

- **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र**
  - प्रारूप नियमों का उद्देश्य ईपीआर या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र (जो 2016 के नियमों का हिस्सा नहीं था) पेश करके पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है ।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एक निश्चित मात्रा में कचरे के प्रसंस्करण पर पुनर्चक्रण करने वालों को इस संख्या की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स सामान कंपनियां अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन प्रमाणपत्रों को सीपीसीबी से ऑनलाइन खरीद सकती हैं।
  - ये प्रमाणपत्र एक कंपनी द्वारा एक विशेष वर्ष में एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किए गए ई-कचरे की मात्रा को प्रमाणित करते हैं और एक संगठन अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के लिए किसी अन्य कंपनी को अधिशेष मात्रा बेच सकता है।
  - पुनर्चक्रणकर्ता एक निश्चित मात्रा में कचरे के पुनर्चक्रण के लिए कंपनी के साथ सीधे अनुबंध कर सकते हैं और प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं, जिसे सीपीसीबी से प्राप्त किया जा सकता है।
- **ई-कचरा विनिमय सुविधाएं**
  - ईपीआर के लिए उत्पादकों को संग्रह और पुनर्चक्रण की सुविधा के लिए ई-कचरा विनिमय सुविधाएं स्थापित करने और सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के थोक उपभोक्ताओं को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपने की आवश्यकता होती है।
- **राज्य सरकारों की भूमिका**
  - राज्य सरकारों को ई-कचरे को हटाने और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए औद्योगिक स्थान निर्धारित करने , औद्योगिक कौशल विकास करने और ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण सुविधाओं में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।
- **इलेक्ट्रॉनिक सामान**
  - अधिसूचना में लैपटॉप, लैंडलाइन और मोबाइल फोन, कैमरा, रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और चिकित्सा उपकरण सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला निर्दिष्ट की गई है।
- **लक्ष्य उन्मुख**
  - एक मसौदा अधिसूचना के अनुसार, उपभोक्ता सामान कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60 प्रतिशत 2023 तक एकत्र किया जाए और उन्हें 2024 और 2025 में क्रमशः 70% और 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

चुनौतियां

- रीसाइकल की गई वास्तविक मात्रा को सत्यापित करना लगभग असंभव है, क्योंकि एक विशेष वर्ष में कितने इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचे गए, कितना ई-कचरा उत्पन्न हुआ और कितना पुनर्नवीनीकरण किया गया, जैसे डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (ई-वेस्ट) क्या है?

- इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट शब्द का उपयोग पुराने, जीवन के अंत या छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

- ई-कचरे को दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 21 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है :
  - सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण।
  - उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स।
- इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) कचरे की सबसे तेजी से बढ़ने वाली धारा है।

भारत में ई-कचरा उत्पादन

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत में वर्ष 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न हुए, जो 2017-18 में 7 लाख टन से अधिक है। इसके विपरीत, 2017-18 से ई-कचरा निपटान क्षमता 82 लाख टन से अधिक नहीं बढ़ी है।
- 2018 में पर्यावरण मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया था कि भारत में 95% ई-कचरे को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और स्क्रैप डीलर इसे अवैज्ञानिक रूप से एसिड में जलाकर या घोलकर इसका निपटान करते हैं।
- ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है कि भारत में लगभग 3 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ था, जो कि केंद्र के अनुमान से तीन गुना है।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम

- सरकार ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के आधार पर 2011 में ई-कचरा प्रबंधन पर पहला कानून पारित किया था।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई-कचरा प्रबंधन के लिए कुछ नियम बनाये गए हैं, जो 2016 से प्रभावी हुआ। ये नियम हर निर्माता पर लागू किये गए जैसे की निर्माता, उपभोक्ता, थोक उपभोक्ता, संग्रह केंद्र, डीलर, ई-रिटेलर आदि।
- 21 से अधिक उत्पादों को नियम के दायरे में शामिल किया गया था। इसमें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और अन्य पारा युक्त लैंप, साथ ही ऐसे अन्य उपकरण शामिल थे।
- पहली बार, नियमों ने उत्पादकों को लक्ष्य के साथ विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत लाया। उत्पादकों को ई-कचरे के संग्रह और उसके विनिमय के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
- विभिन्न उत्पादकों के पास एक अलग उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन (पीआरओ) हो सकता है और ई-कचरे का संग्रह सुनिश्चित कर सकता है, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से इसका निपटान भी कर सकता है।
- जमा वापसी योजना को एक अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में पेश किया गया है, जिसमें निर्माता बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री के समय जमा के रूप में एक अतिरिक्त राशि लेता है और इसे उपभोक्ता को ब्याज के साथ वापस करता है, जब जीवन के अंत में बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वापस कर दिए जाते हैं।
- विघटन और पुनर्चक्रण कार्यों में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका भी पेश की गई है।
- नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
- ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण के लिए मौजूदा और आगामी औद्योगिक इकाइयों को उचित स्थान के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

स्रोतः द हिन्दू

इथेनॉल सम्मिश्रण

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	तृतीय प्रश्नपत्र : पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

प्रसंग

भारत ने निर्धारित समय सीमा से पांच महीने पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

इथेनॉल क्या है?

- यह प्रमुख जैव ईंधन में से एक है, जो स्वाभाविक रूप से खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है।
- यह मुख्य रूप से गुड़ से उत्पादित होता है, जो चीनी उत्पादन का व्युत्पन्न है।
- इथेनॉल का उत्पादन उन फसलों से किया जा सकता है, जिनमें गन्ना, मक्का, गेहूं आदि जैसे स्टार्च की मात्रा अधिक होती है।

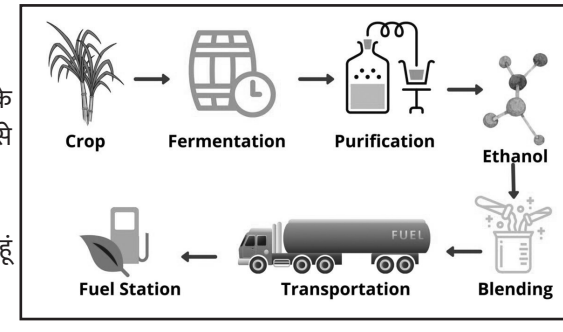

- विदित है कि यह सबसे महत्वपूर्ण जैव ईंधन में से एक है, जो प्राकृतिक रूप से खमीर किण्वन विधि या एथिलीन हाइड्रेशन जैसे पेट्रोकेमिकल विधियों के माध्यम से निर्मित होता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

- इथेनॉल एक जैव ईंधन है, जो कि कार्बनिक पदार्थों के प्रसंस्करण द्वारा उत्पादित ईंधन है। हम सामान्य तौर पर जिन ऑटो ईंधन का उपयोग करते हैं, वे मुख्य रूप से जीवाश्मीकरण की धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, यही वजह है कि उन्हें जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जाना जाता है।
- इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की एक प्रक्रिया है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के कारण, मोटर ईंधन के रूप में या एक योज्य के रूप में इथेनॉल का उपयोग तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।
- यह सम्मिश्रण तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने टर्मिनलों में किया जाता है। एक बार मिश्रित होने के बाद, इथेनॉल को पेट्रोल से अलग नहीं किया जा सकता है।

10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल करने के लाभ

- 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के परिणामस्वरूप 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
- भारत आठ साल की अवधि में 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने में सफल रहा है।
- इस अवधि के दौरान "देश के किसानों को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई।

राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति 2018 में संशोधन

- गत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति 2018 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की थी।
- इस मंजूरी के साथ ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को साल 2025-26 में ही प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जायेगा।
- इससे पहले साल 2018 में राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण वर्ष 2022 तक 10% और वर्ष 2030 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन नए संशोधन के अनुसार यह लक्ष्य बदल दिया गया है। वर्तमान में 2030 की जगह 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगा।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति

- वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जैव ईंधन पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी।
- इस नीति को भारत की घरेलू खपत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की मंशा से प्रस्तुत किया गया था।
- जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य 2030 तक जीवाश्म आधारित ईंधन के साथ जैव ईंधन के 20% सम्मिश्रण को प्राप्त करने के सांकेतिक लक्ष्य को आगे बढ़ाना था।
- नीति का उद्देश्य जैव ईंधन उत्पादन के लिए घरेलू फीडस्टॉक की पर्याप्त और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना, आयात में कमी, रोजगार सृजन और अपशिष्ट से धन सृजन करना है।
- यह नीति स्थिरता के एजेंडे को बढ़ावा देते हुए देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र के झुकाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।

नीति के तहत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां

- केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) इस सम्मिश्रण कार्यक्रम का समन्वय करने वाली एजेंसी है ।
- एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में भारत में पेट्रोल में केवल 1.5 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित किया गया था।
- 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित ' जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति ' में 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।
- 2014 से सरकार द्वारा किए गए उत्साहजनक प्रदर्शन और विभिन्न हस्तक्षेपों को देखते हुए, 20% लक्ष्य को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था।

विशेषताएँ

- यह इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार करता है। इसके अंतर्गत गन्ने के रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, मीठा शर्बत, स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू, मानव के लिए अनुपयुक्त अनाज के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है।
- यह नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के अनुमोदन से पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है ।
- उन्नत जैव ईंधन पर बल देने के साथ यह नीति अतिरिक्त कर प्रोत्साहन के माध्यम से 1जी जैव ईंधन की तुलना में उच्च खरीद मूल्य के अलावा 6 वर्षों में 2जी इथेनॉल बायो रिफाइनरियों के लिए 5000 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को दर्शाती है।

क्या है जैव ईंधन?

- जैव ईंधन नवीकरणीय बायोमास संसाधनों और अपशिष्ट पदार्थों जैसे प्लास्टिक, नगरपालिका ठोस, अपशिष्ट गैसों से प्राप्त उर्जा है।

- जैव-ईंधन तेल आयात पर निर्भरता और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होता है।

आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से जैव-ईंधन का महत्व

- भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल गन्ना और इसके उप-उत्पाद हैं, जो 'इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम' (Ethanol Blending Programme- EBP) के तहत 90% तेल उत्पादन के लिये उत्तरदायी है।
- यह कार्यक्रम आर्थिक दबाव झेल रहे चीनी उद्योग में तरलता बढ़ाने के साथ किसानों को आय का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराता है।
- भारतीय खाद्य निगम के तहत भंडारित अधिशेष चावल और मक्के को इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रयोग किये जाने से उन्हे एक वैकल्पिक बाजार मिल सकेगा।

पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से जैव-ईंधन की महत्ता

- वायु प्रदूषण को कम करना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसे में देश के विभिन्न अपशिष्ट बायोमास स्रोतों से 'संपीड़ित जैव-गैस' (Compressed Bio-Gas-CBG) उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु अक्तूबर 2018 में 'किफायती परिवहन के लिये टिकाऊ विकल्प' (Sustainable Alternative towards Affordable Transportation-SATAT) नामक योजना की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना के तहत प्रस्तावित संयंत्रों (विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश) में संपीड़ित जैव-गैस के उत्पादन के लिये कच्चे माल के रूप में फसलों के अवशेष जैसे- धान का पुआल और बायोमास का उपयोग किया जाएगा।
- विदित है कि सतत योजना न सिर्फ ग्रीनहॉउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में सहायक होती है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में फसलों के अवशेषों जैसे-पराली आदि को जलाने की घटनाओं को कम करने में सहायक है। यह दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।
- 'संपीड़ित जैव-गैस' संयंत्रों से निकलने वाले उत्पादों में से एक जैव खाद है, जिसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह ग्रामीण और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विकास करने के साथ किसानों के अनुपयोगी जैव-कचरे के सदुपयोग के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करने में सहायक होगा।

ऊर्जा सुरक्षा और जैव-ईंधनो के प्रोत्साहन से तेल आयात में कमी

- वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये देश में खनिज तेल और गैस की कुल मांग का क्रमशः 84% तथा 56% अन्य देशों से आयात करता है।
- खनिज तेल की कुछ मात्रा को जैव-ईंधन से प्रतिस्थापित कर आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
- 10 प्रतिशत सम्मिश्रण स्तर प्राप्त करने की वर्तमान नीति से किसानों को काफी लाभ हुआ है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा।

संबंधित पहल क्या हैं?

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम

- भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है।
- वर्ष 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी।
- हालांकि, उत्साहजनक प्रदर्शन को देखते हुए 2014 से सरकार के किए गए विभिन्न उपायों के कारण पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेने का रखा गया था।

जी-वन योजना

- इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मदद दिया जाना है-
- इसके प्रथम चरण (2018-19 से 2022-23) के तहत 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- द्वितीय चरण (2020-21 से 2023-24) के तहत बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को मदद की व्यवस्था की गई है।
- परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है. इसके लिए उसे वाणिज्यिक परियोजनाएं स्थापित करने और अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।

गोबर-धन योजना

- इसे 'गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन योजना' भी कहा जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रत्येक ज़िले का एक गांव चुना जायेगा और प्रत्येक ज़िले में एक क्लस्टर का निर्माण करते हुए लगभग 700 क्लस्टर्स स्थापित किए जाएँगे।
- इसके माध्यम से देश के किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक और संसाधन लाभ भी प्रदान किया जायेगा, जो एक स्वच्छ गाँव बनाने को भी समर्थन प्रदान करेगा।

- यह खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित करने और इस प्रकार गांवों को साफ रखने और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है।

जैव ईंधन के समक्ष चुनौतियाँ

- **दक्षता:** जीवाश्म ईंधन की तुलना में जैव ईंधन की दक्षता बहुत कम है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलने पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
- **जैव विविधता का नुकसान:** चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के परिणामस्वरूप जैव-विविधता का नुकसान हो सकता है।
- **स्थान की उपलब्धता:** जैव ईंधन के उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के मामले में उपयोग की जाने वाली फसलें ज्यादातर गैर-खाद्य फसलें होती हैं, इस प्रकार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है।
- **भोजन की कमी:** पहली पीढ़ी के जैव ईंधन खाद्य स्रोतों का उपयोग करते हैं और यदि जैव ईंधन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो भोजन की कमी का सामना करने का एक आसन्न खतरा है।
- **पानी का उपयोग:** जैव ईंधन फसलों की उचित सिंचाई के साथ-साथ ईंधन के निर्माण के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय और क्षेत्रीय जल संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि, तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के मामले में यह समस्या नहीं है।

निष्कर्ष

- फलत: भारत जैसे देशों में परिवहन में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने से कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी। जैव ईंधन नई नकदी फसलों के रूप में ग्रामीण और कृषि विकास में मदद कर सकता है।
- शहरों में उत्पन्न होने वाली बंजर भूमि और नगरपालिका कचरे का उपयोग सुनिश्चित करके स्थायी जैव ईंधन के उत्पादन के प्रयास किये जाने चाहिए।
- निष्कर्षत: एक उचित रूप से डिजाइन और कार्यान्वित जैव ईंधन समाधान भोजन और ऊर्जा दोनों प्रदान कर सकता है।

स्रोत: द हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडिया

रिमोट वोटिंग

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम पेपर: राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं	**द्वितीय पेपर:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, राजनीति, भारत में चुनाव

संदर्भ

हाल ही में, चुनाव आयोग ने सूचित किया कि वह जल्द ही प्रवासी मतदाताओं के मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी, जिसमें दूरस्थ मतदान की संभावनाओं की खोज करना भी शामिल है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

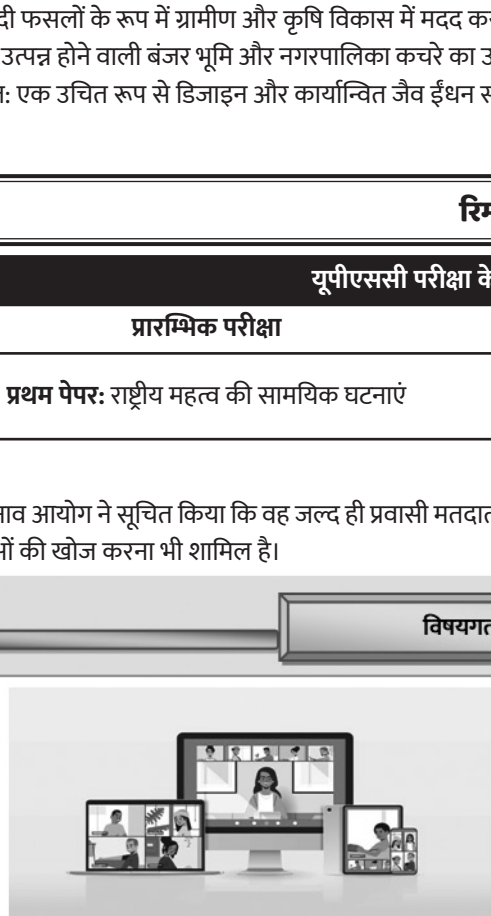

रिमोट वोटिंग सुविधा (आरवीएफ)

रिमोट वोटिंग सुविधा (आरवीएफ) मतदाता को देश के किसी भी मतदान केंद्र से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करता है और अधिवास मतदान केंद्र पर ही मतदान करने की बाध्यता का निवारण करता है।

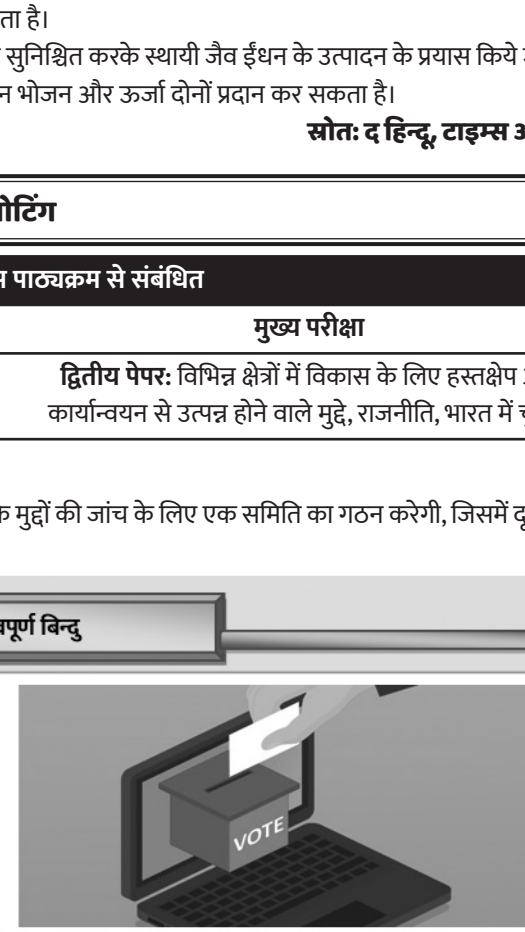

ई वोटिंग

ई वोटिंग प्रणाली मतदाताओं को एक एप्लिकेशन की सहायता से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से मतदान करने की अनुमति प्रदान करता है।

नोट: एक ब्लॉकचेन, सूचना का एक वितरित खाता और नई डेटा संरचना है, जो "पीयर-टू-पीयर" नेटवर्क (पी 2 पी नेटवर्क) आधारित सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी से संबद्ध होती है।

निर्णय और वर्तमान परिदृश्य

- पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों और मतदाताओं सहित सभी हितधारकों के परामर्श से निष्पादित की जाएगी।
- इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में मतदान की उदासीनता को दूर करने के लिए सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को 'छुट्टी लेने वाले लेकिन गैर-मतदान कर्मचारियों' का पता लगाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा।
- चुनाव आयोग विशेष मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी जागरूकता सत्र भी आयोजित करेगा।
- चुनाव आयोग ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में किसी भी मतदाता के लिए 2 किमी. के भीतर मतदान केंद्र स्थापित किए जाने के बावजूद कुछ महानगरों / शहर क्षेत्रों में कम मतदान चिंता का कारण है।
- विदित है कि चुनाव क्षेत्रों में लोगों को परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत कर्मचारियों द्वारा मतदान की सुविधा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक दिन का अवकाश दिया जाता है।

पृष्ठभूमि और आवश्यकता

- ज्ञातव्य है कि मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शिक्षा, रोजगार और अन्य उद्देश्यों के लिए पलायन करते हैं। कभी-कभी उनके लिए अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए वापस जाना संभव नहीं हो पाता है।
- गत वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में 'रिमोट वोटिंग सुविधा' को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- इसके कार्यान्वयन से मतदाता दूरस्थ स्थानों से मतदान कर सकेंगे और मतदान प्रतिशत में सुधार कर सकेंगे।
- यद्यपि, इस पद्धति की सफलता रिमोट वोटिंग के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित कई अन्य चरणों पर निर्भर करती है।

रिमोट वोटिंग सुविधा (आरवीएफ)

- इससे मतदाता को देश के किसी भी मतदान केंद्र से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- यह अधिवास मतदान केंद्र पर ही मतदान करने की बाध्यता को दूर करेगा।
- यह परियोजना आईआईटी-मद्रास द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके विकसित की जा रही है ।

ई वोटिंग

- यह प्रणाली मतदाताओं को एक एप्लिकेशन की सहायता से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से मतदान करने की अनुमति प्रदान करता है।
- विदित है कि यह मतदाताओं को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर जाए बिना दूर के शहरों से मतदान करने की अनुमति देगा।
- इस सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए मतदाताओं को पूर्व-निर्धारित समय के दौरान एक निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना होगा।
- ई-वोटिंग सिस्टम के लिए पहल तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग (TSEC) द्वारा की गई थी और इसे राज्य के आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग के समर्थन से प्रभावी किया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी) द्वारा तकनीकी विकास किया गया था।
- मोबाइल एप्लिकेशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वैध मतदाताओं का तीन चरण में प्रमाणीकरण करेगा।
- इसमें मतदाताओं के नामों का उनके आधार कार्ड से मिलान करना, व्यक्तियों का लाइव पता लगाना और उनकी छवि को चुनावी फोटो पहचान पत्र डेटाबेस के साथ 15 से 20 साल पुराने रिकॉर्ड के साथ मिलान करना शामिल है।
- इसके अलावा ब्लॉक-चेन (डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर) तकनीक का उपयोग डी-आइडेंटिफाइड और एन्क्रिप्टेड वोटों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है, ताकि उन्हें अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड के रूप में बनाए रखा जा सके।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

- एक ब्लॉकचेन, सूचना का एक वितरित खाता और नई डेटा संरचना है, जो "पीयर-टू-पीयर" नेटवर्क (पी 2 पी नेटवर्क) आधारित सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी से संबद्ध होती है।
- डेटा एक ही समय में कई कंप्यूटरों पर मौजूद होता है। यह लगातार विस्तार करता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण के तरीके से रिकॉर्डिंग या ब्लॉक के नए सेट इसमें जुड़ जाते हैं।
- यह तकनीक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी और किसी भी डेटा या डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण का समर्थन करती है।
- एक मानक ब्लॉकचैन पर होने वाले सभी लेन-देन को सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी के साथ सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाता है ।
- तकनीक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी और किसी भी डेटा या डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण का समर्थन करती है।

रिमोट वोटिंग सुविधा के संभावित कामकाज

- ज्ञातव्य है कि ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और एक एन्क्रिप्टेड डेटा तकनीक है। यह संभावित रूप से चुनाव छेड़छाड़/हस्तक्षेप को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, ब्लॉकचेन से चुनावों में अधिकतम मतदान कराया जा सकता है। संभावित कार्यान्वयन में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे-
- पहले चरण में, उपयोगकर्ता की मतदाता पहचान को एक बहुस्तरीय पहचान प्रणाली के माध्यम से सत्यापित और अधिकृत किया जाएगा। इस प्रणाली में वेब कैमरा और बायोमेट्रिक पहचान हो सकती है। इससे दोहराव पर रोक लगेगी।

- दूसरे चरण में, एक ब्लॉकचेन-सक्षम व्यक्तिगत ई-मतपत्र तैयार किया जाएगा। नागरिक इस पेपर का उपयोग अपना वोट डालने के लिए करेंगे।
- तीसरे चरण में, एक एन्क्रिप्टेड ब्लॉकचेन हैशटैग (#) बनाया जाएगा। इसके बाद यह हैशटैग चेन के सभी लोगों को भेजा जाएगा। जिससे चुनावी धोखाधड़ी पर रोक लगाया जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस, एस्टोनिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अतीत में अपने नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ब्लॉकचेन विधियों का उपयोग किया है।

रिमोट वोटिंग सुविधा (आरवीएफ) का महत्व

उच्च मतदाता मतदान

- 2019 के लोकसभा चुनावों में 542 निर्वाचन क्षेत्रों में 67.11 प्रतिशत मतदान हुआ।
- आरवीएफ आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकता है।
- विदित है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 45 करोड़ नागरिक प्रवासी हैं, जिनकी आबादी 37% है।
- इनमें से लगभग 10 मिलियन प्रवासी श्रमिक हैं, जो असंगठित क्षेत्र से संबद्ध हैं और सरकार के ई-श्रम पोर्टल के साथ पंजीकृत हैं।
- एक बड़ी प्रवासी आबादी केवल कुछ ही राज्यों में मौजूद है।
- फलत: यदि रिमोट वोटिंग परियोजना को प्रभावी किया जाता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

समावेशिता को प्रोत्साहन

- आरवीएफ ऐसे लोगों को जो किसी कारणवश अपने मतदान पंजीकरण स्थल से दूर रहते है, जैसे- छात्र, मरीज, प्रवासी मजदूर, आवश्यक सेवा प्रदाता आदि। उन्हें चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकेगा।

लचीलापन

- आरवीएफ मतदाताओं को अधिक लचीली व्यवस्था की सुविधा देता है। एक व्यक्ति केवल एक पंजीकृत मतदान केंद्र से ही नहीं, अपितु कई स्थानों से अपना वोट डाल सकता है।

प्रतिनिधि लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा

- आरवीएफ यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक योग्य मतदाता अपना वोट डालें। इस प्रकार, यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद करेगा।

संवैधानिक जनादेश के अनुकूल

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 ने 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया है, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सुविधा प्रदान की गई है।
- आरवीएफ चुनावों में सार्वभौमिक मतदान सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

रिमोट वोटिंग सुविधा के समक्ष चुनौतियां

साइबर खतरा

- चूंकि आरवीएफ ब्लॉकचेन पर आधारित है, इसलिए हैकर्स द्वारा इस पर हमला किया जा सकता है, जो अंतिम परिणाम को विकृत कर देगा।

प्रवासी मजदूरों का मानचित्रण

- प्रवासी मजदूरों की मैपिंग एक बड़ी कवायद है, जिसे प्रशासन को करना है।
- एक तरीका यह हो सकता है कि प्रखंड स्तर पर प्रवासियों की पहचान की जाए। वे डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कर सकते थे, क्योंकि कई राज्यों के पास प्रवासियों पर कोई डेटाबेस उपलब्ध नहीं है।
- चुनाव आयोग के पास सभी मतदाता सूची होती है और वह जानता है कि मतदाता किन निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- एक अन्य संभावित तरीका यह होगा कि लोग स्वयं रिमोट वोटिंग के विकल्प के लिए आवेदन करें।

गोपनीयता की चिंता

- इस प्रक्रिया में उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक्स और चेहरे के डेटा को सहेजना शामिल है। संबंधित अधिकारियों या हैकर्स द्वारा इसका कोई भी दुरुपयोग निजता के अधिकार को कमजोर करेगा।
- चूंकि आरवीएफ सुविधा एक अधिकृत अधिकारी के सामने ली जाएगी, इसलिए मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।

हितधारक का विश्वास

- कई राजनीतिक दल और उम्मीदवार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। आरवीएफ को विश्वसनीय बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

सुझाव

- सरकार को आरवीएफ को प्रभावी करने से पूर्व सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करना होगा। इसमें राजनीतिक दल और नागरिक समाज समूह शामिल हैं, जैसे- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आदि।
- पायलट चरण में पार्टियों और उम्मीदवारों को आरवीएफ की समय पर सूचनाएं मिलनी चाहिए। वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत किया जा सकता है।

- साथ ही, चुनाव आयोग को अधिक से अधिक जनता का विश्वास बनाने के लिए आरवीएफ हैकथॉन का आयोजन करना चाहिए।
- सार्वभौमिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, जब तक आरवीएफ विकसित नहीं हो जाता, तब तक डाक मतपत्र की प्रक्रिया को आसान करने और बढ़ाने की जरूरत है।
- भारत ने 2019 के लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) का इस्तेमाल किया। ईटीपीबीएस ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और विदेशों में भारतीय मिशनों में काम करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों को वोट डालने में मदद की।

निष्कर्ष

- दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, ईवीएम, वीवीपीएटी मशीन, सी-विजिल ऐप आदि की शुरूआत की गई है।
- आरवीएफ का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। साथ ही, इससे जुड़े चुनौतियों की पूर्व पहचान करके उसका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना होगा। यह रिमोट वोटिंग को एक सुरक्षित, विश्वसनीय और पारदर्शी प्रक्रिया बना देगा।

स्रोत: द हिन्दू, द मिंट

नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFM)

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्नपत्र :** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, सूचना प्रौद्योगिकी

प्रसंग

- हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के निर्देशन में राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (NDGFM) पर एक नया प्रारूप प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत-विशिष्ट डेटासेट का एक बड़ा भंडार बनाने और शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटा को साझा करने पर बल दिया दिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि एनडीजीएपी गैर-व्यक्तिगत डेटा तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगी। साथ ही, यह मसौदा नीति सरकारी डेटा साझा करने के लिए संस्थागत ढांचे में सुधार, डिजाइन द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा के सिद्धांतों को प्रोत्साहन देने पर केन्द्रित है।

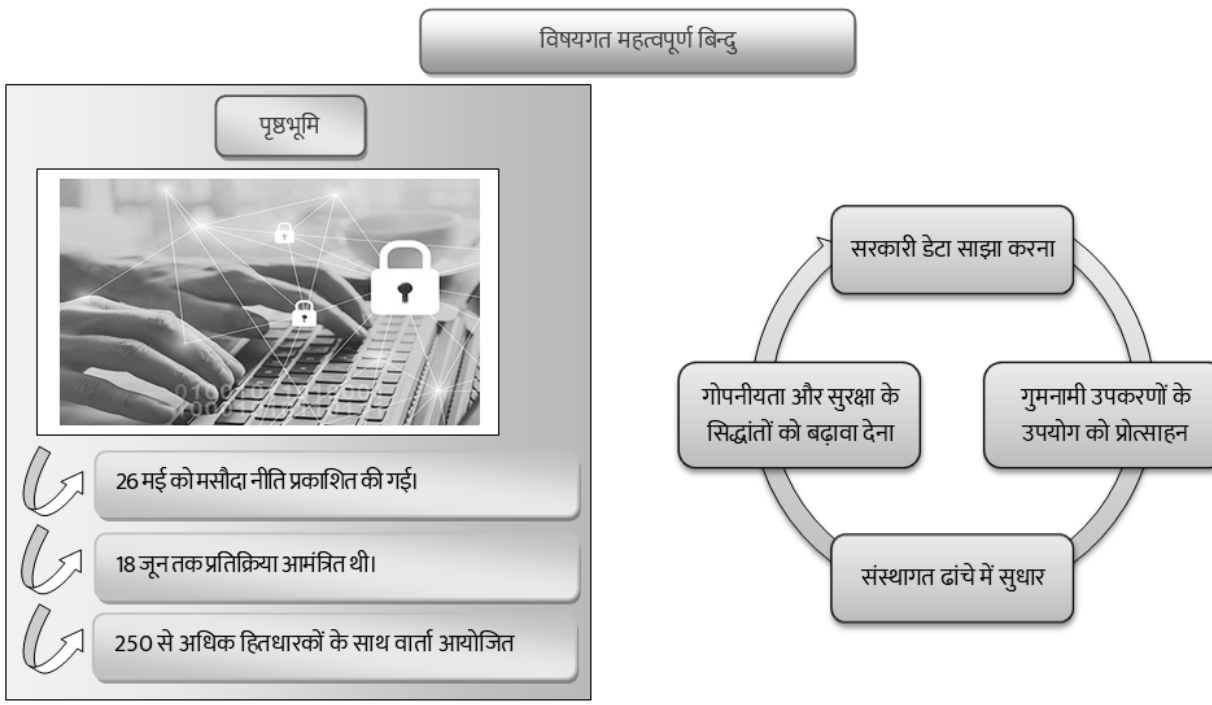

उद्देश्य

- एआई और डेटा आधारित अनुसंधान और एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करते हुए सरकार के डेटा संग्रह और प्रबंधन का मानकीकरण करना।

भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय (आईडीएमओ)

- प्रारूप में यूएस फेडरल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस की तर्ज पर इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (आईडीएमओ) स्थापित करने की योजना शामिल है।
- आईडीएमओ की स्थापना, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत नीति बनाने, प्रबंधन और समय-समय पर संशोधन करने के लिए की जाएगी।

प्रस्ताव

- ढांचे के हिस्से के रूप में एक मंच तैयार किये जाने की योजना है, जो अनुरोधों को संसाधित करेगा और भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप को गैर-व्यक्तिगत और/या अज्ञात डेटासेट तक पहुंच प्रदान करेगा।
- ज्ञातव्य है कि इससे पहले MeitY ने उसी पर एक मसौदा नीति प्रकाशित की थी, किन्तु डेटा साझा करने की योजना को लेकर मंत्रालय द्वारा व्यापक आलोचना का सामना करने के बाद इसे वापस ले लिया गया था।
- वर्तमान मसौदे में डेटा मुद्रीकरण के प्रावधान नहीं हैं।

डेटासेट कहां से प्राप्त किए जाएंगे?

- मसौदा नीति में वर्णित है कि प्रत्येक सरकारी मंत्रालय/विभाग/संगठन को उपलब्ध डेटासेट की पहचान और वर्गीकरण करना होगा।
- निजी कंपनियां भी डेटासेट बना सकती हैं और इंडिया डेटासेट प्रोग्राम में योगदान कर सकती हैं।
- आईडीएमओ इस संबंध में नियम और मानक निर्धारित करेगा।

भारत डेटासेट कार्यक्रम

- नीति के हिस्से के रूप में, भारत सरकार, भारत डेटासेट कार्यक्रम भी बनाएगी, जिसमें सरकारी संस्थाओं के गैर-व्यक्तिगत और अज्ञात डेटासेट शामिल होंगे।
- इस डाटा को भारतीय नागरिकों या भारत में रहने वालों को आधार मानते हुए एकत्र किया गया है।
- नीति में उल्लिखित है कि इस तरह के डेटा को साझा करने के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ढांचे के लिए कौन जिम्मेदार होगा?

- मसौदे में उल्लिखित है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के निर्देशन में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (आईडीएमओ) स्थापित किया जाएगा, जो नीति के तहत नियमों, मानकों और दिशा-निर्देशों को विकसित करके डेटा ढांचे के लिए उत्तरदायी होगा।
- साथ ही, यह प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप द्वारा उपयोग के लिए गैर-व्यक्तिगत और / अथवा अज्ञात डेटासेट तक पहुंच के अनुरोध को संसाधित करता है।
- विभागों और मंत्रालयों में एक नामित अधिकारी की अध्यक्षता में डेटा प्रबंधन इकाइयाँ (DMU) होंगी। यह अधिकारी नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आईडीएमओ के साथ मिलकर काम करेगा।
- राज्य सरकारों को भी राज्य-स्तरीय डेटा अधिकारियों को नामित / नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और आईडीएमओ इस संबंध में प्रशिक्षण सहित सभी सहायता प्रदान करेगा।

डेटा कैसे साझा किया जाएगा?

- आईडीएमओ गोपनीयता, सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करते हुए गैर-व्यक्तिगत डेटासेट साझा करने के लिए प्रोटोकॉल को अधिसूचित करेगा।
- आईडीएमओ भारतीय/भारत-आधारित अनुरोध करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता/विशेष रूप से डेटा प्रदान करने के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा।
- मसौदा नीति में कहा गया है कि प्रस्तावित नियामक संस्था डेटा की वास्तविकता और उसकी वैधता का भी आकलन करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY)

क्या है?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत एक पूर्ण मंत्रालय है। इसका गठन 2016 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय विभाग के बाद किया गया था।

Ministry of Electronics and Information Technology Government of India

सत्यमेव जयते

मिशन

- नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना, एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अंगीकार करना, जिसमें मानव संसाधन का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, दक्षता बढ़ाना शामिल है।
- डिजिटल सेवाएं और एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

- ई-सरकार: ई-सेवाओं के वितरण के लिए ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना।
- ई-उद्योग: इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्माण और आईटी-आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना।

- ई-नवाचार / आर एंड डी: आर एंड डी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन - आईसीटी एंड ई के उभरते क्षेत्रों में नवाचार / आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को सक्षम करना / आर एंड डी अनुवाद के लिए तंत्र की स्थापना।
- ई-लर्निंग: ई-कौशल और ज्ञान नेटवर्क के विकास के लिए सहायता प्रदान करना।
- ई-सुरक्षा: भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा।
- ई-समावेश: अधिक समावेशी विकास के लिए आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना।
- इंटरनेट गवर्नेंस: इंटरनेट गवर्नेंस के वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत की भूमिका को बढ़ाना।

डाटा तक पहुँच की प्रक्रिया

- मसौदा नीति के अनुसार, आईडीएमओ डेटासेट एक्सेस प्लेटफॉर्म का डिजाइन और रख-रखाव करेगा, जो डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- इंडिया डेटासेट प्रोग्राम के सभी डेटासेट को केवल इसके और किसी अन्य आईडीएमओ-निर्दिष्ट और अधिकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- नीति ने आईडीएमओ को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देकर डेटा अनुरोधों की सीमा का भी प्रस्ताव दिया है कि अनुरोध करने वाली संस्थाओं को उनके उपयोग के मामलों के लिए पूर्ण डेटाबेस या संयोजन तक पहुंच की अनुमति दी जाए अथवा नहीं।
- आईडीएमओ अंतर-सरकारी डेटा एक्सेस के लिए एक तंत्र भी विकसित करेगा। इसमें उल्लिखित है कि सभी सरकारी मंत्रालय/विभाग सरकार से सरकार तक डेटा एक्सेस के लिए स्पष्ट मेटाडेटा और डेटा डिक्शनरी के साथ विस्तृत, खोज योग्य डेटा इन्वेंटरी तैयार करेंगे।

डेटा शेयरिंग और स्टोरेज की व्यवस्था

- मसौदा नीति में कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक एकत्र / संग्रहीत / साझा और एक्सेस किए गए डेटा के लिए प्रकटीकरण मानदंड तैयार किए जाएंगे।
- इसके अलावा, आईडीएमओ सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र से इतर साझा किए गए डेटा के नैतिक और उचित उपयोग के सिद्धांतों को परिभाषित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
- आईडीएमओ नागरिकों के लिए डेटासेट का अनुरोध करने, शिकायतें दर्ज करने और समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए आईडीएमओ के तहत डेटा प्रबंधन इकाइयों (डीएमयू) की जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के तत्वावधान में 21 फरवरी, 2022 को "ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022" शीर्षक से एक नीति प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था।

नीति का उद्देश्य

- सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता को मौलिक रूप से परिवर्तित करना।
- सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को सार्वजनिक डेटा के लाइसेंस और बिक्री की अनुमति देने के लिए मसौदा डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति सम्बद्ध प्रस्ताव चर्चा में थी।

एनडीजीएफपी के तहत नए ढांचे का अनावरण

- इंटरनेट कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा नागरिकों से एकत्र किए गए गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण करने के लिए इसकी आलोचना की गई थी।
- आलोचना के तहत सरकार ने बाद में नीति को निरस्त कर दिया और इस वर्ष मई में नए नाम एनडीजीएफपी के तहत नए ढांचे का अनावरण किया।
- ज्ञातव्य है कि इस नए ढांचे में सरकार द्वारा एकत्र किए गए डेटा को खुले बाजार में बेचने की अनुमति देने संबंधी विवादास्पद खंड को समाप्त कर दिया गया है।

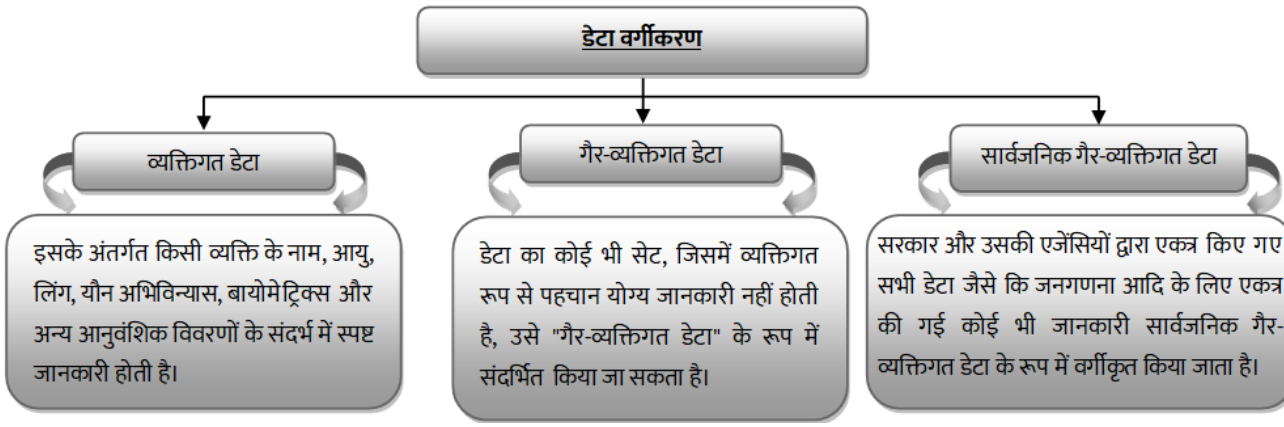

चुनौतियां

- नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी (एनडीजीएफपी) के अंतर्गत प्रस्तावित भारत-विशिष्ट डेटासेट का बड़ा भंडार बिग टेक के वाणिज्यिक संचालन के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
- डेटासेट का भंडार केवल भारतीय स्टार्टअप के लिए उपलब्ध होगा।
- इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या भारतीय स्टार्टअप का आशय भारत में पंजीकृत स्टार्टअप्स से है अथवा जो देश में परिचालन कर रहे हैं।
- गैर-व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा पर चिंता व्यक्त की जा रही है।
- वर्तमान में जब विश्व ब्लॉकचैन जैसे विकेन्द्रीकृत ढांचे की ओर बढ़ रही है, तब एनडीजीएफपी के डेटा केंद्रीकरण पहलू के संदर्भ में चिंता व्यक्त की जा रही है।
- अभी तक आईडीएमओ के संचालन को लेकर अस्पष्टता है।

निष्कर्ष

- वर्तमान समय में डेटा एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक संसाधन बन गया है।
- विदित है कि भारत में सरकार सबसे बड़ा डेटा भंडार है।
- फलतः एक नीतिगत ढांचा न केवल इसलिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में देश में गैर-व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं है, बल्कि सरकारी डेटा साझाकरण को प्रभावी बनाने के लिए भी है, जो आज कई बाधाओं का सामना कर रहा है।

भारत-आसियान सम्मेलन और इसके निहितार्थ

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्नपत्र :** द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत को शामिल और/या इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते

प्रसंग

- क्षेत्र के सर्वाधिक प्रभावशाली समूहों में से एक के रूप में विदित आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन) देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंटवार्ता की और दोनों पक्षों ने सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विमर्श किया।
- ज्ञातव्य है कि 10 राष्ट्रों के समूह आसियान के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है।

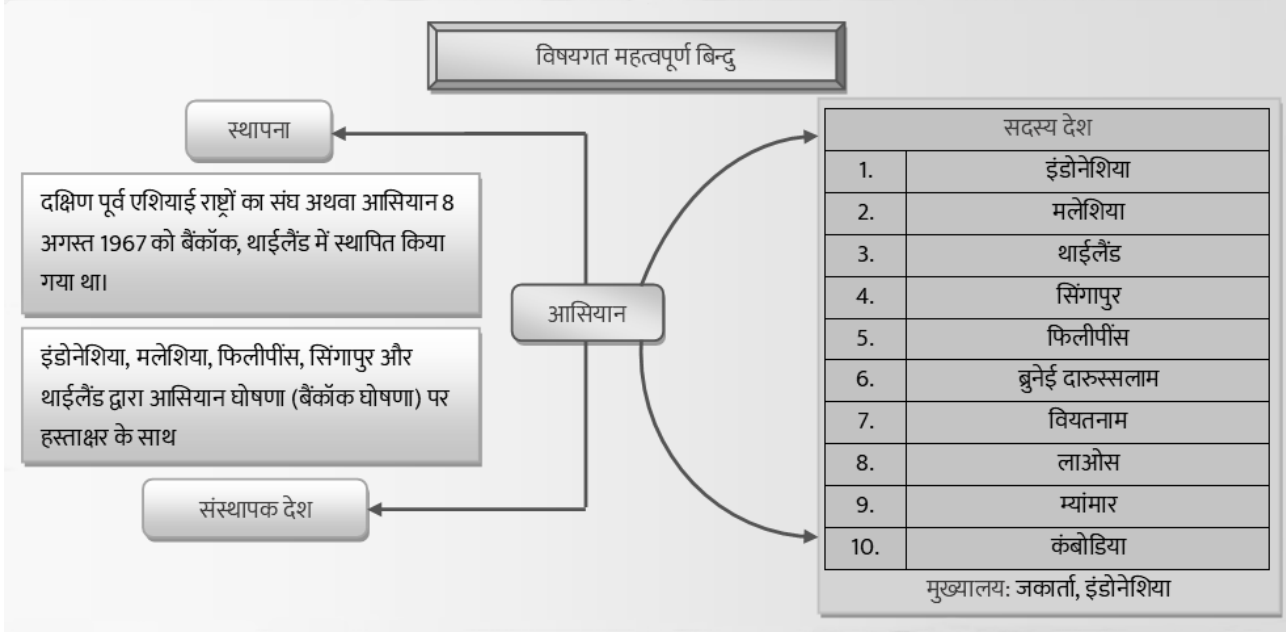

विमर्श के विभिन्न बिन्दु

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षागत मुद्दे

- भारत के विदेश मंत्रियों और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर यूक्रेन संकट के प्रभाव का आकलन करने और इसे संबोधित करने के विभिन्न तरीकों पर परिचर्चा की। साथ ही व्यापार, संपर्क, रक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर पारस्परिक सहमति व्यक्त की।

निम्नलिखित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

- यह पहली बार था, जब भारत ने 10 सदस्यीय समूह के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक की मेजबानी की।
- बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके सिंगापुर के समकक्ष विवियन बालकृष्णन ने की।
- ध्यातव्य है कि भारत-आसियान के मध्य पारस्परिक संबंधों के 30 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन सम्पन्न हुआ।

कोविड -19 और इसके दुष्प्रभाव

- यूरोप में ऐसे समय में हुए घटनाक्रम से महामारी से उबरने की प्रक्रिया जटिल हो गई है, जब कं
- भू-राजनीतिक बाधाओं के कारण यूक्रेन में विकास प्रभावित हुआ है। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा कीमतों में वृद्धि दृष्टिगत हो रही है। साथ ही, रसद और आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA)

- दोनों पक्षों ने मौजूदा भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करने की दिशा में काम करने और समझौते को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और सरल बनाने के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की शीघ्र समीक्षा शुरू करने हेतु सहमति व्यक्त की है।
- एआईटीआईजीए की समीक्षा के लिए स्कोपिंग पेपर के समर्थन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की गई, ताकि आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) संयुक्त समिति को एआईटीआईजीए समीक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सक्रिय किया जा सके।
- इन कदमों से आसियान-भारत व्यापार और आर्थिक साझेदारी की सर्वोत्तम क्षमता को हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसमें एआईएफटीए का प्रभावी कार्यान्वयन भी शामिल है।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता

क्या है?

- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (Asean-India Free Trade Area- AIFTA) आसियान और भारत के दस सदस्य राज्यों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है।

कब प्रभावी हुआ?

- आसियान और भारत ने 2009 में बैंकॉक, थाईलैंड में 7 वें आसियान आर्थिक मंत्रियों-भारत परामर्श में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 2010 में प्रभावी हुआ, जिसे कभी-कभी आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते के रूप में संदर्भित किया जाता है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना

- यह समझौता 2003 में बनाए गए भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते से उत्पन्न हुआ था।
- इस फ्रेमवर्क समझौते ने भविष्य के व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए भारत और आसियान के लिए आधार निर्धारित किया।
- समझौते में भौतिक वस्तुओं और उत्पादों में व्यापार शामिल है। यह सेवाओं में व्यापार पर लागू नहीं होता है।
- आसियान और भारत ने 2014 में एक अलग आसियान-भारत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- आसियान-भारत निवेश समझौते के साथ, तीन समझौते सामूहिक रूप से आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाते हैं।
- 2010 में समझौता लागू होने के बाद, इसने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक की स्थापना की, जिसमें करीब 1.8 बिलियन लोगों का संयुक्त बाजार शामिल था।
- समझौते के तहत आसियान और भारत ने 76.4 प्रतिशत वस्तुओं पर शुल्क को उत्तरोत्तर समाप्त करने और 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर शुल्क को उदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

पारस्परिक संपर्क के विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया

- विदेश मंत्रियों ने आसियान कनेक्टिविटी (एमपीएसी) 2025 पर मास्टर प्लान और इसकी "एक्ट ईस्ट" नीति के तहत भारत की कनेक्टिविटी पहल के बीच सामंजस्य बढ़ाने के विभिन्न मार्गों की खोज करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- शामिल पक्षों ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को तेजी से पूरा करने और संचालित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और इसे पूर्व की ओर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक विस्तारित करने के साथ-साथ अधिक सुदृढ़ वायु और समुद्री संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया।

अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता

- 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) सहित अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए दोनों पक्षों ने एक नियम-आधारित क्षेत्रीय ढांचा विकसित करने में आसियान केंद्रीयता का समर्थन करने के लिए सहमत हुए।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र

- वे इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) और भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (आईपीओआई) विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी, आपदा जोखिम प्रबंधन, खोज और बचाव कार्यों और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के विभिन क्षेत्रों की खोज करने पर सहमति व्यक्त की।

प्रस्तावित अनौपचारिक बैठक के साथ अन्य मुद्दों पर विमर्श

- नवंबर में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की एक प्रस्तावित अनौपचारिक बैठक और एक प्रस्तावित आसियान-भारत समुद्री अभ्यास के अतिरिक्त इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने में पारस्परिक सहयोग पर चर्चा हुई।
- विदित है कि भू-राजनीतिक चुनौतियों और अनिश्चितताओं को देखते हुए आसियान की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
- एओआईपी और आईपीओआई के बीच मजबूत अभिसरण क्षेत्र दोनों पक्षों के मध्य साझा दृष्टिकोण का प्रमाण है।

आसियान शिखर सम्मेलन

- आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान में सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है, जिसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार शामिल हैं।
- आसियान शिखर सम्मेलन अन्य आसियान सदस्य देशों के परामर्श से आसियान शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय में वार्षिक दो बार आयोजित किया जाता है।
- शिखर सम्मेलन की मेजबानी आसियान सदस्य देश द्वारा की जाती है।
- पहला आसियान शिखर सम्मेलन 23-24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था।

भारत-आसियान संबंध और महत्व

- आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के संबंधों की मजबूत नींव पर खड़ी है।
- आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक की हमारी व्यापक परिकल्पना का केन्द्र है।
- भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार, 1996 में संवाद भागीदार और 2002 में शिखर-स्तरीय भागीदार बना।
- पिछले दो दशकों में भारत-आसियान संबंधों के विकास के परिणामस्वरूप 2012 में साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था ।
- भारत ने 2014 में आसियान सदस्य देशों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की।
- भारत-आसियान के मध्य पारस्परिक संबंधों के 30 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन सम्पन्न हुआ।
- एक्ट-ईस्ट नीति में कनेक्टिविटी, वाणिज्य और संस्कृति के 3 सी पर अधिक से अधिक आसियान-भारत एकीकरण के लिए कार्रवाई के फोकस क्षेत्रों के रूप में बल दिया गया है।
- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत ने 2009 में माल में एफटीए और 2014 में आसियान के साथ सेवाओं और निवेश में एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए।
- भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) है, जिसके परिणामस्वरूप रियायती व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।
- भारत, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय (IMT) राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएं चला रहा है।
- भारत आसियान के साथ एक समुद्री परिवहन समझौता स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा है और भारत वियतनाम में हनोई में एक रेलवे लिंक की भी योजना बना रहा है।
- आसियान के साथ लोगों से लोगों की बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि आसियान के छात्रों को भारत में आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान-प्रदान आदि।
- भारत और अधिकांश आसियान देशों के बीच संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

भारत-आसियान संवाद तंत्र

- भारत और आसियान में अनेक संवाद तंत्र हैं, जिनका नियमित रूप से आयोजन किया जाता है, जिसमें एक शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं।

- विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अगस्त 2021 में आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और ईएएस विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने सितंबर 2021 में वर्चुअली आयोजित आसियान आर्थिक मंत्रियों + भारत परामर्श में भाग लिया, जहां मंत्रियों ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

निष्कर्ष

- आरसीईपी समझौते से भारत का अलग होना, आसियान देशों के साथ संबंधों की सीमाओं को दर्शाता है। इन देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों दोनों के लिए आवश्यक है।
- ज्ञातव्य है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के 10 सदस्य देशों ने 15 नवंबर 2020 को वियतनाम के हनोई में 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर को लेकर एक वर्चुअल समारोह का आयोजन किया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट

भारत में आकाशीय बिजली गिरने की समस्या

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे	**प्रथम और तृतीय प्रश्न पत्र :** महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, आपदा प्रबंधन

प्रसंग

- प्राकृतिक आपदाओं में आकाशीय बिजली सबसे बड़ी आपदा साबित हो रही है। विदित है कि भारत में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु के कारण यह एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का रूप धारण करती जा रही है।
- हाल ही में उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से कम से कम 70 लोगों की मृत्यु हो गई।
- भारत की दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच बिजली गिरने से क्रमशः बिहार (401 मौतें), उत्तर प्रदेश (238), मध्य प्रदेश (228), ओडिशा (156) और झारखंड (132) में सबसे अधिक मौतें हुई हैं।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

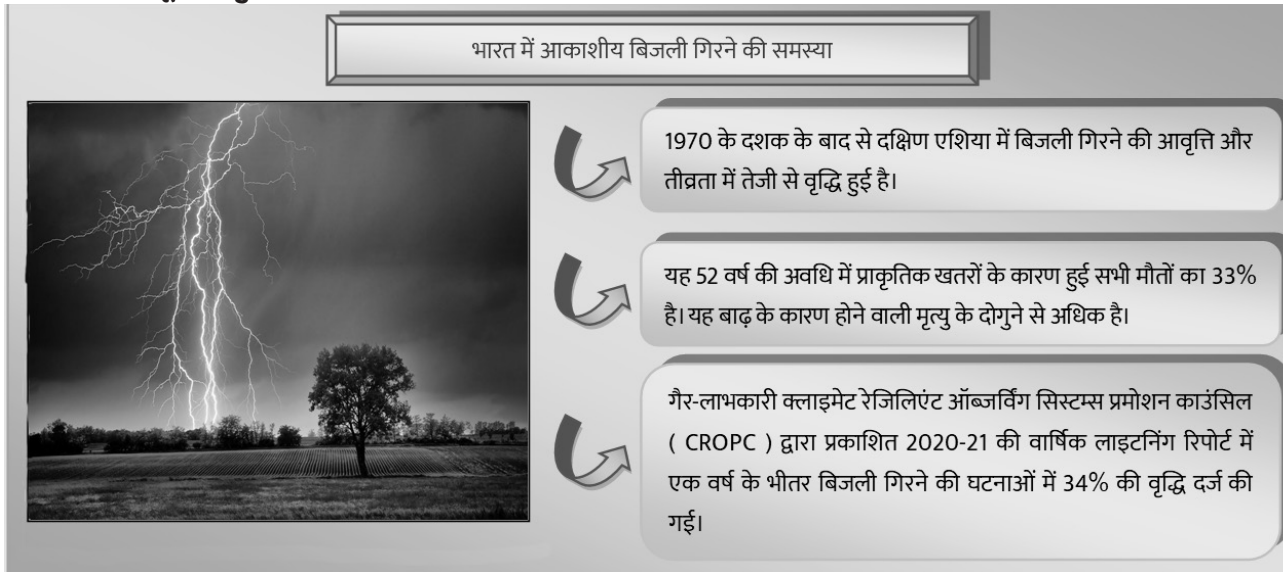

भारत में आकाशीय बिजली गिरने की समस्या

- 1970 के दशक के बाद से दक्षिण एशिया में बिजली गिरने की आवृत्ति और तीव्रता में तेजी से वृद्धि हुई है।
- यह 52 वर्ष की अवधि में प्राकृतिक खतरों के कारण हुई सभी मौतों का 33% है। यह बाढ़ के कारण होने वाली मृत्यु के दोगुने से अधिक है।
- गैर-लाभकारी क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) द्वारा प्रकाशित 2020-21 की वार्षिक लाइटनिंग रिपोर्ट में एक वर्ष के भीतर बिजली गिरने की घटनाओं में 34% की वृद्धि दर्ज की गई।

आकाशीय बिजली

- वैज्ञानिक दृष्टि से बिजली का तेजी से और व्यापक पैमाने पर वायुमंडल में निर्वहन होता है, जिनमें से कुछ को पृथ्वी की ओर निर्देशित किया जाता है।

- विदित है कि निर्वहन विशाल नमी वाले बादलों में उत्पन्न होते हैं, जो 10-12 किमी लंबे होते हैं। इन बादलों का आधार सामान्यतः पृथ्वी की सतह के 1-2 किमी. के भीतर होता है, जबकि शीर्ष 12-13 किमी. दूर होता है। इन बादलों के शीर्ष पर तापमान -35° से –45°C के मध्य होता है।

आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है?

- जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनती है, तो इन बादलों के अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा के होने से बादलों में धनावेश (पॉजिटिव चार्ज) ऊपर की ओर एवं ऋणावेश (निगेटिव चार्ज) नीचे की ओर होता है।
- बादलों में इन विपरीत आवेशों की आपसी क्रिया से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है।
- ध्यातव्य है कि धरती पर पहुंचने पर आकाशीय बिजली बेहतर कंडक्टर (संचालक) को तलाशती हैं, जिससे वह गुजर सके। इसके लिए धातु और पेड़ उपयुक्त होते हैं। बिजली सामान्यत: इन्हीं माध्यमों से पृथ्वी में जाने का मार्ग तलाशती है।
- टकराव इलेक्ट्रॉनों की मुक्ति का अनुगमन करते हैं और उत्प्रेरित करते हैं।
- यह एक प्रक्रिया है, जो बिजली की चिंगारी के उत्पादन के समान है।

आकाशीय बिजली को लेकर किये गये अध्ययन/ भारत में बिजली गिरने की बढ़ती संख्या

- हाल के वर्षों में, भारत में बिजली गिरने की आवृत्ति, तीव्रता और भौगोलिक प्रसार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- बर्कले विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक तापमान में हर एक डिग्री के बढ़ोतरी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 12 फीसद की वृद्धि हुई है।
- अनुमान है कि इस सदी के अंत तक आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में लगभग 50 फीसद की वृद्धि होगी।
- भारत में पहले की अपेक्षा बिजली गिरने की घटना में अचानक वृद्धि हुई है। भारत में बिजली गिरने की घटना और उत्पन्न स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है।

आकाशीय बिजली बनने की प्रक्रिया

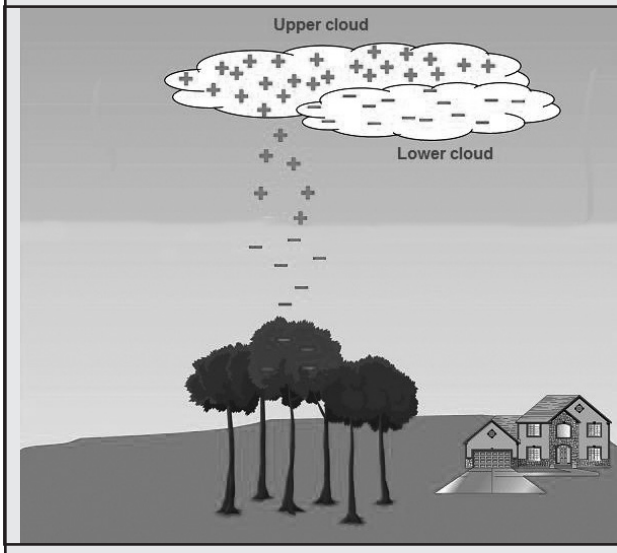

- जलवाष्प बादल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं और गिरते तापमान के कारण संघनित हो जाता है।
- जैसे ही वे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर जाते हैं, पानी की बूंदें छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं।
- विदित है कि वे तब तक बढ़ते रहते हैं, जब तक वे इतने भारी नहीं हो जाते कि वे पृथ्वी पर गिरना शुरू कर दें।
- यह एक ऐसी प्रणाली की ओर ले जाता है, जिसमें एक साथ छोटे बर्फ के क्रिस्टल ऊपर जा रहे हैं और बड़े क्रिस्टल नीचे आ रहे हैं।

2019-22: TOP 8 LIGHTNING-PRONE DISTRICTS

Over 2 lakh strikes each

Mayurbhanj	Korba
Keonjhar	Jaisalmer
Purulia	Medinipur West
Chandrapur	Prakasam

Source: Lightning Annual Report 2021-22

अस्थिर मानसून का अर्थ है उच्च बिजली जोखिम

- गर्म मौसम और आर्द्रता गरज के लिए आदर्श स्थिति का निर्माण करते हैं। फलतः जैसे ही जलवायु परिवर्तन अधिक गर्मी की लहरों का कारण बनता है, अधिक तूफान और बिजली की घटनाएँ होती हैं।
- दक्षिण एशिया में, पूर्व-मानसून तूफानों के दौरान बिजली की आवृत्ति तेजी से बढ़ती है, जो मानसून के दौरान उच्च रहती है और सितंबर में मानसून की वापसी पर फिर से बढ़ जाती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अधिक अनिश्चित हो गया है। बरसात के दिनों के बीच अक्सर तेज धूप वाले दिनों की अवधि होती है। इससे मानसून के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं।
- गत दो वर्षों में बिजली गिरने की संख्या के आकलन पर ज्ञात होता है कि मानसून में और उसके आस-पास ऐसी घटनाएँ सबसे अधिक होती हैं। दो वर्षों के बीच सबसे तेज वृद्धि अप्रैल और मई के महीनों में हुई थी।
- CROPC ने प्रत्येक राज्य में बिजली के हॉटस्पॉट की भी पहचान की है। साथ में, यह जानकारी स्थानीय नीति निर्माताओं को बिजली गिरने के लिए तैयार करने और घातक घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती है।
- भारत में स्थापित बाढ़ और चक्रवात से जुड़ी पूर्व चेतावनी प्रणाली हताहतों की संख्या को कम करने में मदद करती है, वहीं भारत में बिजली गिरने के जोखिम को कम करने की दिशा में कम प्रयास किया गया है।
- बिजली गिरने की बढ़ती संख्या किसानों, चरवाहों, मछुआरों, निर्माण और खेतिहर मजदूरों और बाहरी कारखानों जैसे ईंट भट्टों और निर्माण स्थलों में काम करने वालों को उच्च जोखिम में डालती है।
- कुछ राज्यों - आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, केरल, नागालैंड, बिहार ने व्यापक बिजली जोखिम प्रबंधन उपाय किए हैं।
- परिणामतः अप्रैल 2019 और मार्च 2021 के बीच आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु में 70% तक की कमी आई है।

कौन से क्षेत्र आकाशीय बिजली के प्रति संवेदनशील हैं?

- भारत मौसम विज्ञान विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) द्वारा बिजली गिरने की घटनाओं पर हाल ही में जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में लाइटनिंग एटलस प्रस्तुत किया गया है, जो जिला स्तर पर भेद्यता का मानचित्रण करता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बादल से ग्राउंड लाइटिंग स्ट्राइक की सूचना मिली है, इसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का स्थान है।
- उच्च बिजली जोखिम वाले अन्य राज्यों में बिहार, यूपी, कर्नाटक, झारखंड और तमिलनाडु शामिल हैं।

आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन

- आकाशीय बिजली की घटना सामान्य है, यद्यपि इसे सामान्यतः शहरी केंद्रों में अनुभव नहीं किया जाता है।
- भारत में हाल के वर्षों में एक करोड़ से अधिक बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
- CROPC और भारत मौसम विज्ञान विभाग के संयुक्त प्रयासों से गत कुछ वर्षों से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
- 2019-20 में करीब 1.4 करोड़ बिजली गिरने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो 2020-21 में बढ़कर 1.85 करोड़ हो गया।
- 2021-22 में देशभर में करीब 1.49 करोड़ घटनाएँ दर्ज की गईं। इस तरह की घटनाओं में विश्व स्तर पर कमी देखी गई, जो कोविड -19 महामारी के कारण हुई।
- वार्षिक बिजली रिपोर्ट में उल्लिखित है कि आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कमी का कारण भारतीय उपमहाद्वीप में एयरोसोल स्तर, प्रदूषण, पर्यावरण उन्नयन और अपेक्षाकृत स्थिर मौसम प्रणाली थी, जो कोविड -2019 महामारी से प्रेरित थी।

गत कुछ वर्षों से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं

वर्ष	रिकॉर्ड घटनाएं
2019-20	1.4 करोड़
2020-21	1.85 करोड़
2021-22	1.49 करोड़

बिजली गिरने के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है?

- भारत में बिजली को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लेकिन हाल के प्रयासों के परिणामस्वरूप एक पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना हुई है, जो पहले से ही कई लोगों की जान बचा रही है।
- बिजली गिरने से होने वाली 96 फीसदी से ज्यादा मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। फलतः अधिकांश शमन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को इन समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- भारत में बिजली संरक्षण उपकरण काफी अपरिष्कृत और कम लागत वाले हैं। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी तैनाती अभी बहुत कम है। इसकी संख्या में वृद्धि के प्रयास किए जा सकते हैं।
- राज्यों को हीट एक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए लाइटनिंग एक्शन प्लान तैयार करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- डिटेक्शन और अर्ली वार्निंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लाइटनिंग रिसर्च पर उत्कृष्टता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है।
- 2019 में CROPC ने अपना लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया अभियान 2019-2022 शुरू किया। यह एक नागरिक विज्ञान दृष्टिकोण का उपयोग करता है और भारत मौसम विज्ञान विभाग और वर्ल्ड विजन इंडिया के साथ साझेदारी में है और सरकार के कई एजेंसियों द्वारा समर्थित है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा बनाई गई एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
- अभियान अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, अप्रैल 2019 में शुरू होने के बाद से पहले ही बिजली से होने वाली मौतों को काफी कम कर चुका है। अब इसका लक्ष्य तीन वर्षों में मौतों और नुकसान को 80% तक कम करना है।
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा एक मोबाइल फोन ऐप दामिनी का शुभारंभ किया गया है। यह एक फोन के आस-पास कम से कम 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली का पूर्वानुमान प्रदान करता है और निवारक उपायों पर भी सलाह देता है।
- इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और स्वयंसेवकों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए संभावित बिजली गिरने की घटनाओं के जोखिमों की जानकारी का प्रसार किया जा रहा है।
- देशभर में अधिक मौसम-निगरानी स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक संस्थागत भवनों - स्कूलों, अस्पतालों, सामुदायिक केंद्रों आदि में बिजली सुरक्षा उपकरणों को स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बिजली की कार्ययोजना तैयार करने और पूर्व चेतावनी देने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें जनता के लिए क्या करें और क्या न करें की एक सूची भी है। सत्रह राज्य सरकारों ने बिजली गिरने को आपदा के रूप में अधिसूचित किया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सिंगल-यूज प्लास्टिक

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : पर्यावरणीय मुद्दे	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रसंग

- केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 'एकल उपयोग वाले प्लास्टिक' के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विदित है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गत वर्ष एक गजट अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी और अब उन वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया है, जिन पर अगले माह प्रतिबंध लगाया जाएगा।

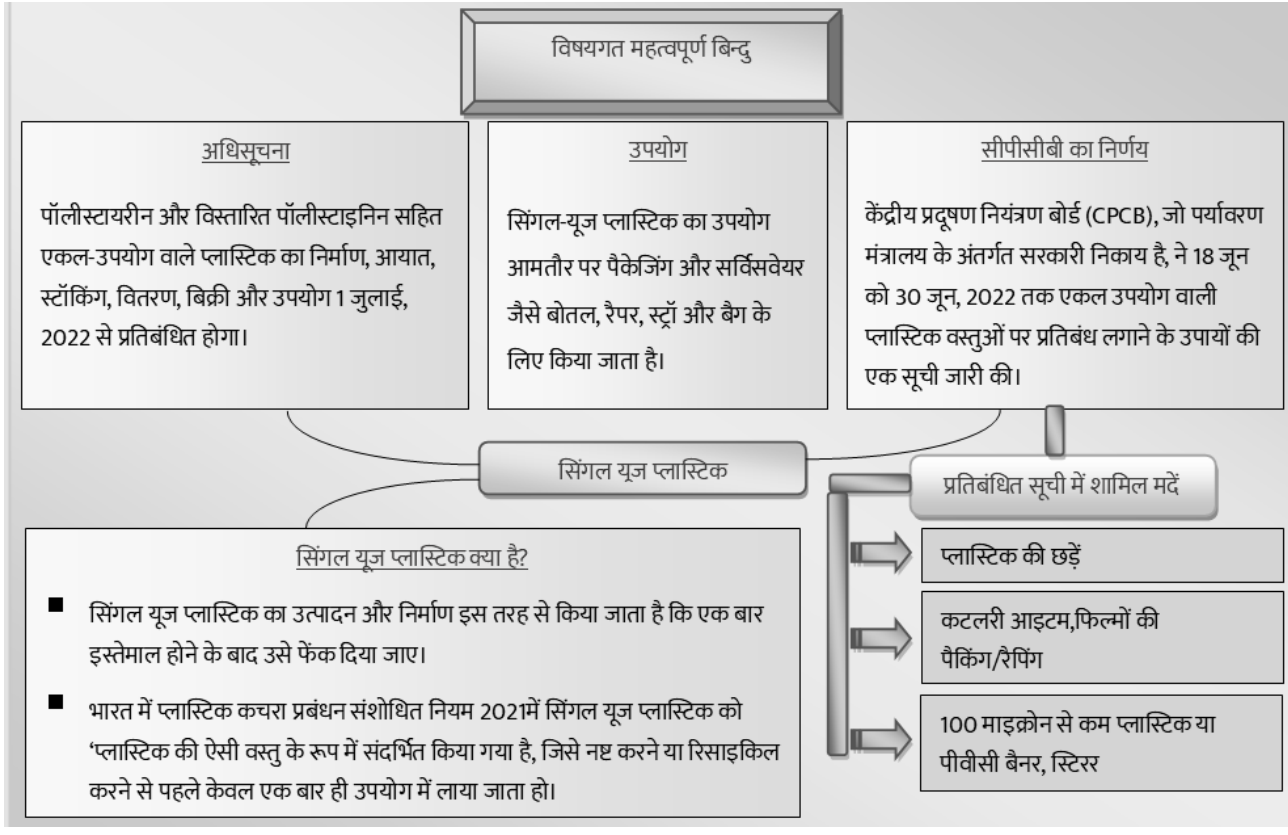

पृष्ठभूमि

- इससे पहले सीपीसीबी ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर चिन्हित वस्तुओं की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के निर्देश भेजे थे।
- इसके अतिरिक्त, एसपीसीबी और पीसीसी को प्रतिबंधित एसयूपी उत्पादन में लगे उद्योगों को वायु या जल अधिनियम के तहत जारी किए गए संचालन के लिए सहमति को संशोधित करने या निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- सीपीसीबी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक विक्रेताओं या उपयोगकर्ताओं का नेतृत्व करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों और प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माताओं को चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के निर्देश जारी किए।

सिंगल-यूज प्लास्टिक

- यह ऐसे प्लास्टिक की वस्तुओं को संदर्भित करता है, जिनका एक बार उपयोग किए जाने के बाद निपटाना आवश्यक होता है।
- सामान्य शब्दों में, सिंगल-यूज प्लास्टिक ऐसे सामान हैं, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन-आधारित रसायनों (पेट्रोकेमिकल्स) से बने होते हैं और उपयोग के तुरंत बाद जिनका निपटान करना होता है।
- सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन और निर्माण इस तरह से किया जाता है कि एक बार उपयोग होने के बाद उसे फेंक दिया जाए। इस परिभाषा के हिसाब से प्लास्टिक के तमाम उत्पाद इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें डिस्पोजेबल स्ट्रा से लेकर डिस्पोजेबल सीरिंज तक सभी शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों (शैम्पू, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन), पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, कचरा बैग, खाद्य पैकेजिंग आदि आते हैं।

- ऑस्ट्रेलियाई परोपकारी संगठनों में से एक मिंडेरू फाउंडेशन की 2021 की एक रिपोर्ट में उल्लिखित है कि विश्व भर में उत्पादित सभी प्लास्टिक का एक तिहाई एकल उपयोग प्लास्टिक है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित है।

सिंगल-यूज प्लास्टिक का प्रभाव

- रिपोर्ट के अनुसार, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक में 2019 में विश्व भर में 13 करोड़ मीट्रिक टन फेंके गए प्लास्टिक के बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से कुछ का दहन कर दिया जाता है अथवा भूमि में दफना दिया जाता है अथवा सीधे पर्यावरण में फेंक दिया जाता है।
- 2050 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 5-10% के लिए जिम्मेदार हो सकता है।
- वार्षिक 11.8 मिलियन मीट्रिक टन के घरेलू उत्पादन के साथ और 2.9 एमएमटी के आयात के साथ, भारत का एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे का शुद्ध उत्पादन 5.6 एमएमटी है और प्रति व्यक्ति उत्पादन 4 किलो है।

भारत में एसयूपी

- एक अनुमान के अनुसार, भारत ने वर्ष 2018 में 18.45 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया। इसी समयावधि में उत्पादित प्लास्टिक 17 मिलियन टन था।
- 2018 में प्रकाशित टेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति औसत खपत लगभग 11 किलोग्राम है। जिसके 2022 तक बढ़कर 20 किलोग्राम होने की संभावना है।
- कुल प्लास्टिक कचरे का केवल 60% ही पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है ।
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 ने उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को स्थानीय निकायों के परामर्श से एक कलेक्ट-बैक सिस्टम शुरू करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए अनिवार्य किया।
- इस प्रणाली को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के रूप में जाना जाता है। यद्यपि, भारत में संग्रह दक्षता मानकों के अनुरूप नहीं है।

प्रतिबंध का कार्यान्वयन

- केंद्र से सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा प्रतिबंध की निगरानी की जाएगी, जो नियमित रूप से केंद्र को रिपोर्ट करेंगे।
- राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधित वस्तुओं में लगे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं- उदाहरण के लिए, सभी पेट्रोकेमिकल उद्योग।
- स्थानीय अधिकारियों को इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया है कि उनके परिसर में एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं की बिक्री नहीं की जाएगी।
- यदि वे इन वस्तुओं का विक्रय करते पाए जाते हैं, तो मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।
- प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है - जो 5 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की अनुमति देता है।

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक संबंधी विदेशों में प्रावधान

- इस वर्ष की शुरुआत में, भारत सहित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 124 देशों ने एक समझौते को तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए भविष्य में हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के पूरे जीवन को संबोधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।
- बांग्लादेश 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया।
- न्यूज़ीलैंड जुलाई 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया।
- चीन ने 2020 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया।
- जुलाई 2019 तक 68 देशों में अलग-अलग डिग्री के प्रवर्तन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है।
- अमेरिका में आठ राज्यों ने 2014 में कैलिफोर्निया से शुरुआत करते हुए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- 2 जुलाई, 2021 को यूरोपीय संघ (ईयू) में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर निर्देश प्रभावी हुआ। निर्देश कुछ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध हैं; एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ, बैलून स्टिक और कॉटन बड्स को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बाजारों में विक्रय नहीं किया जा सकता है। विस्तारित पॉलीस्टाइनिन से बने कप, खाद्य और पेय कंटेनर और ऑक्सो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने सभी उत्पादों पर भी यही उपाय लागू होता है।

व्यक्त की जा रही चिंताएं

- कंपनियों ने कहा कि 1 जुलाई से प्रतिबंध लागू होने से आपूर्ति की कमी और आयातित पेपर स्ट्रॉ जैसी वैकल्पिक वस्तुओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ लागत में वृद्धि जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ।
- कोका-कोला इंडिया, पेप्सिको इंडिया, पार्ले एग्रो, डाबर, डियाजियो और रेडिको खेतान का प्रतिनिधित्व करने वाली एक्शन अलायंस फॉर रिसाइक्लिंग बेवरेज कार्टन (एएआरसी) ने कहा कि इस बदलाव से उद्योग को बिक्री में 3,000 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना है।

राष्ट्रव्यापी एसयूपी प्रतिबंध के संकल्प को लागू करने के लिए परामर्श एवं किये जा रहे उपाय

- वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशन में स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जिसमें एसयूपी का उन्मूलन शामिल है, फोकस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

- मिशन के तहत, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को कचरे के शत-प्रतिशत स्रोत पृथक्करण को अपनाने की आवश्यकता है और सूखे कचरे (प्लास्टिक कचरे सहित) को रीसाइक्लिंग और/या मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में प्रसंस्करण के लिए आगे के अंशों में विभाजित करने के लिए एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) तक पहुंच हो, जिससे प्लास्टिक और सूखे कचरे की मात्रा कम से कम होकर डंपसाइट्स या जलाशयों में समाप्त हो जाए।
- जबकि 2,591 शहरी स्थानीय निकायों (4,704 में से) ने पहले ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अधिसूचना के तौर पर एसयूपी प्रतिबंध की सूचना दी है। इसके तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि शेष 2,100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय 30 जून, 2022 तक इसे अधिसूचित करें।
- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एसयूपी 'हॉटस्पॉट' की पहचान करने और उन्हें खत्म करने की आवश्यकता होगी, जबकि समानांतर रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के समर्थन का लाभ उठाते हुए और विशेष प्रवर्तन दस्तों का गठन, औचक निरीक्षण करने और एसयूपी प्रतिबंधों को लागू करने के लिए चूककर्ताओं पर भारी जुर्माना और दंड लगाने की आवश्यकता होगी।
- मंत्रालय ने सितंबर 2021 में 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था, जो पहले के 50 माइक्रोन से सीमा का विस्तार करता था।
- दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- यह प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि निर्माताओं को ऐसे मोटे पॉलीथिन बैगों के उपाय को अपनाने का समय मिल सके, जिन्हें रिसाइकिल करना आसान हो।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिये दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर दिया है।
- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सम्बंधी दिशा-निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पाबंदियों के साथ संबद्ध किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम उपयोगी होता है और उसका कचरा बहुत जमा होता है। यह कदम 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी हो जायेगा।
- देश में प्लास्टिक के कचरे से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- दिशा-निर्देशों में एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है, जिससे प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, प्लास्टिक के नये विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापार प्रतिष्ठान टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत इकट्ठा किये जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की री-साइकिल को न्यूनतम स्तर पर रखने का उपाय किया गया है। इसके साथ ही री-साइकिल किये गये प्लास्टिक को बार-बार उपयोग में लाया जायेगा। इस तरह प्लास्टिक की खपत को और कम किया जायेगा तथा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को री-साइकिल करने को प्रोत्साहन मिलेगा।

निर्णय के निहितार्थ

इससे प्लास्टिक के नये विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये रोडमैप उपलब्ध होगा।

निष्कर्ष

- कपास, खादी बैग और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विदित है कि ये आर्थिक रूप से किफायती और पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य विकल्प हैं, जो आवश्यक संसाधनों पर बोझ नहीं डालेंगे, उनकी कीमतें भी समय के साथ कम होंगी और मांग में भी वृद्धि होगी।
- साथ ही, स्थायी रूप से व्यवहार्य विकल्पों की खोज के लिए और अनुसंधान एवं विकास पर बल देने के साथ इसके लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अग्निपथ योजना

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप, रक्षा

प्रसंग

- हाल ही में, सरकार ने नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के तहत आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीर के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत नौकरी रिक्तियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- ज्ञातव्य है कि अग्निपथ योजना के विरुद्ध चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच सेवा प्रमुखों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से इस वर्ष 17.5 से 23 वर्ष की आयु के बीच के 46,000 युवाओं को अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भर्ती करने की योजना है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को 'अग्निवर' नाम से संबोधित किया जाएगा।

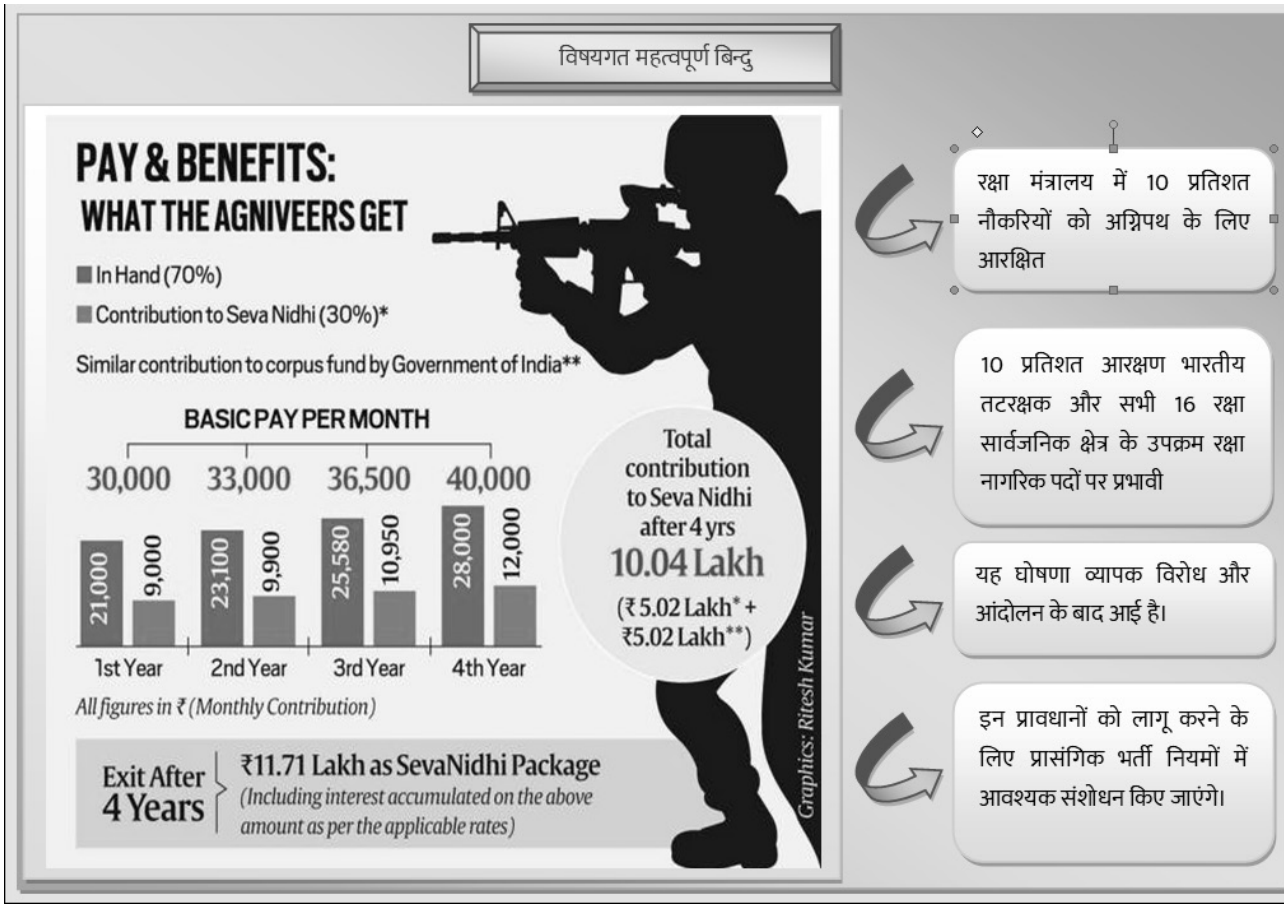

अग्निपथ योजना क्या है?

- सरकार ने तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है।
- नई भर्ती सुधार योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर के नाम से संबोधित किया जाएगा।
- 'अग्निपथ भर्ती योजना' के तहत युवा चार साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे।
- नई योजना के तहत हर साल लगभग 45,000-50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिनमें से अधिकांश 75% की भर्ती केवल 4 वर्ष के लिए की जाएगी।
- केवल 25 फीसदी सैनिकों को चार वर्ष बाद भी अवसर मिलेगा। यद्यपि, यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हों।
- कुल वार्षिक भर्तियों में से शेष 25% स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक जारी रखने में सक्षम होंगे।
- कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे, जिन्होंने देश की सेवा की है।
- योजना के तहत सशस्त्र बलों के लिए युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- चार साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेhवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जो 11.71 लाख रुपए होगा।
- योजना के तहत इस वर्ष 46 हजार अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।

आयु सीमा में संशोधन

- केंद्र ने अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है।
- वर्ष 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती के लिए आयु में छूट सिर्फ एक बार दी जाएगी।
- विदित है कि पहले इस योजना के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई थी।

- योजना की घोषणा के दो दिनों के भीतर अपने पहले संशोधन में केंद्र ने कहा, 'इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि गत दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं था, सरकार ने यह निर्णय किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में एकमुश्त छूट दी जाएगी।'

पात्रता मापदंड

- आवेदन करने की आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित।
- 2022-23 के लिए ऊपरी आयु सीमा में 21 वर्ष से 23 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यद्यपि, यह एकमुश्त छूट होगा।

- चिकित्सा और शारीरिक स्वास्थ्य मानदंडों को मौजूदा नियमों के अनुसार पूरा किया जाएगा।
- भर्ती प्रक्रिया 'अखिल भारतीय सभी वर्ग' के आधार पर की जाएगी।

चयन के बाद की प्रक्रिया

- एक बार चयनित होने के बाद, उम्मीदवारों को छह महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर साढ़े तीन वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा।
- इस अवधि के दौरान, उन्हें अतिरिक्त लाभ के साथ 30,000 रुपये का प्रारंभिक वेतन मिलेगा, जो चार वर्ष की सेवा के अंत तक 40,000 रुपये हो जाएगा।
- इस अवधि के दौरान, उनके वेतन का 30 प्रतिशत एक सेवा निधि कार्यक्रम के तहत अलग रखा जाएगा और सरकार हर महीने एक समान राशि का योगदान करेगी, जिस पर ब्याज का भी प्रावधान है।
- चार साल की अवधि के अंत में, प्रत्येक सैनिक को एकमुश्त राशि के रूप में 11.71 लाख रुपये मिलेंगे, जो कर मुक्त होगा।
- उन्हें चार साल के लिए 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा।
- मृत्यु के मामले में भुगतान नहीं किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
- यद्यपि, चार वर्ष के बाद, बैच के केवल 25 प्रतिशत को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।
- जिन्हें पुनः चयनित किया जाएगा, उनके लिए सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए प्रारंभिक चार वर्ष की अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया और महत्ता

- योजना के तहत 90 दिनों के भीतर भर्ती शुरू हो जाएगी, जो 'अखिल भारतीय सभी वर्ग' के आधार पर की जाएगी।
- यह सेना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ किसी भी जाति, क्षेत्र, वर्ग या धार्मिक पृष्ठभूमि से किसी को भी मौजूदा रेजिमेंट का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए समाप्त कर दिया जाएगा।

इस योजना से सशस्त्र बलों को कैसे लाभ होगा?

- यह देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इसके परिणामस्वरूप देश के लगभग 13 लाख सशस्त्र बलों के लिए स्थायी बल का स्तर काफी कम हो जाएगा। फलतः रक्षा पेंशन खर्च में काफी कमी आएगी, जो कई वर्षों से सरकारों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है।
- यह तीनों सेनाओं के युवा प्रोफाइल तैयार करने में सहायता करेगा।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में सेना में औसत आयु 32 वर्ष है, किन्तु इस योजना के कार्यान्वयन से यह छह से सात वर्षों में घटकर 26 वर्ष हो जाएगी।
- यह युवाओं को नई तकनीक सीखने हेतु उत्प्रेरित करेगा। इसके अलावा, स्थायी रूप से भर्ती किए जाने वाले 25% अग्निवीरों के लिए योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया से स्थायी सैनिकों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।
- इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और चार साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- इससे अर्थव्यवस्था के लिए उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो उत्पादकता लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगी।
- सरकार चार साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में सहायता करेगी। उन्हें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जाएगा।

अग्निपथ योजना को लेकर व्यक्त की जा रही आपत्ति

- इस योजना को लेकर इस आधार पर आपति व्यक्त की जा रही है कि यह स्थायी संवर्ग और पेंशन लाभों को समाप्त करने का प्रावधान करती है, जो युवाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए हतोत्साहित कर सकती है।
- नई सशस्त्र सेना भर्ती योजना के तहत युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए सेना में लिया जाएगा, जिसके बाद केवल 25% ही भर्ती होंगे। फलतः इससे उनके रोजगार अधिकारों का हनन होगा।

- कई दिग्गजों ने सशस्त्र बलों को अल्पकालिक बल में बदलने के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो एक सैनिक की सेना के प्रति वफादारी में बाधा उत्पन्न करेगा।

निष्कर्ष

- ज्ञातव्य है कि कोई भी सुधार अचूक नहीं होता है और न ही जनमत के समर्थन के बिना कारगर सिद्ध हो सकता है। फलतः व्यक्त किए जा रहे सार्थक प्रश्नों का निवारण किया जाना चाहिए।
- सरकार को चार वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के पुनर्वास हेतु पहल करने की आवश्यकता है। इस दिशा में अग्निवीर के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना एक प्रशंसनीय कदम है।
- समग्र दृष्टि से इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यह योजना उन युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करेगी, जो राष्ट्र की सेवा करने के इच्छुक हैं। साथ ही, इसका सशस्त्र बलों के मानव संसाधन प्रबंधन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स

आदिवासियों की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोकथाम लगाने वाले कानूनों को निरस्त करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका

झारखंड में आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने वाले कानून छोटा नागपुर टेनेन्सी (सीएनटी) एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेन्सी (सप्लीमेंट्री प्रोवीजन) एक्ट 1949 (एसपीटी) की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता

- झारखंड रांची के निवासी श्याम प्रसाद सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों कानूनों को निरस्त करने की मांग की है।

क्यों मांग की जा रही है?

- दाखिल याचिका में कहा गया है कि सीएनटी कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों की जमीन के संरक्षण के लिए 1908 में लाया गया था और इसी तरह एसपीटी कानून 1949 में लाया गया था।
- विदित है कि यह दोनों कानून आदिवासियों की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाता है।
- जमीन आदिवासी या उसी उपजाति के कृषक के अलावा किसी दूसरे को नहीं बेची जा सकती और न ही कोई और उस जमीन को व्यवसायिक उपयोग के लिए खरीद सकता है। यहां तक कि उसी उपजाति के कृषक को भी जमीन जिलाधिकारी की अनुमति से ही बेची जा सकती है।

याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित कानून में व्याप्त कमियाँ

- अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, भूमि को छह वर्ष से अधिक के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता और उसके उपयोग पर भी नियंत्रण है।
- भूमि का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता।
- इन दोनों कानूनों में लगी रोक के कारण आदिवासी न तो अपनी जमीन को गिरवी रख सकते हैं और न ही बैंक से कर्ज ले सकते हैं।
- ये दोनों कानून न केवल गैर-आदिवासियों के ही खिलाफ नहीं हैं, बल्कि यह आदिवासियों के लिए भी लाभप्रद नहीं हैं।
- दोनों कानून पुराने हो चुके हैं और उनमें बदलाव करने की आवश्यकता है।

आवश्यकता

- वर्तमान समय और आधुनिक आवश्यकताओं तथा झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या को देखते हुए कानून में संशोधन करने और कुछ क्षेत्रों से इस कानून को वापस लिये जाने की जरूरत है।
- इन कानूनों के कारण नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी न तो उस जमीन का कृषि क्षेत्र में उपयोग कर पाते हैं और न ही वे उस जमीन को बाजार कीमत पर बेच सकते हैं। ऐसे में झारखंड में आदिवासियों की जमीन गैर-कानूनी रूप से छपरबंदी के जरिये स्थानांतरित हो रही है और संथाल परगना में साधारण करार जैसे भुक्तबंद के जरिये स्थानांतरित हो रही है। इसमें जमीन मालिक को जमीन की कीमत बाजार कीमत से कम मिलती है और वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति से पिछड़ जाते हैं।
- याचिका में कहा गया है कि छोटा नागपुर और संथाल क्षेत्र संवैधानिक प्रविधानों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। इसमें किसी भी तरह का बदलाव संसद के जरिये होता है, जिसे राष्ट्रपति करते हैं।
- छोटा नागपुर और संथाल क्षेत्र खनिज से भरपूर है और इसके कारण वहां औद्योगीकरण की अपार संभावनाएं है, किन्तु जमीन स्थानांतरण पर रोक के कारण बहुत से निवेशकों को इन दोनों कानून की जटिलताओं के कारण निवेश में बाधा उत्पन्न होती है।

सीएनटी और एसपीटी अधिनियम

- छोटा नागपुर टेनेन्सी (सीएनटी) अधिनियम 1908 में अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम उत्तर और दक्षिण छोटानागपुर और पलामू मंडलों तक विस्तृत हुआ।
- वहीं एसएनटी अधिनियम 1949 में पारित किया गया था, जो पूर्वी झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ तक फैला हुआ था।
- इन अधिनियमों ने आदिवासियों को विशेष सुरक्षा और भूमि अधिकार प्रदान किए और संबंधित ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने या भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) अध्यादेश और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 (संशोधन) अध्यादेश

- मई 2016 में सरकार ने दो अध्यादेश पेश किए- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) अध्यादेश और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 (संशोधन) अध्यादेश, जिसने आदिवासी भूमि के व्यावसायिक उपयोग को सक्षम बनाया और इसे आसानी से हस्तांतरणीय बना दिया।

- इस अधिनियम ने सरकार को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए आदिवासियों से कृषि भूमि खरीदने का अधिकार दिया।
- यद्यपि जून 2017 में झारखंड विधानसभा द्वारा अध्यादेश पारित किए गए थे, लेकिन झामुमो, कांग्रेस, वामपंथी और राज्य के निवासियों जैसे राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बाद झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। बाद में सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया।

सोशल मीडिया नियमों में संशोधन का प्रस्ताव

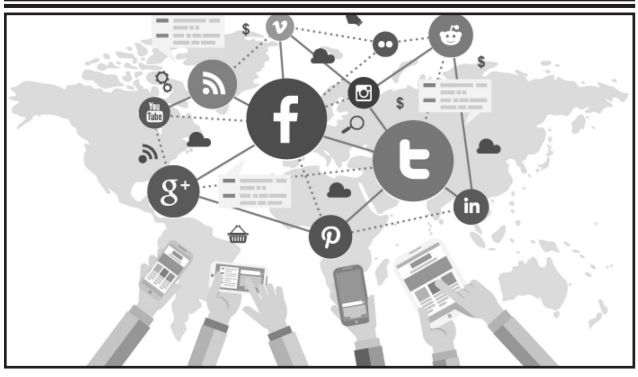

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय समितियों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
- ज्ञातव्य है कि सरकार सोशल मीडिया मंचों के नियमों में संशोधन के साथ शिकायत निपटान अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ दायर आवेदनों पर विचार के लिए अपीलीय समिति के गठन की योजना बना रही है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन के लिए जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटान करना होगा।
- यह निर्णय मध्यवर्तियों या संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा।
- ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों ने 'समुदायिक दिशा-निर्देशों' के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए पिछले कुछ समय में कई चर्चित हस्तियों समेत कई उपयोगकर्ताओं के खाते बंद किए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से यह कदम काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
- सरकार सोशल मीडिया मंचों के नियमों में संशोधन के साथ शिकायत निपटान अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ दायर आवेदनों पर विचार के लिए अपीलीय समिति के गठन की योजना बना रही है।
- ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों ने 'समुदायिक दिशा-निर्देशों' के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए पिछले कुछ समय में कुछ चर्चित हस्तियों समेत कई उपयोगकर्ताओं के खातों को बंद किया है। ऐसे में सरकार की तरफ से यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- इन्फार्मेशन टेक्नालजी (इंटरमीडियारी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम बनाए गए थे। इसके अंतर्गत 50 लाख से ज्यादा यूजर वाली कंपनियों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई थी।
- 26 मई, 2021 को प्रभावी हुए इन नियमों में कंटेंट पर नियंत्रण के लिए कई प्रावधान हैं। यद्यपि कुछ शिकायतकर्ता यूजर कंपनी के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे।
- ऐसे में सरकार शिकायतकर्ता को अपील के लिए एक और विकल्प देना चाहती है।

प्रस्ताव

- समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटान करना होगा। यह निर्णय मध्यवर्तियों या संबंधित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा।
- केंद्र सरकार एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। इस समिति में एक चेयरपर्सन और अन्य सदस्य होंगे। केंद्र सरकार समिति का आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के जरिये गठन कर सकती है।
- नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ संबंधित उपयोगकर्ता अपनी अपील दायर कर सकते है।
- जारी अधिसूचना के मसौदे के अनुसार, "अपीलीय समिति उपयोगकर्ताओं की अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर अंतिम रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी।
- समिति की तरफ से पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यवर्तियों द्वारा किया जाएगा।
- इसके अलावा समिति एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगी। साथ ही, शिकायतकर्ता के पास किसी भी समय शिकायत को लेकर न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार होगा।
- मध्यस्तों को 24 घंटे के भीतर सूचना या लिंक हटाने और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटान करने के मामले में खाते के निलंबन, हटाने या अवरुद्ध करने जैसी किसी भी शिकायत को स्वीकार करना होगा।
- वहीं मानहानि, अश्लील, निजता का हनन, फर्जी या गलत जानकारी/संचार/सामग्री को हटाने की शिकायत दर्ज किये जाने के 72 घंटों के भीतर निवारण करना होगा।
- मसौदा अधिसूचना में कहा गया कि संबंधित मध्यस्थ को गोपनीयता और पारदर्शिता की अपेक्षा के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को सभी उचित उपाय उठाने होंगे।
- इसके अलावा, सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के संविधान के तहत देश के नागरिकों के सभी अधिकारों का सम्मान करना होगा।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से जुड़े नियमों में परिवर्तन

- रक्षा मंत्रालय (MoD) की एक अधिसूचना के अनुसार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से जुड़े नियमों में परिवर्तन किए गए हैं।

सेना, नौसेना और वायु सेना के नियमों में संशोधन की अधिसूचना

- विदित है कि रक्षा मंत्रालय ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के नियमों में संशोधन करते हुए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं।

संशोधन के मुख्य बिन्दु

- एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत, अधिसूचना के अनुसार, लोकहित में लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या इसके बराबर के रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर या फिर सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया जा सकता है। यद्यपि वह अधिकारी नियुक्ति के समय 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
- सरकार ने सेना के नियम 1954; नौसेना (अनुशासन और विविध प्रावधान) विनियम, 1965; नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनियम, 1963 तथा वायु सेना विनियम, 1964 में संशोधन किया है। इसके तहत केंद्र सरकार यदि आवश्यक हो, जनहित में ऐसा करने के लिए एक अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर सकती है, जो लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल के रूप में सेवारत है अथवा जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल या एक अधिकारी जो इन रैंकों से सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन अपनी नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।
- इसमें उल्लिखित है कि सरकार सीडीएस की सेवा को उतनी अवधि के लिए बढ़ा सकती है, जितनी वह आवश्यक समझे, जो अधिकतम 65 वर्ष की आयु के अधीन हो।
- इसका आशय है कि सेना में सभी लेफ्टिनेंट जनरल और नौसेना और वायु सेना में समकक्ष अधिकारी, जो जून 2020 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, विचाराधीन हैं।

संशोधन का आधार

- इस परिवर्तन के बाद सीडीएस के पद के लिए ज्यादा आवेदक होंगे।
- इससे हाल ही में रिटायर हुए पूर्व कमांडर इन चीफ रैंक के अफसर भी सीडीएस बन सकते हैं।
- थ्री स्टार जनरल यानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, एयरफोर्स में एयर मार्शल और नेवी में वाइस एडमिरल 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इसलिए कोई भी थ्री स्टार जनरल, जिसे रिटायर हुए दो साल से कम का समय हुआ है, वह भी सीडीएस बनने की दौड़ में शामिल माने जा सकते हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

- 1999 में हुए करगिल युद्ध के बाद जब 2001 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) ने समीक्षा की तो पाया गया कि तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय की कमी रही। अगर तीनों सेनाओं के मध्य प्रभावी सामंजस्य होता तो नुकसान को काफी कम किया जा सकता था।
- उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो पाई।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान सीडीएस के पद के निर्माण की घोषणा की थी।
- यह पद दिसंबर 2021 से खाली है।

धर्मांतरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी

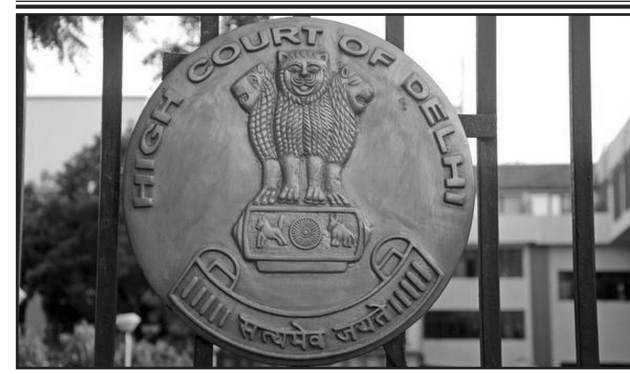

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में उल्लिखित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत लोगों के अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।

याचिका

- अश्विनी उपाध्याय ने कथित तौर पर वंचित लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के "सामूहिक धर्मांतरण" का आरोप लगाया था।
- उन्होने याचिका में मांग की है कि दिल्ली में धर्म परिवर्तन की लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाए, क्योंकि दिल्ली में बड़े पैमाने में धर्म परिवर्तन हो रहा है।
- याचिकाकर्ता ने मांग की कि स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई व्यक्ति और संगठन बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है।

उच्च न्यायालय की टिप्पणी

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल आशंकाओं के आधार पर याचिका दाखिल की गई है।
- प्रस्तुत अनुमानों का स्रोत व्यक्तिगत ज्ञान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का निर्णय, संविधान सभा वाद-विवाद और सरकारी वेबसाइटों से एकत्र की गई जानकारी है।
- किसी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करने का अधिकार है। वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार का अधिकार प्रदान करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25

- संविधान का अनुच्छेद 25 (1) कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में दो प्रकार के अधिकारों का उल्लेख करता है, पहला अधिकार अंत करण की स्वतंत्रता और दूसरा अधिकार धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- अंत: करण की स्वतंत्रता का तात्पर्य आत्यंतिक आंतरिक स्वतंत्रता से है, जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंधों को स्थापित करता है। यह स्वतंत्रता जब बाहरी रूपों में व्यक्त की जाती है, तो उसे धर्म को मानना और प्रचार करना कहते हैं।
- धर्म के मानने से तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वासों का स्वतंत्रता पूर्वक और खुलेआम घोषित करना, प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को किसी भी व्यावहारिक रूप से मान सकता है। धर्म के आचरण करने का तात्पर्य धर्म द्वारा विहित कर्तव्यों कर्मकांड और धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है, जो उसके धर्म द्वारा विहित किए गए हो। धर्म के प्रचार करने का अर्थ विचारों को दूसरों तक प्रेषित करना और इसके लिए उनका प्रकाशन करना आवश्यक है।
- प्रचार का अर्थ अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करना ही नहीं अपितु उसको मनवाने के लिए समझाने-बुझाने का भी अधिकार शामिल है, बशर्ते कि इसके संबंध में कोई दबाव का तत्व न हो। प्रचार करने के अधिकार में किसी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने का अधिकार शामिल नहीं है।
- अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अंत करण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वह केवल अपने विशेष धर्म को अनुसरण करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म को परिवर्तित करने का मूल अधिकार सम्मिलित नहीं है।
- यदि व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को दूसरों तक प्रेषित करने के बजाय उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश करता है तो वह उसके अंतरण की स्वतंत्रता पर सीधा आघात करता है, जो संविधान द्वारा वर्जित है, यदि विधानमंडल विधि बनाकर कोई ऐसा कानून बनाकर धर्म परिवर्तन का प्रतिषेध करता है तो वह संविधानिक होगा।

रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य

- रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 25 में 'प्रचार' शब्द "दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार" नहीं देता है। यद्यपि इसमें सिद्धांतों की व्याख्या के द्वारा धर्म का प्रसार किया जा सकता है।
- संविधान पीठ ने यह भी कहा था कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे का धर्मांतरण करता है, जो धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने या फैलाने के प्रयास से अलग है, तो वह देश के सभी नागरिकों को समान रूप से दी गई 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता' पर आघात माना जाएगा।

श्रेष्ठ योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशन में 'श्रेष्ठ' योजना का शुभारंभ किया गया। विदित है कि इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाईस्कूल के छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है।

श्रेष्ठ योजना क्या है?

- संविधान के अनुसार, अनुसूचित जाति के सबसे गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) तैयार की गई है।
- इसे देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करने की मंशा से शुरू किया गया है।
- इसके अंतर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों के कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

उद्देश्य

- सरकारी पहलों और योजनाओं की सुलभ पहुँच सुनिश्चित करना।
- अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समग्र विकास के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- शिक्षा क्षेत्र में सेवा से वंचित अनुसूचित जाति (SC) के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिये स्वयंसेवी समूहों के साथ सहयोग करना।
- योग्य अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ सक्षम करना, ताकि वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकें।

पात्रता

- अनुसूचित जाति के छात्र, जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र हैं।
- इसमें 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हाशिये के आय वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं।
- चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ (NETS) के रूप में जाना जाता है।
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 9वीं और 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लिये इसका आयोजन किया जाएगा।

लाभार्थी

- सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रणाली के तहत हर साल SC वर्ग के लगभग 3000 छात्रों को कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा।
- मंत्रालय उनके शिक्षा और आवास शुल्क की पूरी लागत वहन करेगा जब तक कि वे अपनी कक्षा 12वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते।

SCs के लिये अन्य संबंधित पहलें

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक नोडल एजेंसी है।

- नए छात्रावासों के निर्माण के लिये केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) के तहत निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों, अर्थात् राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों/ गैर-सरकारी संगठनों/ डीम्ड विश्वविद्यालयों/ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

SCs के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

- यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसे राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है।
- सरकार अपने प्रयासों में वृद्धि के लिये प्रतिबद्ध है ताकि अनुसूचित जाति का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय मानकों तक पहुँच जाए।

एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को योग्यता परीक्षा आयोजित करके योजना को लागू करने का काम सौंपा गया है।
- **लाभार्थी:** अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त, खानाबदोश और घुमंतू जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति (EBC) श्रेणियों के छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे।

सामरिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण

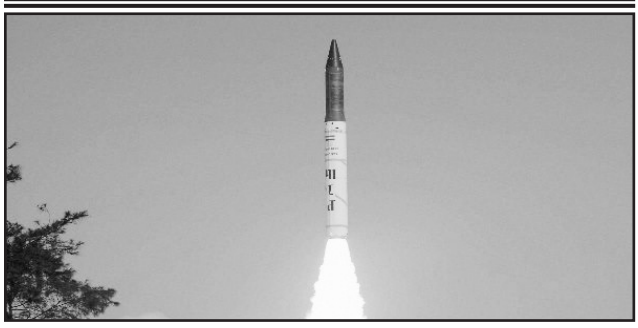

- भारत ने 6 जून को मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (Intermediate Range Ballistic Missile- IRBM) अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया।
- ज्ञातव्य है कि अग्नि-4 का सफल परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की नीति की पुष्टि करता है।
- यह सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command) के तत्वावधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च का हिस्सा था।
- यह सामरिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला में कई मिसाइलों में से एक है।
- अग्नि-4 मिसाइल की सीमा 3,500 किमी से अधिक है।
- रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, लॉन्च ने सभी परिचालन मानकों और सिस्टम की विश्वसनीयता को भी मान्य किया है।

एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप

- ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-4 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया।
- अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह भारत के ओडिशा के तट पर एक द्वीप है, जो राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर (93 मील) दूर है।
- इस द्वीप में एकीकृत परीक्षण रेंज मिसाइल परीक्षण सुविधा है। इस द्वीप का नाम मूल रूप से अंग्रेजी कमांडेंट लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था।
- 4 सितंबर 2015 को दिवंगत भारतीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को सम्मानित करने के लिए द्वीप का नाम बदल दिया गया था।
- अब्दुल कलाम द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर (6.2 मील) दूर बंगाल की खाड़ी में और ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर से लगभग 70 किलोमीटर (43 मील) दक्षिण में स्थित है।

परीक्षण का सामरिक महत्व

- यह परीक्षण पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य टकराव के बीच हुआ है, जो अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और ऊंचाई वाले क्षेत्र में तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है।
- त्रि-सेवा सामरिक बल कमान (एसएफसी) में पहले से ही पृथ्वी-द्वितीय (350-किमी), अग्नि- I (700-किमी), अग्नि-द्वितीय (2,000-किमी), अग्नि- III (3,000-किमी) और अग्नि- IV मिसाइल इकाइयाँ हैं।
- देश की पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-V (5,000 किलोमीटर से अधिक) को शामिल करने का काम अभी उन्नत चरण में है।
- अग्नि- IV और अग्नि-V मुख्य रूप से चीन के खिलाफ प्रतिरोध के लिए हैं, जो लंबी दूरी की मिसाइलों की अपनी दुर्जेय सूची के साथ किसी भी भारतीय शहर को निशाना बना सकता है। अग्नि-5 चीन के सबसे उत्तरी हिस्से को अपने हमले के दायरे में लाता है। वहीं कम दूरी की अग्नि मिसाइलें पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- भारत ने परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम को ध्यान में रखते हुए सुखोई -30 एमकेआई, मिराज -2000 और जगुआर लड़ाकू विमानों को संशोधित किया है। भारतीय वायु सेना द्वारा शामिल किए गए नए फ्रांसीसी मूल के राफेल लड़ाकू विमान भी ऐसा करने में सक्षम हैं।

दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए का दुरुपयोग और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

- हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के दुरुपयोग के दृष्टिगत महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
- न्यायालय ने दहेज मामले से संबंधित दो आपराधिक संशोधनों की अनुमति देते हुए, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए कुछ सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिया और उत्तर प्रदेश के राज्य अधिकारियों को एक निश्चित समय अवधि में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) के तहत प्रत्येक जिले में एक परिवार कल्याण समिति का गठन किया जाना चाहिए और ऐसी समिति को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के तुरंत बाद सौंपना चाहिए।
- दो महीने की "कूलिंग पीरियड" के दौरान पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
- उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित परिवार कल्याण समितियों (जैसे कि एक युवा मध्यस्थ या एक वकील या एक वरिष्ठ कानून के छात्र को शामिल करना) की संरचना में मामूली अंतर को छोड़कर, ऐसी समितियों की प्राथमिक भूमिका वही रहती है, जो दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद के निपटान के लिए होती है।
- प्रत्येक जिले में कम से कम एक या अधिक एफडब्ल्यूसी (जिला कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के तहत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर) में कम से कम तीन सदस्य होंगे। इसके गठन और कार्य की समीक्षा उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा समय-समय पर की जाएगी, जो उस जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण में चेयरपर्सन या को-चेयरपर्सन होंगे।
- दूसरे शब्दों में, यदि वैवाहिक लड़ाई के दौरान किसी महिला की हड्डी टूट जाती है या उसके पति द्वारा किसी आंख या कान या जोड़ में स्थायी चोट लग जाती है, तो पुलिस गिरफ्तारी को प्रभावी नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे मामलों में निर्धारित अधिकतम कारावास गंभीर चोट के लिए सात वर्ष है।
- पुलिस केवल परिधीय जांच करेगी, जैसे कि चोट की रिपोर्ट एकत्र करना और गवाहों के बयान दर्ज करना, जिनकी कीमत आगे की कार्यवाही में अनिश्चित है।

मानव अधिकार बनाम भारत संघ (2018)

- उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से मानव अधिकार बनाम भारत संघ (2018) के लिए सोशल एक्शन फोरम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मार्गदर्शन लेने के अपने फैसले में उल्लेख किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा और अन्य बनाम यू पी राज्य और अन्य ने पहली बार में धारा 498-ए आईपीसी के तहत आपराधिक शिकायतों को देखने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित परिवार कल्याण समिति को अधिकार प्रदान करने सहित कई निर्देश जारी किए।
- निर्देश दिया गया कि जब तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।
- ध्यातव्य है कि सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार 2018 (10) SCC 443 में, सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या ऐसे निर्देश जारी किए जाने चाहिए थे।

लिव इन रिलेशनशिप पर न्यायालय का पक्ष

- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए का दुरुपयोग वैवाहिक संस्था को प्रभावित कर रही है और लिव इन रिलेशनशिप परंपरागत विवाह का स्थान लेती जा रही है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मुकेश बंसल की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपरागत विवाह का स्थान लेती जा रही है। यह जमीनी हकीकत है, जिसे स्वीकार करने की आवश्यकता है।

आईपीसी की धारा 498ए

- भारतीय संसद ने 1983 में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498ए पारित की।
- विदित है कि आईपीसी की धारा 498ए आपराधिक कानून है।
- इसका उद्देश्य एक महिला पर उसके पति और उसके ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता को रोकने के लिए त्वरित राज्य हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करना था।
- इसमें परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने ऐसी महिला के साथ क्रूरता की है, तो उन्हें 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए महिला के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यू) के लिए सबसे बड़े कानूनी बचाव में से एक है, जो एक घर की चार दीवारों के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा की दयनीय वास्तविकता का प्रतिबिंब है।

निष्कर्ष

- घरेलू हिंसा और पति या पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार एक जटिल व्यवहार हैं।
- न्यायालयों, कानूनी संस्कृतियों और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है, किन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

एनडीपीएस को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने की योजना

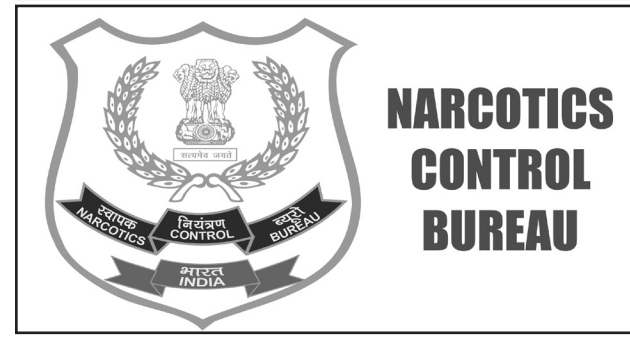

- सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 और नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।
- वर्तमान में, गृह मंत्रालय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को नियंत्रित करता है, इसलिए सरकार नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मुद्दों को गृह मंत्रालय के तहत लाने की योजना बना रही है।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 किसी व्यक्ति को किसी भी मादक औषधि के उत्पादन/निर्माण/खेती और उपभोग से प्रतिबंधित करता है।
- नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 में मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के प्रावधान हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

- इसकी स्थापना 1986 में हुई थी।
- यह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नज़र रखने और अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- सत्य नारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक हैं।

इंडिया चाइल्ड वेल-बीइंग रिपोर्ट 2021

Where children are in a state of well-being

Based on World Vision India's Child Well-Being Index 2021

Best performing States (overall)

State	Rank	Index score
Kerala	1	0.89
Uttarakhand	2	0.77
Punjab	3	0.77
Himachal Pradesh	4	0.73
Sikkim	5	0.73

Worst performing States (overall)

State	Rank	Index score
Meghalaya	28	0.00
Bihar	27	0.02
Tripura	26	0.14
Uttar Pradesh	25	0.18
Odisha	24	0.18

Best performing districts (overall)

District	State	Rank
Kasaragod	Kerala	1
Kanniyakumari	Tamil Nadu	2
Wayanad	Kerala	3
Pathanamthitta	Kerala	4
Kannur	Kerala	5

Toppers in each category

Indicator	State with the highest rank	State with the lowest rank
Health	Mizoram	Bihar
Hygiene	Sikkim	Odisha
Protection	Arunachal Pradesh	Kerala
School Education	Kerala	Meghalaya

- हाल ही में, वर्ल्ड विजन इंडिया और पॉवर्टी लर्निंग फाउंडेशन ने इंडिया चाइल्ड वेल-बीइंग रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है ।
- इंडिया चाइल्ड वेल-बीइंग रिपोर्ट 2021 ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और स्कूली शिक्षा जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को बच्चे की भलाई पर रैंकिंग प्रदान की है।
- इंडिया चाइल्ड वेल-बीइंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार केरल सभी राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि मेघालय अंतिम स्थान पर है।
- उत्तराखंड (0.77), पंजाब (0.76), हिमाचल प्रदेश (0.73) और सिक्किम (0.72) क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।
- बिहार (0.02), त्रिपुरा (0.14), उत्तर प्रदेश (0.177) और ओडिशा (0.179) सूची में सबसे निचले राज्यों में शामिल हैं।
- कासरगोड, कन्याकुमारी, वायनाड, पठानमथिट्टा और कन्नूर शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले जिले हैं।
- मिजोरम, केरल और उत्तराखंड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है।
- रिपोर्ट में राज्यों के समग्र स्कोर की गणना स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और स्कूली शिक्षा के मानकों के आधार पर की गई है।

भारत एनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी

- भारत एनसीएपी (नई कार आकलन कार्यक्रम) में भारत में ऑटोमोबाइल को स्टार रेटिंग दी जाएगी।
- स्टार रेटिंग क्रैश टेस्ट (टक्कर परीक्षण) में उनके प्रदर्शन पर आधारित होगी।

- भारत-एनसीएपी उपभोक्ता केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा।
- यह ग्राहकों को उनकी स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों को चुनने की अनुमति देगा।
- यह सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए भारत में मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत एनसीएपी के परीक्षण प्रोटोकॉल को ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाएगा।

चुनाव आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 'गैर-मौजूद' दलों को हटा दिया

- एक सत्यापन अभ्यास के दौरान, चुनाव आयोग ने अपने रजिस्टर से 111 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने का आदेश दिया है।
- सत्यापन के दौरान इन पार्टियों को "अस्तित्वहीन" पाया गया। चुनाव आयोग द्वारा उनके पते और संचार विवरणों को सत्यापित करने के लिए भेजे गए पत्र बिना प्राप्ति के वापस हो गए।

- इन 111 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुच्छेद 29ए (4) और अनुच्छेद 29ए (9) का अनुपालन नहीं किया।
- चुनाव आयोग ने कर छूट का दावा करने वाले कई पंजीकृत राजनीतिक दलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
- इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने 87 गैर-मौजूद राजनीतिक दलों को अपने रजिस्टर से हटा दिया था।
- भारत में लगभग 2,800 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं।

राजनीतिक दल पंजीकरण

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत राजनीतिक दल का पंजीकरण किया जाता है।
- पंजीकरण की मांग करने वाले किसी भी दल को गठन के 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को एक आवेदन जमा करना होता है।

एमओएचयूए ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए 'निपुण' (एनआईपीयूएन) परियोजना शुरू की

- नई दिल्ली में, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक नई योजना शुरू की, जिसका नाम निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण) है।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत 'निपुण' की शुरुआत की।
- इस योजना का उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है, साथ ही उन्हें अन्य देशों में अवसर प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार होगा। एनएसडीसी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत नोडल एजेंसी है।

परियोजना कार्यान्वयन को तीन भागों में बांटा गया है:

- निर्माण स्थलों पर पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से प्रशिक्षण।
- नलसाजी (प्लंबिंग) और बुनियादी ढांचा क्षेत्र कौशल परामर्श परिषद (इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल-एसएससी) द्वारा नवीनतम कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण।
- उद्योगों / बिल्डरों / ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट किया जाना।

साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया

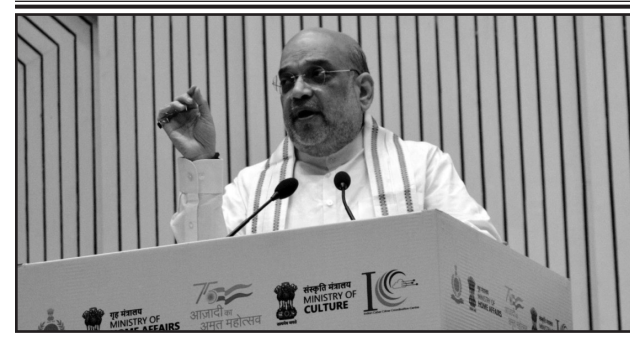

- 20 जून को, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन (साइबर अप्राध से आज़ादी - आज़ादी का अमृत महोत्सव) नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था।
- गृह मंत्रालय ने सम्मेलन की मेजबानी की।
- सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह थे।
- यह सम्मेलन साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के देश के प्रयासों का हिस्सा है।

केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हित में निष्पक्ष विज्ञापन के लिए नए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए

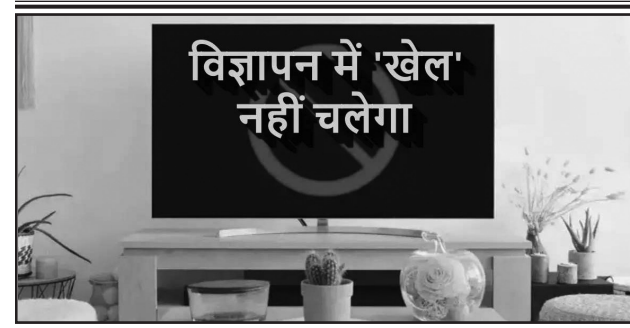

- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवा के भ्रामक प्रचार से बचाने के लिए विज्ञापन के लिए नए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।
- दिशा-निर्देश 10 जून, 2022 को लागू हुए हैं। यह सरोगेट विज्ञापन पर रोक लगाएगा और बच्चों के लिए विज्ञापनों और 'बेट' विज्ञापनों के लिए इसने शर्तें रखी हैं।
- दिशा-निर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी प्लेटफार्मों पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे।
- नए दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से 'भ्रामक विज्ञापन' के अर्थ को परिभाषित करता हैं और 'बेट' विज्ञापनों पर भी स्पष्टता प्रदान करता हैं।
- यह न केवल उपभोक्ताओं की रक्षा करेगा बल्कि उद्योग को विज्ञापनों की असलियत के बारे में भी समझाएगा।
- दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

- सरोगेट विज्ञापन एक प्रकार का विज्ञापन है जिसमें कंपनियां सिगरेट और शराब जैसे बाजार विनियमित उत्पादों के लिए प्रच्छन्न विज्ञापनों का उपयोग करती हैं।
- 'बेट' विज्ञापन एक प्रकार का विज्ञापन है जो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कम कीमतों पर वस्तुओं की पेशकश करता है।

रामकृष्ण मुक्काविल्ली यूएनजीसी द्वारा वैश्विक एसडीजी पायनियर के रूप में नामित होने वाले पहले भारतीय बने

- रामकृष्ण मुक्काविली को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट (यूएनजीसी) द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) पायनियर के रूप में मान्यता दी गई है।
- यूएनजीसी ने दस नए एसडीजी पायनियर्स, व्यापारिक नेताओं को नामित किया है, जो मानवाधिकार, पर्यावरण, श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के दस सिद्धांतों को लागू करके एसडीजी को आगे बढ़ा रहे हैं।
- मेक-इन-इंडिया कंपनी मैत्री एक्वाटेक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक रामकृष्ण मुक्काविल्ली को पहले इस साल की शुरुआत में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया (जीसीएनआई) द्वारा भारत के एसडीजी पायनियर के रूप में चुना गया था।
- उन्हें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में फैले 27 देशों में प्रकृति आधारित जल समाधान के साथ जल सुरक्षा के निर्माण में उनके काम के लिए चुना गया था।
- मैत्री एक्वाटेक एक ईएसजी कंपनी है, और उनका 'मेघदूत' उत्पाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एकमात्र वायुमंडलीय जल जनरेटर (एडब्ल्यूजी) समाधान है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा जारी किया है।
- इसमें सरकार द्वारा नियुक्त अपील समितियां बनाने का प्रस्ताव है। इसे सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा लिए गए कंटेंट-मॉडरेशन फैसलों को वीटो करने का अधिकार होगा।
- मसौदा एक शिकायत अपील समिति बनाने का प्रस्ताव करता है। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे।
- कोई भी उपयोगकर्ता जो सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह सरकार द्वारा नियुक्त अपील समितियों के समक्ष निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है।
- यह सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की भी सिफारिश करता है।
- इसने शिकायत निवारण तंत्र में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। सोशल मीडिया मध्यस्थों को 72 घंटों के भीतर प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने के संबंध में शिकायतों का समाधान करना होगा।
- आईटी नियम 2021 में एक नया खंड जोड़ा गया है, जिसके तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों को 'भारत के संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं को गारंटीकृत अधिकारों' का सम्मान करना होगा
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता) नियम फरवरी 2021 में अधिसूचित किया गया था। यह मई 2021 में लागू हुआ।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति का शुभारंभ किया

- राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 (NASP 2022) भारत में एक सुरक्षित, सुलभ, किफायती और टिकाऊ वायु खेल इकोसिस्टम बनाएगी।
- इसका लक्ष्य 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करना और 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार देना है।
- यह दुनिया भर से विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से वायु खेल के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करने में मदद करेगा।
- 'राष्ट्रीय वायु खेल नीति' 2022 का मसौदा नीति निर्माताओं, एयर स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर्स और जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की मुख्य विशेषताएं

- एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएसएफआई) भारत में एयर स्पोर्ट्स के लिए सर्वोच्च शासी निकाय होगा।
- क्षेत्रीय या राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश स्तर की इकाइयों का भी गठन किया जाएगा।

- इसमें बैलूनिंग, एरोबेटिक्स, पैराशूटिंग आदि सहित कई हवाई खेल शामिल होंगे।
- यह वैश्विक हवाई खेल आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता को बढ़ाने में मदद करेगा।
- यह भारत में हवाई खेल उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा देगा।
- यह सुरक्षा, हवाई खेल के बुनियादी ढांचे, उपकरण और संचालन में अंतरराष्ट्रीय अच्छी प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा।

अमित शाह ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) का उद्घाटन किया

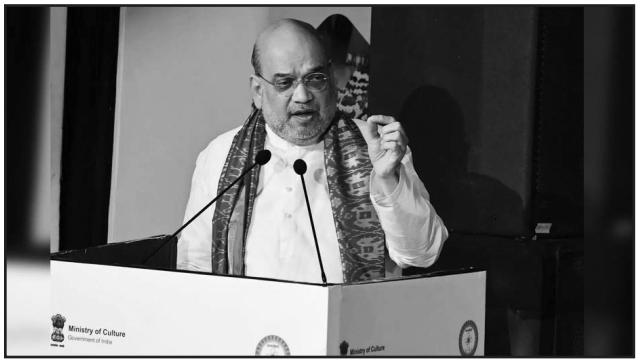

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में एनटीआरआई का उद्घाटन किया गया।
- एनटीआरआई एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान होगा। यह जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों का केंद्र बन जाएगा।
- यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की परियोजनाओं की निगरानी करेगा। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय को नीतिगत इनपुट प्रदान करेगा।
- यह राज्य कल्याण विभागों को भी नीतिगत इनपुट प्रदान करेगा।
- यह आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का समर्थन करने वाले अध्ययनों और कार्यक्रमों को डिजाइन करेगा।

भारतीय वायु सेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा

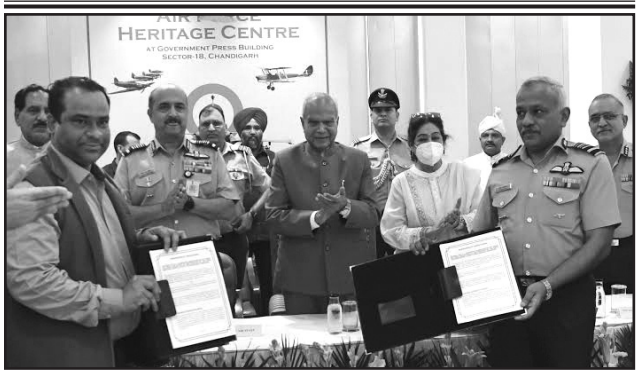

- भारतीय वायु सेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से 'आईएएफ हेरिटेज सेंटर' स्थापित किया जाएगा।
- केंद्र-शासित प्रदेश चंडीगढ़ और आईएएफ ने इस केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- इसमें भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए कलाकृतियां, सिमुलेटर और इंटरैक्टिव बोर्ड होंगे।
- विरासत केंद्र विभिन्न युद्धों में भारतीय वायु सेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करेगा।
- इसके अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।

भारतीय वायु सेना

- इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और हवाई युद्ध करना है।
- भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं।
- वायु सेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं।

ई-संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया

- टेलीमेडिसिन सेवा 'ई संजीवनी' को एनएचए के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ एकीकृत किया गया है।
- एकीकरण ई-संजीवनी के उपयोगकर्ताओं को आसानी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) बनाने और अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग करने में मदद करेगा।
- अब, उपयोगकर्ता ई-संजीवनी पर डॉक्टरों के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी साझा कर सकते हैं। यह बेहतर नैदानिक निर्णय लेने और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- 'ई-संजीवनी' सेवा दो प्रकारों में उपलब्ध है: ई-संजीवनी आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और ई-संजीवनी ओपीडी योजना।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- इसे देश में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था।
- यह हेल्थकेयर इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को पाटने में मदद करता है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट

- हाल ही में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने आठ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की आय के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है।

- एडीआर की इस रिपोर्ट में उल्लिखित है कि 2020-2021 में आठ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की आय का 54% भाजपा को प्राप्त हुआ।
- एडीआर ने भाजपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई वार्षिक लेखापरीक्षित रिपोर्टों का विश्लेषण किया।
- 1,373.78 करोड़ रुपये की कुल घोषित आय में से भाजपा के पास 752.33 करोड़ रुपये थी, जबकि कांग्रेस 285.76 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर थी, उसके बाद क्रमशः CPI(M) 171.04 करोड़ रुपये, तृणमूल कांग्रेस 74.41 करोड़ रुपये, बसपा 52.46 करोड़ रुपये, राकांपा 34.92 करोड़ रुपये, भाकपा 2.12 करोड़ रुपये और नेशनल पीपल्स पार्टी (69 लाख रुपये) का स्थान है।
- बीजेपी ने जहां अपनी आय का 82 फीसदी खर्च किया, वहीं कांग्रेस ने अपनी कमाई का 73.14 फीसदी खर्च किया। तृणमूल कांग्रेस का खर्च उसकी कमाई से 78.10% अधिक था।

आय का मुख्य स्रोत

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के लिए आय का प्राथमिक स्रोत स्वैच्छिक योगदान था, जबकि कांग्रेस को अपनी अधिकांश आय कूपन जारी करने से और बसपा को बैंक ब्याज से मिली।
- भाजपा ने अपने कुल खर्च का अधिकांश हिस्सा "चुनाव/आम प्रचार" (421.01 करोड़ रुपये) पर खर्च किया। वहीं चुनावी खर्च पर कांग्रेस और राकांपा ने अपने कुल खर्च का 84% "प्रशासन और सामान्य खर्च" पर व्यय किया।
- भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने चुनावी बांड से क्रमश: 22.38 करोड़, 42 करोड़ और 10.07 करोड़ रुपये की आय घोषित की।
- एडीआर की रिपोर्ट में पाया गया कि सभी दलों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट 59 दिनों (बसपा) से लेकर 201 दिनों (बीजेपी) तक की समय सीमा से पहले जमा कर दी थी।

एडीआर रिपोर्ट

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्थापना 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा की गई थी।
- इसका लक्ष्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर काम करके शासन में सुधार और लोकतंत्र को मजबूत करना है।
- एडीआर देश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने प्रयासों को केंद्रित करता है:
  - राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण।
  - बेहतर और सूचित विकल्प के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित सूचना के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं का सशक्तिकरण।
  - राजनीतिक दलों की अधिक जवाबदेही की आवश्यकता।
  - पार्टी के भीतर लोकतंत्र और पार्टी के कामकाज में पारदर्शिता की आवश्यकता।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

इज़राइल-संयुक्त अरब अमीरात मुक्त व्यापार समझौता

- हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मंगलवार को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए। यह पहला अवसर है, जब इज़रायल ने किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है।
- विदित है कि इससे पहले यूएई वर्ष 2020 में अमेरिकी के समर्थन से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुआ था। तब से, दोनों देशों ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है।
- यह यहूदी राज्य और अरब-बहुमत वाले देश के बीच पहला पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है, जो 2020 में यूएस-ब्रोकर संबंधों के सामान्यीकरण अर्थात अब्राहम समझौते पर आधारित है।
- इससे यूएई-इज़राइल व्यापार 2022 में 2 बिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है, जो पांच वर्षों में बढ़कर लगभग 5 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यह अक्षय, उपभोक्ता वस्तुओं, पर्यटन और जीवन विज्ञान क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करेगा।
- मुक्त व्यापार समझौते में विनियमन, सीमा शुल्क, सेवाएं, सरकारी खरीद, ई-कॉमर्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा शामिल है।
- समझौते के अनुसार, खाद्य, कृषि, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण और दवा सहित देशों के बीच कारोबार किए जाने वाले लगभग 96% उत्पादों को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी।
- 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के बाद संयुक्त अरब अमीरात इजरायल के साथ औपचारिक रूप से संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला तीसरा अरब देश बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला फारस की खाड़ी देश बन गया।
- यह समझौता इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक "अभूतपूर्व कदम" था जो "क्षेत्र के लिए प्रेरणा" के रूप में भी काम करेगा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए "दोनों देशों के उद्यमियों के लिए व्यापार के लिए असीमित अवसर पैदा करेगा।

अब्राहम समझौता

- अब्राहम समझौते के अंतर्गत इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच एक सामान्यीकरण समझौते पर सितंबर 2020 में वाइट हाउस में हस्ताक्षर किए थे। बाद में, सूडान और मोरक्को जैसे देश भी इस समझौते में शामिल हुए।
- 2020 में अब्राहम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से दोनों देश कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास, साझा चिंता और वैश्विक मसले पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि अब्राहम यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के साझा पूर्वज हैं। ये वो संबंध है, जो सदियों पुरानी शत्रुता से इतर इन तीनों धर्मों को पारस्परिक संबद्ध करता है।
- इब्राहीम समझौते के हिस्से के रूप में, इज़राइल फ़िलिस्तीनी क्षेत्र के आगे के कब्जे को रोकने के लिए सहमत हो गया।

भारत-इज़रायल रक्षा सहयोग

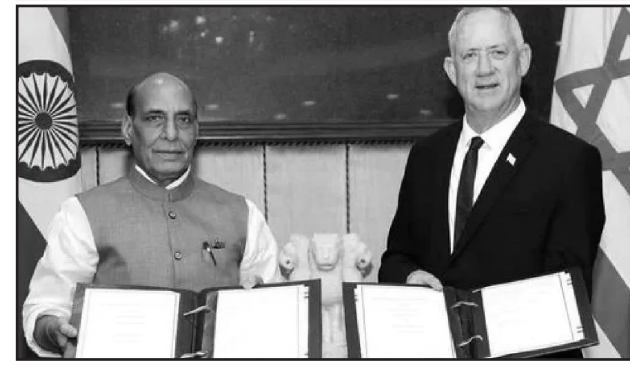

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इज़रायली समकक्ष बेंजामिन गैंट्ज के मध्य कूटनीतिक वैश्विक चुनौतियों, सैन्य सहयोग और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

विमर्श के मुख्य बिन्दु

- दोनों मंत्रियों के बीच भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर एक आशय पत्र का भी आदान-प्रदान किया गया।
- भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और इजरायल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के बीच हस्ताक्षरित एक सहयोग समझौते पर भी चर्चा की गई।
- मंत्रियों ने भारत के "असाधारण विकास और उत्पादन क्षमताओं" के साथ-साथ इजरायल के "तकनीकी अग्रिम और परिचालन अनुभव" का उपयोग करने वाले तरीके से रक्षा सहयोग को और विकसित करने की अपनी मंशा की घोषणा की
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर व्यापक सहमति व्यक्त की गई।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2022 भारत और इज़राइल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का प्रतीक है।

- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17-21 अक्टूबर 2021 तक इज़राइल की आधिकारिक यात्रा की। यात्रा के दौरान, इज़राइल ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अनुसमर्थन प्रदान किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के अवसर पर इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की।
- रक्षा पर वार्षिक भारत-इज़राइल संयुक्त कार्य समूह (JWG) 26-27 अक्टूबर, 2021 को इज़राइल में आयोजित किया गया था।

भारत-इज़रायल मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

- भारत इज़रायल के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के लिए वार्ता कर रहा है।
- यह घोषणा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अनुरूप है।
- भारत यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
- ज्ञातव्य है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते को प्रभावी किया जा चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए उन्नत चरण में है।
- यह एफटीए कृषि उत्पादों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगा।

भारत-इज़रायल संबंध

- भारत ने वर्ष 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी।
- यद्यपि दोनों देशों के मध्य 29 जनवरी, 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- भारत दिसंबर 2020 तक इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 164 संयुक्त राष्ट्र (UN) सदस्य राज्यों में से एक था।
- भारत में ऊर्जा, रियल स्टेट और वाटर टेक्नोलाजी के क्षेत्रों में इजराइली कंपनियां निवेश के लिए प्रोत्साहित हैं।
- अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2021 तक इजरायल का भारत में प्रत्यक्ष निवेश 25.46 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा है।
- कृषि के क्षेत्र में अब तक इजरायल भारत में 30 सेंटर आफ एक्सीलेंस फार हार्टिकल्चर खोल चुका है तथा आने वाले समय में इस संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

भारत-इज़रायल रक्षा संबंध

- भारत इजरायल से सैन्य उपकरण खरीद मामले में रूस के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है।
- भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज़राइली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया है, जिसके अंतर्गत फाल्कन एडब्ल्यूएसीएस (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स) और हेरॉन, सर्चर-द्वितीय और हारोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइडर क्विक-रिएक्शन विमान भेदी मिसाइल प्रणाली की चर्चा की जा सकती है।
- द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG 2021) की 15 वीं बैठक में दोनों देशों ने सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक दस-वर्षीय रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वीं बैठक

- भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग के सातवें दौर में उद्घाटन भाषण देते विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उल्लिखित किया कि भारत और बांग्लादेश दोनों को अपराध मुक्त सीमा और नदी प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करना चाहिए।
- कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद से यह पहली इन-पर्सन जेसीसी बैठक थी, जिसका पिछला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था।
- विदित है कि भारत-बांग्लादेश जेसीसी का 8वां दौर 2023 में बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा।

द्विपक्षीय सहयोग के किन बिन्दुओं को संदर्भित किया गया

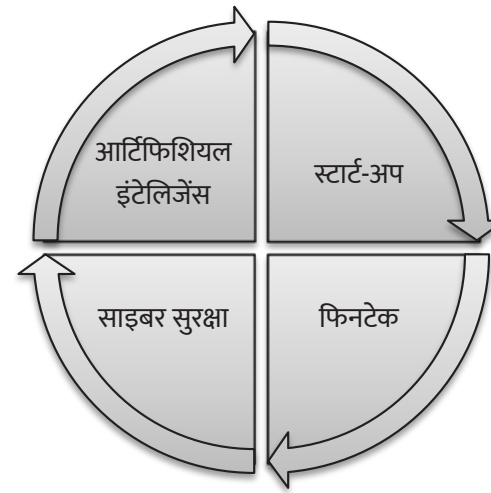

सुंदरबन में साझा पर्यावरण जिम्मेदारी पर विमर्श

- दोनों देश 54 नदियों के प्रबंधन और उनके संरक्षण के साथ-साथ सुंदरबन में साझा पर्यावरण जिम्मेदारी साझा करते हैं।
- ज्ञातव्य है कि ये वास्तव में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- भारतीय विदेश मंत्री ने रेखांकित किया कि उनकी लंबी सीमा का बेहतर प्रबंधन भी एक प्रमुख प्राथमिकता है, सीमा सुरक्षा बलों को सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए कि सीमा अपराध मुक्त रहे।

निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने पर सहमति बनी

- दोनों पक्षों ने साझा नदियों और जल संसाधन प्रबंधन, आईटी और साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की
- ध्यातव्य है कि दोनों पक्षों के मध्य उच्चस्तरीय यात्राओं के अलावा, विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से गहन जुड़ाव रहा है। साथ ही, नए उत्साह और नियमितता के साथ साझेदारी-निर्माण के प्रयासों को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस संबंध में, दोनों मंत्रियों ने अपने अधिकारियों को दोनों लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए मुद्दों को संबोधित करने और टिकाऊ समाधान खोजने पर ध्यान देने के साथ सहयोग में तेजी लाने का दायित्व सौंपा गया।

रखाइन मुद्दे पर परिचर्चा

- दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में रेखांकित किया कि दोनों देश रखाइन प्रांत से म्यांमार में जबरन विस्थापित लोगों की सुरक्षित, तेज और स्थायी वापसी के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिन्हें वर्तमान में बांग्लादेश द्वारा आश्रय दिया जा रहा है।
- विदित है कि बांग्लादेश रखाइन, रोहिंग्या से दस लाख से अधिक विस्थापित लोगों की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2022 इस समुदाय के निर्वासन का पांचवां वर्ष है।

भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता

- भारत और बांग्लादेश ने इस क्षेत्र में उचित कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 2014 में भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों देशों के बीच दस्तावेजों के आदान-प्रदान से 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (एलबीए) को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके तहत दोनों देशों के बीच 161 एनक्लेवों का आदान प्रदान किया गया है।
- समझौते के अंतर्गत 111 सीमा परिक्षेत्रों को 51 के बदले बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जाएगा, जो भारत का हिस्सा बन जाएगा।
- यह समझौता एक पुराने भूमि सीमा विवाद को सुलझाता है, जो औपनिवेशिक काल से है, क्योंकि भारत 51 परिक्षेत्रों के बदले बांग्लादेश को 111 सीमा परिक्षेत्र हस्तांतरित करता है।
- यह इन एन्क्लेव के अंतर्गत रहने वाले 50,000 से अधिक लोगों के लिए नागरिकता के प्रश्न का भी समाधान करता है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

- भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 6 दिसंबर, 1971 को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी।
- भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
- भारत-बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है।
- भारत और बांग्लादेश ने 2021 में अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई।
- दोनों देशों के बीच 54 सामान्य नदियाँ हैं।
- भारत और बांग्लादेश ने 2015 के भूमि सीमा समझौते के माध्यम से सीमा समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन कई नदियों के बंटवारे पर वार्ता प्रगति पर है, जो सीमाओं को परिभाषित करती हैं और दोनों पक्षों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करती हैं।
- यद्यपि, बांग्लादेश विशेष रूप से तीस्ता के पानी का एक उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहा है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से होकर बहती है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

- भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने 9 वर्ष पश्चात दीर्घकाल से लंबित व्यापार और निवेश समझौते के लिए ब्रसेल्स में वार्ता फिर से शुरू की।
- विदित है कि भारत और यूरोपीय संघ द्वारा संतुलित और व्यापक व्यापार समझौते के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने की घोषणा के एक वर्ष पश्चात ब्रसेल्स में वार्ता सम्पन्न हुई।

- इसके अलावा, एक निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए) और एक जीआई समझौते के लिए भी वार्ता शुरू की गई।
- एफटीए पर अगले दौर की बातचीत 27 जून से 1 जुलाई तक नई दिल्ली में होगी।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना है, अपितु दोनों पक्षों के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना, जलवायु की रक्षा के लिए काम करना और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है।
- इसका अंतिम लक्ष्य यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापक पैमाने पर अप्रयुक्त व्यापार और निवेश क्षमता को अधिकतम करना है।

पृष्ठभूमि

- गत वर्ष 8 मई, 2021 को पोर्टो में आयोजित भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता फिर से शुरू करने और आईपीए पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने और जीआई पर एक अलग समझौता-वार्ता के लिए एक समझौता किया गया था।
- दोनों साझेदार अब लगभग नौ साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 2013 में पहले की बातचीत को सौदे के दायरे और अपेक्षाओं में अंतर के कारण छोड़ दिया गया था।
- अप्रैल 2022 में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन की दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाल की यूरोप यात्रा ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को गति दी और वार्ता के लिए एक स्पष्ट रोडमैप को निर्धारित करने में मदद की।

यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण?

- यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते में से एक होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- भारत-यूरोपीय संघ के व्यापारिक कारोबार ने 2021-22 में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 116.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का अभूतपूर्व कारोबार किया है।
- यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 57 प्रतिशत बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो गया। भारत का यूरोपीय संघ के साथ निर्धारण से अधिक व्यापार है।
- दोनों भागीदारों के एकसमान आधारभूत मूल्यों और उनके साझा हितों के साथ साथ उन्हें विश्व की दो सबसे बड़ी खुली बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में ध्यान में रखते हुए, यह व्यापार समझौता आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और सुरक्षित करने, हमारे व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने और लोगों को महत्वपूर्ण लाभ लाने में मदद करेगा।
- दोनों पक्ष निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांतों के आधार पर व्यापार वार्ता को विस्तृत, संतुलित और व्यापक बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं।
- साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाले बाजार पहुंच के मुद्दों को भी संबोधित करने का प्रयास किया गया।

भारत-ईयू संबंध

- दोनों पक्ष 120 बिलियन यूरो के वार्षिक व्यापार के साथ प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं।
- यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसका 2021 में भारतीय व्यापार का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, जिसका 2021 में यूरोपीय संघ के व्यापार में दो प्रतिशत से अधिक का योगदान है।

प्रस्तावित निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए)

- प्रस्तावित आईपीए, निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए सीमा पार निवेश के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
- जीआई समझौते से हस्तशिल्प और कृषि-वस्तुओं सहित जीआई उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और अनुमान-योग्य नियामक वातावरण स्थापित होने की संभावना है।
- दोनों पक्ष समानांतर तौर पर तीनों समझौतों पर बातचीत करने और उन्हें एक साथ समाप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं।
- तीनों समझौतों के लिए पहले दौर की वार्ता 27 जून से 1 जुलाई, 2022 तक नई दिल्ली में होगी।

मुक्त व्यापार समझौता

- मुक्त व्यापार समझौता वार्ता प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संतुलित व्यापार समझौते बनाने और व्यापार तथा निवेश में सुधार के लिए मौजूदा व्यापार समझौतों में सुधार लाने के लिए भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
- मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दो या दो से अधिक देशों के मध्य सम्पन्न व्यापारिक संधि है, जिसके अंतर्गत शामिल देश कुछ दायित्वों, यथा- आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने, निवेशकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर सहमति व्यक्त करते हैं।
- इसमें व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है। सीईपीए में व्यापार के नियामक मुद्दों को भी शामिल किया जाता है।
- सन 1995 में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को सरल बनाने के लिए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) पर सहमति बनी।
- विदित है कि इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की थी।
- इसके बाद एक और प्रणाली का उद्भव हुआ, जिसे मुक्त व्यापार समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो देश या देशों का समूह आपस में समझौता कर सकते हैं।
- भारत ने 1998 में सबसे पहले श्रीलंका के साथ समझौता किया। इससे पहले भारत ने मलेशिया व सिंगापुर से क्षेत्रीय व्यापार समझौता (Regional Trading Agreements- RTA) कर चुका था।

भारत का अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता / समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत वर्तमान में ईयू के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इज़राइल के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता करने की प्रक्रिया में है।
- हाल ही में भारत और यूके ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के दूसरे दौर की वार्ता पूर्ण कर ली है।
- भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) या प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही, दोनों देशों ने निवेश की सुविधा के लिए प्रस्तावित विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (FIPPA) पर भी चर्चा कर रहे हैं।
- 2 अप्रैल, 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं दोनों में एक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) स्थापित करता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र

- ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत की यात्रा से पहले उल्लिखित किया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया के सबसे करीबी सुरक्षा साझेदारों में से एक है और यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में

भागीदारों के साथ ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक रूप से गहरे जुड़ाव को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है।

- विदित है कि यह दौरा 20 से 23 जून तक निर्धारित है।
- मई में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद यह ऑस्ट्रेलिया की पहली उच्च-स्तरीय यात्रा है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में गत कुछ वर्षों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर काफी विस्तार हुआ है।
- नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसने दशकों से हिंद-प्रशांत में शांति और समृद्धि लाई है, दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र भू-रणनीतिक व्यवस्था में बदलाव का सामना कर रहे हैं।
- ऑस्ट्रेलिया एक खुले, समावेशी और लचीले इंडो-पैसिफिक के समर्थन में भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उभरते सहयोग को व्यापक रूप से चीन की चुनौती की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है, जिसे क्वाड जैसे बहुपक्षीय समूहों द्वारा सुगम बनाया गया है।
- यद्यपि हाल ही में 2 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर से पता चलता है कि द्विपक्षीय संबंध कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
- 21 मार्च को आयोजित द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन और उसके बाद का समझौता भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में एक नए चरण का प्रतीक है, विशेष रूप से व्यापक सुरक्षा और रक्षा संदर्भ में।

सूचना संलयन केन्द्र- हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर)

- यह हिंद महासागर क्षेत्र में जहाजों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय पहल है।
- इसका उद्देश्य सहयोगी देशों और बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ नौवहन जागरुकता और सूचना साझा करने के लिये परस्पर सहयोग करना है। यह वाणिज्यिक मालवाहक जहाजों के बारे में सूचनाओं को साझा करने में महत्वपूर्ण है, इससे हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

सामरिक वार्ता

- जून 2020 में, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सचिव स्तर के 2+2 संवाद (रक्षा और विदेश मामलों) को मंत्री स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया।
- साथ ही, व्यापक रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने के लिए दोनों देशों के मंत्री कम से कम हर दो वर्ष में मिलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- दोनों पक्षों ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है।

मालाबार अभ्यास

- भारत की नौसेना अमेरिकी नौसेना (यूएसएन), जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (आरएएन) के साथ 26 से 29 अगस्त 2021 तक मालाबार अभ्यास 2021 के समुद्री चरण में भाग लिया।
- विदित है कि समुद्री नौसैन्य अभ्यास की मालाबार श्रृंखला वर्ष 1992 में आईएन-यूएसएन अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। वर्ष 2020 के अभ्यास संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया।

AUSINDEX

- यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य 06 सितंबर, 2021 से 10 सितंबर, 2021 तक आयोजित किया गया।
- भारतीय नौसेना कार्य समूह में आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत शामिल हुए।

पिच ब्लैक

- भारतीय वायु सेना ने पहली बार 2018 में डार्विन में अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया।
- ऑस्ट्रेलिया के बहुपक्षीय अभ्यास में कई ऑस्ट्रेलियाई सहयोगियों और साझेदार देशों की वायु सेनाएं शामिल हैं।

क्वाड-चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD-Quadrilateral Security Dialogue)

- क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य गठित एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समन्वय की स्थापना करना है।
- क्वाड शब्द 'क्वाड्रीलेटरल (चतुर्भुज) सुरक्षा वार्ता' के क्वाड्रीलेटरल से लिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि क्वाड जैसे समूह की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भारत द्वारा अपने और अन्य प्रभावित पड़ोसी देशों के लिए बचाव और राहत पहुँचाने के प्रयास क्रम में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की परिणति के रूप की गई।

हिंद महासागर क्षेत्र

- हिंद महासागर क्षेत्र विश्व व्यापार और कई देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
- विश्व के 75% से अधिक समुद्री व्यापार और 50% वैश्विक तेल खपत आईओआर से होकर गुजरता है।
- अमेरिका के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों को भारत की रणनीतिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है।
- हिंद-प्रशांत को एक रणनीतिक स्थान के रूप में मानने का विचार हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है।
- यह भारतीय और प्रशांत महासागरों की परस्पर संबद्धता, सुरक्षा और वाणिज्य के लिए महासागरों के महत्व को दर्शाता है।

G7 शिखर सम्मेलन

- भारत और जर्मनी के बीच सुदृढ़ और घनिष्ठ साझेदारी और उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा के दृष्टिगत जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के विशेष निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26-27 जून को जी 7 शिखर सम्मेलन के लिए श्लॉस एलमौ (जर्मनी) की यात्रा करेंगे।
- G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 जून, 2022 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करेंगे।

पृष्ठभूमि

- विदित है कि भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (आईजीसी) के छठे संस्करण के लिए पीएम मोदी की अंतिम जर्मनी यात्रा 2 मई, 2022 को हुई थी।
- प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीन दिवसीय यूरोप यात्रा के पहले चरण में जर्मनी में थे।
- जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था।
- दिसंबर 2021 में चांसलर स्कोल्ज के पदभार ग्रहण करने के बाद से यह उनकी पहली भेंटवार्ता थी।

भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) का छठा संस्करण

- संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, छठे अंतर-सरकारी परामर्श के दौरान भारत और जर्मनी ने हरित और सतत विकास के लिए अपने समझौते में हाइड्रोजन रोडमैप विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देश भारत-जर्मन अक्षय ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने पर सहमत हुए, जिसमें नवीन सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जिसमें बिजली ग्रिड, भंडारण और बाजार डिजाइन के लिए संबंधित चुनौतियों को शामिल किया गया, ताकि एक उचित ऊर्जा संक्रमण की सुविधा मिल सके।
- मई में यात्रा के दौरान, भारत और जर्मनी ने सतत विकास पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो भारत को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करने के लिए 2030 तक € 10 बिलियन की सहायता प्रदान करेगा।
- उस समय, स्कोल्ज़ ने भारत को "अर्थव्यवस्था, रक्षा और जलवायु नीति के मामले में एशिया में जर्मनी के लिए केंद्रीय भागीदार" के रूप में वर्णित किया।

संभावी विमर्श के विभिन्न बिन्दु

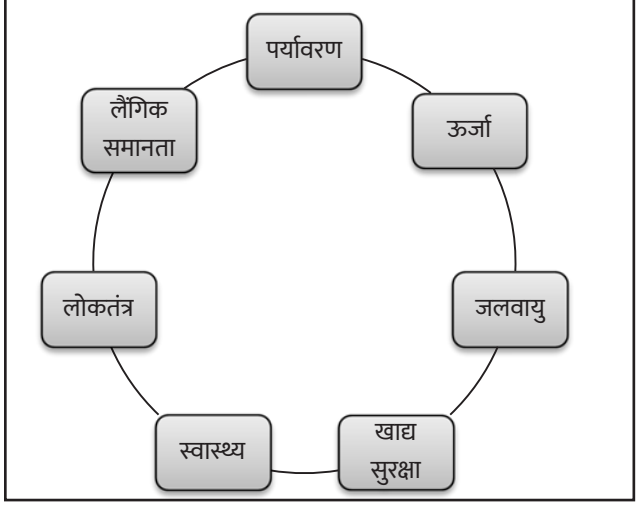

आमंत्रित देश

- प्रधानमंत्री जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के निमंत्रण पर जर्मन रिसॉर्ट श्लॉस एल्मौ की यात्रा करेंगे। उनके दो सत्रों में बोलने की संभावना है, जो पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र पर केंद्रित होंगे।
- भारत के अलावा, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और सेनेगल जैसे देशों को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।

भारत को क्यों आमंत्रित किया गया है?

- भारत को प्राप्त जी-7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भारत और जर्मनी के बीच मजबूत और करीबी साझेदारी और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है।
- प्रधानमंत्री को जी 7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण यूक्रेन में संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत को रूस से दूर करने के जर्मनी के प्रयासों का हिस्सा है।
- विदित है कि रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों के कारण भारत ने यूक्रेन संकट पर तटस्थ रुख बनाए रखा है और बार-बार शत्रुता को समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है।

जी 7

क्या है?

- जी 7 सात देशों का एक अनौपचारिक समूह है। यह विश्व की सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- रूस को 1998 में शामिल कर जी 8 का निर्माण किया गया, किन्तु 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के कारण इसे बाहर कर दिया गया।

सदस्य देश

- इसके सदस्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम हैं, जो यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं।
- विदित है कि यूरोपीय संघ जी 7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।

वैश्विक प्रतिनिधित्व

- सदस्य देश मिलकर वैश्विक जीडीपी का 40% और दुनिया की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

G7 में सन्निहित शक्तियों का अवलोकन

- यह कोई कानून पारित नहीं कर सकता, क्योंकि यह अलग-अलग राष्ट्रों से बना है, जिनकी अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं।
- यद्यपि, इसके पिछले कुछ निर्णयों का वैश्विक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, जी 7 ने 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूके में 2021 में होने वाले जी 7 शिखर सम्मेलन से पहले, जी 7 के वित्त मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक कर देने पर सहमत हुए। इसने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को संबोधित किया है।

चीन ने आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के प्रस्ताव को बाधित किया

- चीन ने यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित शीर्ष लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में सूचीबद्ध करने के भारत-अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को रोक दिया।

पृष्ठभूमि

- मक्की को अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है। मक्की लश्कर-ए-तैयबा के सरगना एवं 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार है।
- मक्की लश्कर-ए-तैयबा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता रहा है, जिसे अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन (एफटीओ) घोषित कर चुका है। भारत और अमेरिका दोनों ने मक्की को अपने-अपने देश के कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है।
- चीन ने अपने इस कदम को संबद्ध प्रक्रियाओं एवं नियमों के अनुरूप बताया है।

प्रस्ताव

- भारत और अमेरिका ने एक जून को मक्की को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अलकायदा एवं आईएसआईएल प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध करने का संयुक्त रूप से प्रस्ताव किया था।
- इसे यूएनएसी 1267 समिति के तौर पर भी जाना जाता है।
- यद्यपि, पाकिस्तान के निकट सहयोगी चीन ने मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर एक तकनीकी रोक लगा दी और यह उपाय एक बार में छह महीने की अवधि तक काम करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।
- प्रतिबंधों का आवेदन इस संबंध में परिषद की संभावनाओं में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 41 के तहत प्रतिबंध उपायों में प्रवर्तन विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें सशस्त्र बल का उपयोग शामिल नहीं है।
- यह आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिक लक्षित उपायों तक हो सकते हैं, जैसे कि धन की जब्ती और यात्रा प्रतिबंध।

प्रतिबंध व्यवस्था

- वर्तमान में यूएनएससी में 14 सक्रिय प्रतिबंध व्यवस्थाएं हैं, जो सशस्त्र संघर्षों, परमाणु अप्रसार और आतंकवाद विरोधी में राजनीतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से प्रतिबंध व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं।

प्रतिबंध समिति

- प्रत्येक प्रतिबंध व्यवस्था को एक प्रतिबंध समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य होते हैं।
- 15 सदस्यों में शामिल हैं - 5 स्थायी सदस्य और यूएनएससी के 10 अस्थायी सदस्य।
- ये प्रतिबंध समितियां प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं और विशिष्ट व्यक्तियों, उद्यमों या संस्थाओं के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों को अपनाने के लिए आम सहमति से निर्णय ले सकती हैं।
- यूएनएससी अल-कायदा और आईएसआईएल प्रतिबंध समिति या 1267 प्रतिबंध समिति उनमें से एक है।
- 1267 प्रतिबंध समिति को आईएसआईएल (दाएश) और अल कायदा प्रतिबंध समिति के रूप में भी जाना जाता है ।
- यह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय संयुक्त राष्ट्र सहायक निकायों में से एक है, विशेष रूप से आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में।
- यह उपरोक्त संगठनों से जुड़े व्यक्तियों, संस्थाओं और समूहों से संबंधित प्रतिबंध उपायों की देख-रेख करता है।
- यह समिति यूएनएससी के प्रस्तावों 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसार प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की देख-रेख करती है।

कार्य

- समिति आतंकवादियों की आवाजाही को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर चर्चा करती है, विशेष रूप से यात्रा प्रतिबंधों से संबंधित, संपत्ति की जब्ती और आतंकवाद के लिए हथियार प्रतिबंध।
- एक बार जब कोई संस्था या व्यक्ति सूची में शामिल हो जाता है तो उसे "वैश्विक आतंकवादी" के रूप में नामित किया जाता है।

सदस्य राज्यों के लिए आवश्यक

- उस व्यक्ति/संस्था की निधियों और वित्तीय संपत्तियों को जब्त करना,
- यात्रा प्रतिबंध लागू करना, और
- हथियारों और संबंधित सामग्री तक पहुंच को बाधित करना।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह इसकी स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई।
- सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी।
- सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर दो वर्ष के बाद होता है।
- इसका मुख्य कार्य दुनियाभर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और

इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम भी सुरक्षा परिषद के काम का हिस्सा है।

- यह परिषद दुनियाभर के देशो में शांति मिशन भी भेजता है और अगर दुनिया के किसी हिस्से में सैन्य अभियान की आवश्यकता होती है, तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करता है।

मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किये जाने हेतु डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन बैठक

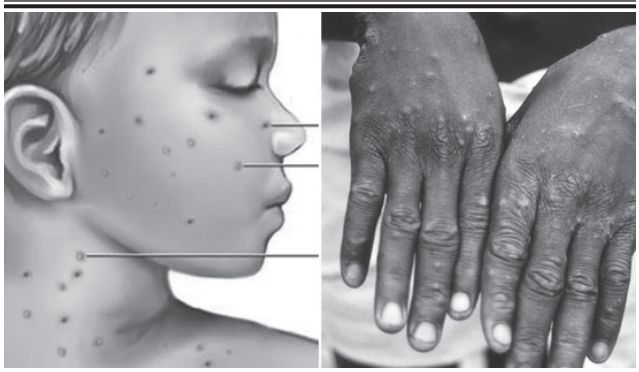

- मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आपात समिति की बैठक आयोजित की है।
- इस आयोजन में मंकीपॉक्स को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।

पृष्ठभूमि

- डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्येयियस ने हाल ही में 40 से अधिक देशों में मंकीपॉक्स के मामले सामने आने के बाद चिंता व्यक्त की थी।
- वर्ष 2017 में नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर ये बीमारी फैली थी और हजारों मामले सामने आए थे।
- मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में ये बीमारी दशकों से लोगों को बीमार बना रही है।
- इस बीमारी के कारण करीब बीमारी के शिकार दस फीसदी लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि अफ्रीका में अभी तक इस बीमारी से एक भी मौत होने की जानकारी नहीं है।

मंकीपॉक्स

- मंकीपॉक्स एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी है, जो मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है।
- मंकीपॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें चेचक और चेचक की बीमारी पैदा करने वाले वायरस भी शामिल हैं।
- यह मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है।

मंकीपॉक्स से जुड़े मामले और प्रसार

- यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था।
- मंकीपॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था।
- यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी-कभी अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाता है।
- अफ्रीका के बाहर अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ब्रिटेन में मंकीपॉक्स के मामले सामने आए हैं और इन मामलों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा व बीमारी से ग्रस्त बंदरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से जोड़ा गया है।
- यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अब तक 42 ऐसे देशों में मंकीपॉक्स के 3,300 से अधिक मामलों की पुष्टि की है, जहां संबंधित वायरस सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है। इनमें 80 प्रतिशत से अधिक मामले यूरोप में हैं। इस बीच अफ्रीका में इस साल 1,400 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 62 लोगों की मौत हो गई है।

मृत्यु दर

- हाल के समय में मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3-6 प्रतिशत रहा है, लेकिन यह 10 प्रतिशत तक हो सकता है।
- संक्रमण के वर्तमान प्रसार के दौरान मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है।

संक्रमण का प्रसार

- मंकीपॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ऐसा माना जाता है कि यह चूहों, चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है।
- यह रोग घावों, शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है।
- यह वायरस चेचक की तुलना में कम संक्रामक है और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है।

मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के निहितार्थ

- मंकीपॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित करने का अर्थ होगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी इस प्रकोप को एक "असाधारण घटना" मानती है और इस बीमारी के और अधिक प्रसार की खतरा है।
- यह कोविड-19 महामारी और पोलियो उन्मूलन के लिए जारी प्रयासों की तरह ही मंकीपॉक्स को लेकर भी कार्रवाई करेगी।
- कई वैज्ञानिकों को अनुमान है कि किसी भी तरह की घोषणा से महामारी के अंकुश लगाने पर मदद मिलेगी, क्योंकि विकसित देशों में मामले सामने आने के बाद वहां इस पर रोक लगाने के लिए पहले ही प्रयास शुरू हो चुके हैं।
- पिछले एक दशक में डब्ल्यूएचओ ने स्वाइन फ्लू, पोलियो और इबोला सहित प्रकोपों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005)

- बीमारी का प्रकोप और अन्य तीव्र सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम सामान्यतः अप्रत्याशित होते हैं और इसके लिए कई तरह की प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं और आपात स्थितियों से निपटने में देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है।
- IHR अंतरराष्ट्रीय कानून का एक उपकरण है, जो 194 डब्ल्यूएचओ सदस्य राज्यों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- IHR घातक महामारियों की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं की रिपोर्ट करने की आवश्यकता सहित देशों के लिए अधिकार और दायित्व का निर्धारण करता है। विनियम ऐसे मानदंडों को भी रेखांकित करते हैं कि कोई विशेष घटना "अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल" है अथवा नहीं।

- आईएचआर विनियमों के तहत स्वास्थ्य उपायों के आवेदन में व्यक्तिगत डेटा, सूचित सहमति और गैर-भेदभाव के उपचार के संबंध में यात्रियों और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को प्रस्तुत करता है।

कार्यान्वयन

- आईएचआर को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उन सभी राज्यों की पार्टियों पर है, जो विनियमों और डब्ल्यूएचओ पर बाध्य हैं।
- सरकारें अपने सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों, स्तरों, अधिकारियों और कर्मियों सहित राष्ट्रीय स्तर पर आईएचआर को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- डब्ल्यूएचओ आईएचआर कार्यान्वयन में समन्वय की भूमिका निभाता है और अपने भागीदारों के साथ मिलकर देशों को क्षमता निर्माण में मदद करता है।
- देश के कार्यान्वयन का लक्ष्य पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य जोखिमों के प्रसार को सीमित करना और अनुचित यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों को रोकना है।
- आईएचआर के लिए आवश्यक है कि सभी देशों के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और आपात स्थितियों का पता लगाने, मूल्यांकन करने और रिपोर्ट करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता हो।

तैयारी

- सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों का तेजी से पता लगाने, सत्यापन और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और बनाए रखने में देशों का समर्थन करने के लिए, डब्ल्यूएचओ उपकरण, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- डब्ल्यूएचओ का समर्थन डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय और विभिन्न देशों के कार्यालयों द्वारा पहचानी गई प्राथमिक आवश्यकताओं पर केंद्रित है, ताकि प्रत्येक देश को अपनी आईएचआर प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिल सके।

यूरोपीय संघ ने यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया को सदस्यता के लिए 'उम्मीदवार' का दर्जा दिया

- यूरोपीय संसद ने यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया को 'उम्मीदवार' का दर्जा देने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
- प्रस्ताव के समर्थन में 529 और विपक्ष में 45 मत पड़े, जबकि 14 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
- यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए कई राजनीतिक और आर्थिक सुधार करने होंगे।
- सभी 27 यूरोपीय संघ सरकारों के प्रमुखों वाली यूरोपीय परिषद यूक्रेन की सदस्यता पर अंतिम निर्णय लेगी।

जी20 की 2023 में बैठकों की मेजबानी करेगा जम्मू और कश्मीर

- जम्मू-कश्मीर सरकार ने जी20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- सितंबर 2021 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को जी20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था।
- भारत 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता करेगा। भारत 2023 में पहला जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।

जी20

- इसकी स्थापना 1999 में केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी।
- इसका गठन एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुआ था। जी20 शिखर सम्मेलन 2011 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

जी20 सदस्यों की सूची

अर्जेंटीना	ऑस्ट्रेलिया	ब्राजील	कनाडा	चीन
फ्रांस	जर्मनी	भारत	इंडोनेशिया	इटली
जापान	तुर्की	मेक्सिको	रूस	दक्षिण अफ्रीका
सऊदी अरब	कोरिया गणराज्य	यूनाइटेड किंगडम	संयुक्त राज्य अमेरिका	यूरोपीय संघ

गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए

- गुस्तावो पेट्रो ने रोडोल्फो हर्नांडिज़ को हराकर कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है।
- फ्रांसिया मार्केज़ कोलंबिया की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति होंगी।
- वह देश की पहली एफ्रो-कोलंबियाई महिला उप-राष्ट्रपति होंगी।
- गुस्तावो पेट्रो एम-19 गुरिल्ला आंदोलन के पूर्व सदस्य हैं।

कोलंबिया

- यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बोगोटा इसकी राजधानी है।
- इसकी सीमा उत्तर में कैरेबियन सागर और पूर्व में वेनेजुएला से लगती है।
- इसकी सीमा दक्षिण-पूर्व में ब्राजील से लगती है। इसकी सीमा दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू से लगती है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में पनामा से लगती है।

जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा।

- जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 28-30 जून को मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
- स्वीडन और फिनलैंड भी अपने प्रतिनिधिमंडल को शिखर सम्मेलन में भेजेंगे।
- 'यूं सुक-योल' शिखर नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले दक्षिण कोरिया के पहले नेता होंगे।
- जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हाल ही में जापान की सैन्य क्षमता और बजट को मजबूत करने की घोषणा की है।
- जापान नाटो का सदस्य नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड ने हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)

- यह 30 देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है।
- इसका गठन 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि के साथ किया गया था, जो नाटो के कामकाज को नियंत्रित करती है।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की

- हाल ही में, डब्ल्यूएचओ के निर्देशन में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर आठ में से एक व्यक्ति मानसिक विकार से पीड़ित है।
- 2019 में, मानसिक विकार से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग एक अरब थी।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, देश अपने स्वास्थ्य देखभाल बजट का 2 प्रतिशत से भी कम मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं।
- मानसिक विकार के कारण ईयर लीवड विथ डिसेबिलिटी (वाईएलडी) हो रहे हैं।
- यह रिपोर्ट देशों से व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013-2030 के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी आग्रह करती है।
- इसमें यह भी कहा गया है कि मानसिक विकार वाले लोगों के खिलाफ कलंक, भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोका जाना चाहिए।
- रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने, जोखिम कम करने और बाधाओं को दूर करने के कदमों पर कई सिफारिशें भी करती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हर 100 मौतों में एक से अधिक लोगों की मौत आत्महत्या के कारण होती है।

यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर भारत-प्रायोजित प्रस्ताव का अनुमोदन किया

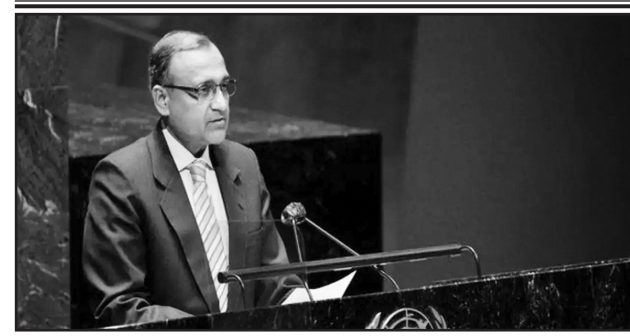

- प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है।
- 11 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव पारित किया।
- यह संयुक्त राष्ट्र से हिंदी सहित अधिकृत और अनधिकृत भाषाओं में संचार और संदेशों का प्रसार जारी रखने का आग्रह करता है।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि पहली बार इस तरह के प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है।
- इसके अतिरिक्त बंगाली और उर्दू भाषा का भी प्रस्ताव में पहली बार उल्लेख हुआ है।

इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड को यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया

- इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड अगले वर्ष 1 जनवरी को भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे।
- इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड को दो साल के कार्यकाल 2023-24 के लिए चुना गया है।
- एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होगा।
- अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात यूएनएससी के अन्य गैर-स्थायी सदस्य हैं।
- स्विट्जरलैंड (187 वोट) और माल्टा (185 वोट) पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों की श्रेणी की सीटों से चुने गए।

- मोजाम्बिक (192 वोट) और जापान (184 वोट) लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों की श्रेणी से चुने गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)

- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- इसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
- मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
- इसमें कुल 15 सदस्य हैं जिनमें 10 स्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य हैं।

'भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030' के लिए संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर

- इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- यह पारस्परिक रूप से लाभकारी लॉजिस्टिक समर्थन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह वियतनाम द्वारा किसी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला ऐसा बड़ा समझौता है।
- दोनों देश वियतनाम के लिए 500 मिलियन डॉलर की रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत हुए।
- भारत ने वायु सेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में भाषा और सूचना प्रोद्योगिकी लैब की स्थापना के लिए दो सिमुलेटर तथा मौद्रिक अनुदान देने की भी घोषणा की।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में अपने वियतनामी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की।
- भारत और वियतनाम 2016 से व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।
- वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है।

बिम्सटेक ने ढाका में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया

- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया देशों के बीच दोस्ती के सेतु का काम करती है।
- 6 जून को ढाका में बिम्सटेक का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया।
- ढाका में बिम्सटेक सचिवालय की स्थापना और 5वें शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक चार्टर को अपनाना बिम्सटेक की प्रमुख उपलब्धि है।

बिम्सटेक

- यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्सटेक के सदस्य हैं।
- इसका गठन 6 जून 1997 को हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।

संयुक्त राष्ट्र तुर्की का आधिकारिक नाम बदलकर 'तुर्किये' करने पर सहमत हुआ

- संयुक्त राष्ट्र में तुर्की को तुर्किये के नाम से जाना जाएगा।
- नाम में परिवर्तन की संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति से अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा तुर्की के नए नाम को अपनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
- तुर्की का नाम बदलने की प्रक्रिया पिछले साल शुरू की गई थी।
- वहां के नागरिक इसे तुर्किये कहते हैं, लेकिन इसके अंग्रेजी संस्करण 'तुर्की' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था।
- 'तुर्की' शब्द का प्रयोग एक बड़े पक्षी के लिए भी किया जाता है जिसे उत्तरी अमेरिका में थैंक्सगिविंग और क्रिसमस भोजन के लिए परोसा जाता है।
- सरकार 'तुर्की' शब्द के लिए गूगल खोज परिणामों से खुश नहीं थी। इसने कैम्ब्रिज डिक्शनरी की "तुर्की" शब्द की परिभाषा पर भी आपत्ति जताई है।
- तुर्किये शब्द तुर्की लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक का प्रतिनिधित्व करेगा

- ब्रिक्स व्यापार फोरम को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लिखित किया कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कुल 2.5 ट्रिलियन डॉलर की क्षमता है।
- साथ ही, भारत ड्रोन, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में नवाचार का समर्थन करता है।

14वां ब्रिक्स सम्मेलन

- चीन में 23 जून से 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है।
- दो दिन की इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग की स्थिति और उनकी संभावनाओं पर विमर्श करेंगे।
- वर्तमान अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों की समीक्षा करने की भी योजना है।
- ज्ञातव्य है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

14वां ब्रिक्स सम्मेलन और भारत

- विदेश मंत्रालय के अनुसार, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा 24 जून को मेहमान देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्चस्तरीय संवाद में भी हिस्सा लेंगे।

13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

- 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पिछली बार भारत में हुआ था।
- विदित है कि 2012 और 2016 के बाद तीसरी बार भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।

ब्रिक्स व्यापार फोरम में भारत के संबोधन के मुख्य अंश

- भारत की सफलता का आधार नवाचार और स्टार्टअप्स के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का विकास भी है।
- अंतरिक्ष, नीली अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा, ड्रोन और भू-स्थानिक डेटा जैसे क्षेत्रों में उभरते नए भारत में हर क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कुल 2.5 ट्रिलियन डॉलर की क्षमता है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में नवाचार समर्थन का उल्लेख किया गया

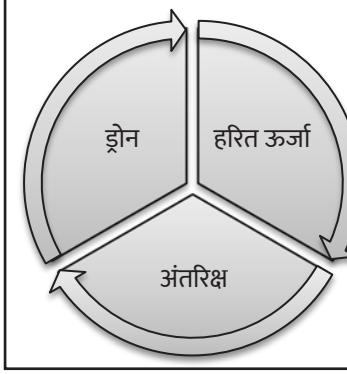

- भारत में जो डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, वह विश्व मंच पर पहले कभी नहीं देखा गया।
- भारत में 70,000 से अधिक स्टार्ट-अप में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
- नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश के अवसर हैं।
- भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य 2025 तक $ 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा।
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम के जरिये आधारभूत संरचना को तैयार करने और डिजिटल सुधार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण का कार्य पूरा किया गया।
- महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने सुधार कार्य और परिवर्तन जैसे तरीकों का प्रयोग किया। यह भारत की आर्थिक सोच का परिणाम है।
- ध्यातव्य है कि ब्रिक्स संगठन की स्थापना इस विश्वास के साथ की गई थी कि ये समूह वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन होगा। आज जब पूरा विश्व कोविड के बाद की स्थिति को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किए हुए है, ऐसी स्थिति में ब्रिक्स में शामिल देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।

ब्रिक्स

क्या है?

- ब्रिक्स को विश्व की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन के रूप में जाना जाता है।
- यह विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में विदित है।

सदस्य देश

- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका

पृष्ठभूमि

- ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी।
- विदित है कि प्रारम्भ में इसमें चार देश (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) शामिल थे और इसका नाम ब्रिक (BRIC) था।
- वर्ष 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम BRIC से बदलकर BRICS हो गया।
- वर्ष 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022

- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दुनिया का 'सबसे अच्छा रहने योग्य' शहर बन गया है।
- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में, वियना ने ऑकलैंड से पहला स्थान छीन लिया, जो कोरोनोवायरस महामारी प्रतिबंधों के कारण 34 वें स्थान पर आ गया है।
- डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और स्विट्जरलैंड का जूरिक क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- कैलगरी भी तीसरे स्थान पर है, उसके बाद वैंकूवर और जिनेवा है।
- इस रैंकिंग में यूरोप के छह शहर टॉप-10 में हैं। ओसाका और मेलबर्न 10वें स्थान पर हैं।
- भारत की राजधानी नई दिल्ली को सबसे अच्छा रहने योग्य शहरों की सूची में 112वें स्थान पर रखा गया है, जबकि मुंबई 117वें स्थान पर है।
- कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के 'सबसे कम रहने योग्य' शहरों में से हैं।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022

- इसने 173 शहरों को रैंकिंग दी है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है।
- यह स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, शिक्षा और स्थिरता सहित विभिन्न कारकों पर आधारित है।

स्थान	शहर
1st	वियना, ऑस्ट्रिया
2nd	कोपेनहेगन, डेनमार्क
3rd	ज़्यूरिख़, स्विट्जरलैंड और कैलगरी, कनाडा
112th	नई दिल्ली, भारत
117th	मुंबई, भारत

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की रिपोर्ट: 'गोल्ड रिफाइनिंग एंड रीसाइक्लिंग'

- भारत ने 2021 में 75 टन सोने का पुनर्चक्रण (रीसाइकिल) किया, भारत सोने को रिसाइकिल करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है । डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट 'गोल्ड रिफाइनिंग एंड रीसाइक्लिंग' के अनुसार चीन दुनिया में सबसे अधिक सोने का रीसाइकिल करता है।
- चीन ने 168 टन सोने का पुनर्चक्रण (रीसाइकिल) किया। चीन के बाद इटली है, जो 80 टन सोने के रीसाइकिल के साथ दूसरे स्थान पर है।
- 2021 में 78 टन सोने के रीसाइकिल के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत की गोल्ड रिफाइनिंग क्षमता में 1,500 टन (500%) की वृद्धि हुई, जो 2013 में 300 टन थी।
- रिपोर्ट के मुताबिक सोने की औपचारिक रिफाइनिंग का पैमाना बढ़ा है और असंगठित रिफाइनिंग का पैमाना गिर गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल आयात में सोने के डोर की हिस्सेदारी 2013 में 7% से बढ़कर 2021 में लगभग 22% हो गई है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सोने की वैश्विक स्क्रैप आपूर्ति का लगभग 8% रीसाइकिल करता है।

मई 2022 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त) 24% बढ़ा

- मई 2022 में, भारत का कुल निर्यात 62.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- मई 2022 में, भारत का व्यापारिक निर्यात 38.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मई 2021 में यह 32.30 अरब डॉलर था।

- वस्तुओं के निर्यात में 20% की वृद्धि हुई। सेवा निर्यात में 30% की वृद्धि हुई।
- मई 2022 में, सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 23.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मई 2021 में यह 17.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- अप्रैल-मई 2022 में, भारत का कुल निर्यात 124.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- इसी अवधि के लिए व्यापारिक निर्यात 78.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- इसी अवधि के लिए सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 45.87 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- मई 2022 में कुल आयात 77.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। वे 59.19% बढ़े।
- अप्रैल-मई 2022 में कुल आयात 151.89 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना

- रूस ने हाल ही में सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। मई 2022 में इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा।
- सऊदी अरब अब भारत को तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- भारतीय रिफाइनर ने मई में रूस से अपने सभी तेल आयात का 16% से अधिक खरीदा।
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला और खपत करने वाला देश है।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। यह अपनी खपत की आवश्यकता का 85% से अधिक आयात करता है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'स्टार्टअप फॉर रेलवे' नामक एक अभिनव नीति शुरू की

- स्टार्टअप फॉर रेलवे नीति का उद्देश्य एक बड़े और कम सेवा वाले स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की मदद से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्रों में पैमाने और दक्षता में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों को परिचालन दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए विचारों के साथ आने के लिए प्रेरित करना है।
- इनोवेटर अब भारतीय रेलवे की इनोवेशन पॉलिसी के अनुसार, मील के पत्थर के भुगतान के प्रावधान के साथ, समान-साझाकरण आधार पर 1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

- इस नीति के तहत, नवप्रवर्तक का चयन एक पारदर्शी और निष्पक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाएगा, जिसे नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन पोर्टल - इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने पीएलएफएस चौथी वार्षिक रिपोर्ट जारी की

- जुलाई 2020 से जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की वार्षिक रिपोर्ट में बेरोजगारी दर, सामान्य स्थिति के अनुसार, 2019-20 में 4.8% से घटकर अब 4.2% हो गई।
- 14 जून 2022 को जारी एनएसओ के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों की तुलना में जुलाई 2020-जून 2021 में श्रम संकेतकों में तेज, सर्वांगीण सुधार दर्ज किया गया है।

- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार, 2020-21 में बेरोजगारी दर 8.8% से घटकर 7.5% हो गई।
- 2020-21 में 4.2% की बेरोजगारी दर पहले पीएलएफएस के बाद सबसे कम है। 2017-18 में पहले पीएलएफएस ने 6.1% की बेरोजगारी दर दिखाई थी।

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2020-21 में चार साल में सबसे अधिक 39.3% थी। 2020-21 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 36.3% है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं (2.1%) की तुलना में पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर (3.9%) अधिक थी।
- शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर (8.6%) पुरुषों (6.1%) की तुलना में अधिक थी।
- जबकि समग्र रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ, कम गुणवत्ता वाले, अवैतनिक कार्य में वृद्धि हुई।
- 2020-21 में अवैतनिक स्वरोजगार श्रेणी में 17.3% और ग्रामीण अवैतनिक रोजगार में 2020-21 में 21.3% की वृद्धि हुई।
- पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार, कृषि में लगे श्रम बल की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़ती रही। यह बढ़कर 46.5% हो गई।
- कृषि रोजगार के हिस्से में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के लिए अधिक दर्ज की गई।

पीएलएफएस के बारे में

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू किया।
- जुलाई 2017- जून 2018, जुलाई 2018-जून 2019 और जुलाई 2019-जून 2020 के दौरान पीएलएफएस में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तीन वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट जारी की गईं।

फिच रेटिंग्स ने भारत के रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव में बदला

- फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023 के लिए आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.8% कर दिया है। इसने मार्च में आर्थिक विकास दर 8.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।
- आउटलुक में नेगेटिव से स्टेबल में बदलाव का मतलब है कि भारत की तेजी से आर्थिक सुधार के कारण मध्यम अवधि के विकास में गिरावट का जोखिम कम हो गया है।
- जून 2020 में, फिच रेटिंग्स ने भारत के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव में बदल दिया था।
- फिच रेटिंग्स ने रेटिंग को BBB- पर अपरिवर्तित रखा है। अगस्त 2006 से भारत की रेटिंग BBB- बनी हुई है।
- इसने FY24 और FY27 के बीच लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- इसने 2020-21 में 87.6% से चालू वित्त वर्ष में ऋण-से-जीडीपी अनुपात घटकर 83% होने का अनुमान लगाया है।

पीएसबी के लिए ईज़ 5.0 (EASE 5.0) 'कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा' निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया

- विदित है कि वित्त वर्ष 19 से 22 तक एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE) के चार संस्करण लॉन्च किए जा चुके हैं।
- ईज़नेक्स्ट कार्यक्रम का ईज़ 5.0 'सामान्य सुधार एजेंडा' सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विकसित किया गया है और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
- पीएसबी मंथन अप्रैल 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यात्मक प्रमुखों के साथ आयोजित किया गया था, जिसने एक व्यापक और साहसिक कार्यक्रम ईज़नेक्स्ट की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया।
- ईज़नेक्स्ट में 2 प्रमुख पहलें शामिल होंगी- ईज़ 5.0 (सामान्य पीएसबी सुधार एजेंडा) और बैंक विशिष्ट रणनीतिक 3-वर्षीय रोडमैप (व्यक्तिगत बैंक की व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर)।
- पीएसबी अगली पीढ़ी की क्षमताओं में निवेश करना जारी रखेंगे और ग्राहकों की बदलती जरूरतों, प्रतिस्पर्धा और तकनीकी वातावरण के लिए ईज़ 5.0 के तहत चल रहे सुधारों को बेहतर करेंगे।
- ईज़ 5.0 का फोकस डिजिटल ग्राहक अनुभव के साथ-साथ एकीकृत और समावेशी बैंकिंग पर होगा।

एनएचएआई ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

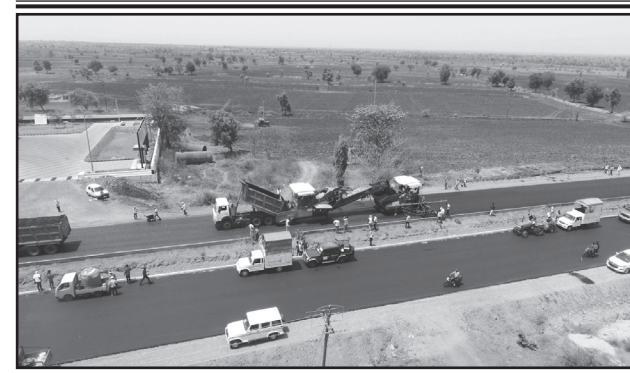

- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि एनएचएआई ने NH53 पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किमी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

- अमरावती से अकोला जिलों के बीच 75 किलोमीटर लंबा सिंगल लेन राजमार्ग बनाया गया है।
- परियोजना को स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों द्वारा कार्यान्वित किया गया।
- इससे पहले, सबसे लंबी बिटुमिनस सड़क के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड कतर ने फरवरी 2019 में बनाया था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

- यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- अलका उपाध्याय एनएचएआई की वर्तमान अध्यक्ष हैं।

भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रैंक में एक स्थान का सुधार

- अंकटाड (UNCTAD) द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से एक है।
- अंतर्वाह में गिरावट के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में भारत सातवें स्थान पर है।
- भारत का एफडीआई प्रवाह 2020 में 64 अरब डॉलर से घटकर 2021 में 45 अरब डॉलर हो गया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (367 अरब डॉलर) एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा। चीन (181 अरब डॉलर) और हांगकांग (141 अरब डॉलर) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

- 2021 में भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्वाह 43 प्रतिशत बढ़कर 15.5 बिलियन डॉलर हो गया है।
- भारत में, 2021 में 108 नई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं की घोषणा की गई। परियोजनाओं की सबसे बड़ी संख्या (23) अक्षय ऊर्जा में थी।
- अंकटाड ने कहा कि वैश्विक एफडीआई प्रवाह 2021 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर के महामारी पूर्व स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इस साल संभावनाएं विकट हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एफएसएसएआई का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्ष 2021-22 की रैंकिंग के आधार पर विजेता राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को सम्मानित किया।

- बड़े राज्यों में, तमिलनाडु इस सूची में पहले स्थान पर रहा, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान रहा।
- छोटे राज्यों में, गोवा इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम हैं।
- केंद्र-शासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने पहली, दूसरी और तीसरी रैंक हासिल की।
- एफएसएसएआई का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक खाद्य सुरक्षा के पांच मानकों में राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2018-19 में शुरू किया गया था।

पांच पैरामीटर हैं:

- मानव संसाधन और संस्थागत डेटा (20% वेटेज)
- अनुपालन (30% वेटेज)
- खाद्य परीक्षण- अवसंरचना और निगरानी (20% वेटेज)
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (10% वेटेज)
- उपभोक्ता अधिकारिता (20% वेटेज)

एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट प्रकार का सौर संयंत्र मारुती सुजुकी द्वारा अपनी मानेसर सुविधा में स्थापित किया गया

- मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित संयंत्र में 20 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता है।
- 2020 में, कंपनी ने अपने गुरुग्राम कारखाने में 5 मेगावाट कारपोर्ट स्टाइल फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया था।
- मानेसर सुविधा में सौर संयंत्र के साथ, मारुती सुजुकी की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता, इसके संयंत्रों में, 26.3 मेगावाट है।

नोट

- विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जोधपुर में स्थित भादला सोलर पार्क है।

- लुधियाना में सीएसआईआर-सीएमईआरआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मशीनरी में स्थापित सोलर ट्री दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% किया

- भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4.40% से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वित्तीय वर्ष 23 जीडीपी विकास अनुमान को 7.2% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया।
- स्थायी जमा सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा दरों में भी 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई है।
- वर्तमान में, स्थायी जमा सुविधा दर 4.65% है और सीमांत स्थायी सुविधा दर 5.15 प्रतिशत है।
- वित्तीय वर्ष 23 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के 5.7 प्रतिशत से संशोधित कर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है।

आरबीआई की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा के अन्य मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

- क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जाएगा। सबसे पहले रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जाएगा।
- सहकारी बैंकों के आवास ऋण की सीमा दोगुनी कर दी गई है।
- शहरी सहकारी बैंकों को डोर-स्टेप बैंकिंग की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

आईआईएम अहमदाबाद ने छह राज्यों के लिए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक (ALPI) लॉन्च किया

- एएलपीआई भारत का अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है। इस सूचकांक के अनुसार, कर्नाटक में कृषि भूमि सबसे महंगी है और उसके बाद तेलंगाना का स्थान है।
- इसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 107 जिलों के लिए विकसित किया गया है।
- सूचकांक का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि मूल्यांकन में अनिश्चितता को दूर करना है।
- इसे आईआईएम-अहमदाबाद द्वारा डिजिटल कृषि-भूमि बाज़ार एसफार्म्सइंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
- यह भूमि की कीमतों की गणना में एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करेगा और कृषि भूमि को रियल एस्टेट या औद्योगिक उपयोग में बदलने में मदद करेगा।
- इस सूचकांक के अनुसार, छह राज्यों के 34 जिलों को 'सबसे महंगा' माना गया, जबकि 32 जिलों को 'माध्य' माना गया और 41 जिलों को 'सबसे कम महंगा' श्रेणी में रखा गया।
- इस सूचकांक के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृषि भूमि की कीमत क्रमश: 0.93 करोड़ रुपये, 0.81 करोड़ रुपये और 0.77 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है।

वित्त वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.7 फ़ीसदी तक कम हुआ

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.7% था, जबकि संशोधित बजट अनुमान 6.9% था।
- फरवरी में, वित्त मंत्रालय ने 15,91,089 करोड़ रुपये या जीडीपी के 6.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया था।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 17.65 ट्रिलियन रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) के मुकाबले कर प्राप्तियां 18.2 ट्रिलियन रुपये थीं।
- वित्त वर्ष 2022 के लिए, राजस्व प्राप्तियां 21.68 लाख करोड़ या संशोधित अनुमान का 104.3% थी।
- कुल खर्च 37.9 लाख करोड़ रुपये या संशोधित अनुमान का 100.6% अनुमानित था।
- सरकार विनिवेश से प्राप्तियों के लक्ष्य से चूक गई।
- सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.4 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है।
- राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर है। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को बाजार उधार से पूरा करती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी 4.1% की दर से बढ़ी

- वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत की जीडीपी 8.7% की दर से बढ़ी। यह फरवरी में अनुमानित 8.9% से थोड़ा कम है।
- जनवरी-मार्च तिमाही के लिए जीडीपी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए दर्ज 5.4 फीसदी जीडीपी दर से कम थी।
- आठ प्रमुख क्षेत्रों में, एकमात्र क्षेत्र जिसने जनवरी-मार्च तिमाही में संकुचन दिखाया है, वह विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) है। इसने -0.2% पर संकुचन दिखाया है।
- वित्त वर्ष 2012 की चौथी तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय में सालाना आधार पर 1.8% की वृद्धि हुई।
- सकल अचल पूंजी निर्माण में 5.1% की वृद्धि हुई। सरकार का अंतिम उपभोग व्यय जनवरी-मार्च में 4.8 फीसदी की दर से बढ़ा।
- वित्त वर्ष 22 के लिए सकल मूल्य वर्धन में 8.1% की वृद्धि हुई। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में 19.5% की वृद्धि हुई।

भारत की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में पूर्व-कोविड स्तर से नीचे बनी हुई है

- 2021-22 में, स्थिर कीमतों पर भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 91,481 रुपये थी।
- स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में 94,270 रुपये और 2020-21 में 85,110 रुपये थी।
- स्थिर मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय (एनएनआई) पर आधारित प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 22 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
- 2021-22 के वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर 18.3 प्रतिशत बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गई है।
- मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में 1.32 लाख रुपये से घटकर 2020-21 में 1.27 लाख रुपये हो गई।
- कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया था।
- प्रति व्यक्ति आय एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन है। यह किसी देश की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

सरकार ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा

- कोयला मंत्रालय ने बिजली मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन विश्व खनन कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा किया गया था।
- कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज़ तैयार किया है।
- कोयले को जलाने की तुलना में कोयला गैसीकरण अपेक्षाकृत स्वच्छ विकल्प है। यह कोयले के रासायनिक गुणों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- रिफाइनरियों और उर्वरक संयंत्रों के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन वर्तमान में प्राकृतिक गैस से किया जाता है, जिसे कोयले के माध्यम से कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जा सकता है।
- कोयला गैसीकरण कोयले को सिंथेसिस गैस (सिनगैस) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो हाइड्रोजन (H2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का मिश्रण है।
- सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है।

पीएमईजीपी योजना 13,554 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 26 तक बढ़ा दी गई

- सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
- अगले पांच वर्षों में यह योजना लगभग 40 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

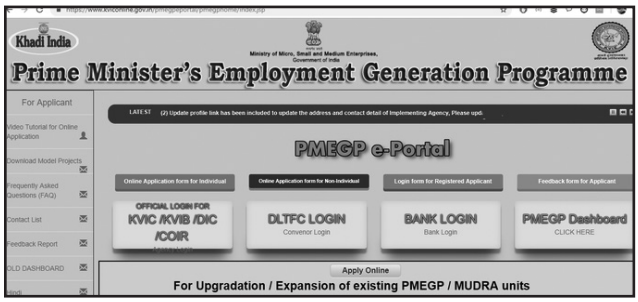

- पीएमईजीपी योजना युवाओं को गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में भी मदद करेगी।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा भी बदल दी गई है।
- पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा, जबकि नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा।
- आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर के आवेदकों को विशेष श्रेणी के आवेदकों के रूप में माना जाएगा और उन्हें अधिक सब्सिडी मिलेगी।
- इसके तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपये कर दी गई है, जो पहले 25 लाख रुपये थी। सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए इसे 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
- इसकी शुरुआत के बाद से, लगभग 7.8 लाख सूक्ष्म उद्यमों को पीएमईजीपी के तहत वित्तीय सहायता मिली है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:

- यह 2008 में शुरू की गई एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है।
- इसे दो योजनाओं- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) को मिलाकर शुरू किया गया था।

आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई के आईटी संसाधन 'महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' घोषित

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने 16 जून को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार, "महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना" को "कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा"।
- सरकार डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी डेटा, डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के रूप में घोषित कर सकती है।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी है। इसका गठन 2014 में हुआ था।
- सीआईआई को अनधिकृत पहुंच, संशोधन, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान और अक्षमता से बचाया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह कानून का उल्लंघन करता है। उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी।

- सरकार ने 2022 के अंत तक कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है।
- वर्तमान में, ईएसआई योजना पूरी तरह से 443 जिलों में लागू है और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है। लगभग 148 जिले ईएसआई योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- ईएसआई कॉर्पोरेशन ने देश भर में 23 नए 100-बेड वाले अस्पताल और 62 औषधालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में 48, दिल्ली में 12 और हरियाणा में 2 डिस्पेंसरी खुलेंगी।
- ईएसआई कॉर्पोरेशन ने अपने मेडिकल कॉलेजों में हेल्थ केयर लिंक वर्कर्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का भी फैसला किया है।
- सनथनगर, तेलंगाना और अलवर, राजस्थान में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो कैथ लैब भी स्थापित किए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

- इसकी स्थापना 1952 में हुई थी।
- यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- यह ईएसआई योजना के कार्यान्वयन के लिए ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत स्थापित किया गया था।
- मुखमीत एस भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के महानिदेशक हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में प्रवास 2020-21 रिपोर्ट जारी की

- प्रवासन पहलुओं पर जुलाई 2020-जून 2021 के दौरान पीएलएफएस में एकत्र की गई जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गयी है। इस रिपोर्ट में 'प्रवासियों' और 'अस्थायी आगंतुकों' की श्रेणियों को अलग किया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5% और शहरी क्षेत्रों में 34.9% प्रवास के साथ अखिल भारतीय प्रवासन दर 28.9% थी।
- कुल महिला प्रवासन दर (47.9%), पुरुषों (10.7%) की तुलना में अधिक है। महिला प्रवासन की उच्च दर का कारण मुख्य रूप से विवाह (प्रवास के 86.8% मामलों में) है।
- 42.9% पुरुष रोजगार/बेहतर रोजगार की तलाश में या रोजगार लेने/बेहतर रोजगार/व्यवसाय/कार्यस्थल से निकटता/स्थानांतरण के लिए पलायन कर गए।
- भारत की आबादी का 0.7 प्रतिशत घरों में 'अस्थायी आगंतुक' के रूप में दर्ज किया गया था। इनमें से 84% अस्थायी आगंतुक COVID-19 महामारी से संबंधित कारणों जैसे परिवार/रिश्तेदारों से मिलना, नौकरी छूटना/इकाई बंद होना/रोजगार की कमी, कमाई करने वाले सदस्य का प्रवास, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना आदि के कारण स्थानांतरित हो गए।

रिपोर्ट में परिभाषित धारणात्मक ढांचा

- सामान्य निवास स्थान (UPR): यह वह स्थान (गांव/कस्बा) है जहां व्यक्ति कम से कम छह महीने से लगातार रह रहा है या सर्वेक्षण के दौरान वहां छह महीने या उससे अधिक समय तक लगातार रहने के इरादे से वहां रह रहा है। तब वह स्थान उसकी यूपीआर के रूप में दर्ज था।
- प्रवासी: एक घर का सदस्य जिसका किसी भी समय अंतिम सामान्य निवास स्थान गणना के वर्तमान स्थान से अलग था, एक घर में प्रवासी सदस्य माना गया।
- प्रवास दर: किसी भी श्रेणी के व्यक्ति (जैसे ग्रामीण या शहरी, पुरुष या महिला) के लिए प्रवासन दर, उस श्रेणी के व्यक्तियों से संबंधित प्रवासियों का प्रतिशत है।
- अस्थायी आगंतुक: वे व्यक्ति जो मार्च 2020 के बाद आए और लगातार 15 दिनों या उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम की अवधि के लिए घर में रहे। अस्थायी आगुंतकों से सम्बंधित अनुमान उन लोगों से संबंधित हैं जिनके लिए वर्तमान निवास स्थान जहां वह रह रहे थे अस्थायी रूप से उनके सामान्य निवास स्थान (यूपीआर) से भिन्न थे।

विज्ञान एवं तकनीकी

इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम 'सूर्य नूतन'

- इंडियन ऑयल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम 'सूर्य नूतन' विकसित किया है।
- इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम 'सूर्य नूतन' सूर्य ऊर्जा एकत्र करती है और इसे विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ताप तत्व की सहायता से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
- सिस्टम को परीक्षण के लिए 60 स्थानों पर स्थापित किया गया है। यह एक स्थिर, रिचार्जेबल और हमेशा रसोई से जुड़ा इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है।
- यह हाइब्रिड मोड में काम कर सकता है और एक साथ सौर और एक सहायक ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकता है। यह हर मौसम में काम कर सकता है।
- कई दिनों तक सूरज न दिखने पर भी 'सूर्य नूतन' कुकटॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC):** यह एक महारत्न पीएसयू है जिसका गठन 1959 में किया गया था। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है।

दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट के साथ अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया

- दक्षिण कोरिया ने अपने पहले घर में विकसित नूरी रॉकेट की मदद से एक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
- दक्षिण कोरिया अपनी तकनीक से उपग्रह को कक्षा में पहुंचाने वाला 10वां देश बन गया है।
- कोरियाई उपग्रह लॉन्च व्हीकल II, जिसे नूरी के नाम से जाना जाता है, ने 21 जून को नारो स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी।
- तीन चरणों वाले रॉकेट ने उपग्रह को लक्ष्य की ऊंचाई पर पहुंचाया और इसने पृथ्वी पर अपनी स्थिति के बारे में संकेत प्रेषित किए।
- यह दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण है। अक्टूबर 2021 में, नूरी वांछित ऊंचाई पर पहुंच गई थी, लेकिन उपग्रह को कक्षा में पहुंचा नहीं सकी थी।
- दक्षिण कोरिया ने 2013 में एक रूसी रॉकेट की मदद से अपनी धरती से अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।

फ्रेंच गयाना के कौरू से जीसैट-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

- जीसैट-24 भारत का संचार उपग्रह है। इसे इसरो ने एनएसआईएल के लिए बनाया है।
- इसे फ्रांस की कंपनी एरियनस्पेस ने लॉन्च किया। यह चार हजार एक सौ अस्सी किलोग्राम वजन वाला 24 केयू बैंड का संचार उपग्रह है, जो पूरे भारत में डीटीएच ऐप की जरूरतें पूरी करेगा।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद एनएसआईएल का यह पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है।
- एनएसआईएल ने समूची उपग्रह क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी है।
- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की एक कंपनी है।

कृषि मंत्री ने जानवरों के लिए देश की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया

- एनोकोवैक्स हरियाणा की एक कंपनी- आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स (NRC) द्वारा विकसित किया गया है।

- एनोकोवैक्स द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा सार्स-सीओवी-2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों संस्करणों को निष्प्रभावी कर देता है।
- वैक्सीन, जो कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है, में निष्क्रिय सार्स-सीओवी-2 (डेल्टा) एंटीजन होता है, जिसमें अलहाइड्रोजेल एक सहायक के रूप में होता है।
- मंत्री ने कैनाइन में सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और विशिष्ट न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन-आधारित अप्रत्यक्ष एलिसा किट 'सीएएन-सीओवी-2 एलिसा किट' भी लॉन्च किया।
- सुर्रा एलिसा किट भी लॉन्च की गई, जो कई जानवरों की प्रजातियों में ट्रिपैनोसोमा इवांसी संक्रमण के लिए एक उपयुक्त नैदानिक जांच है।
- इसके अतिरिक्त, घोड़ों के बीच पितृत्व विश्लेषण के लिए एक इक्वाइन डीएनए पेरेंटेज परीक्षण किट भी लॉन्च किया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर):

- यह कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का उद्घाटन

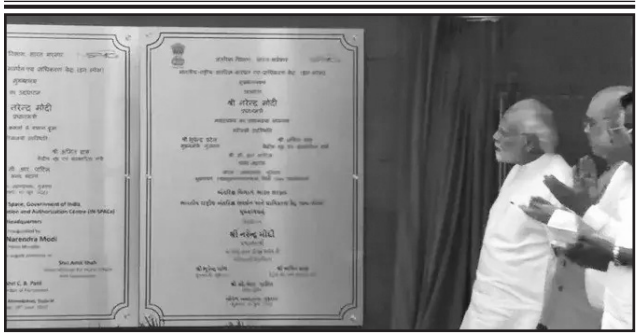

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश और नवाचार को बढ़ावा देगा।
- सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार शुरू किए हैं और इसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है।
- इन-स्पेस गैर-सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष विभाग की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी हितधारकों की अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा।
- पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कुल 10 एमओयू का आदान-प्रदान हुआ।
- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है।

चीन ने चंद्रमा का नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया

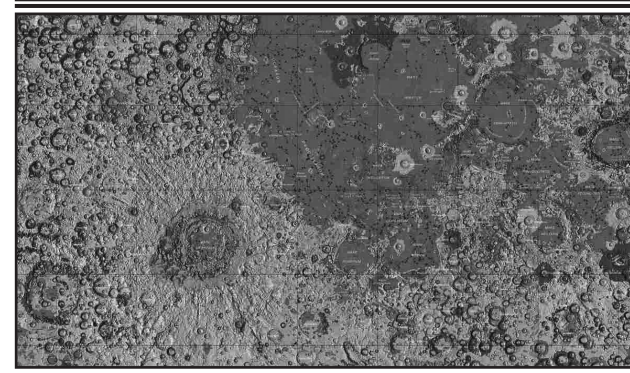

- चीनी वैज्ञानिकों ने चांग'ई परियोजना के आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा का एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया है।
- मानचित्र में 12,341 प्रभाव क्रेटर, 81 प्रभाव बेसिन, 17 चट्टान के प्रकार और 14 प्रकार की संरचनाएं शामिल हैं।
- चंद्रमा का नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र 1:2,500,000 के पैमाने पर आधारित है।
- अन्य संगठनों के साथ मिलकर चीनी विज्ञान अकादमी के भू-रसायन संस्थान ने परियोजना का नेतृत्व किया है।
- नया नक्शा वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण और चंद्रमा पर लैंडिंग साइट चयन में मदद करेगा।
- इससे पहले, यूएसजीएस एस्ट्रोजियोलॉजी साइंस सेंटर ने वर्ष 2020 में 1:5,000,000 के पैमाने पर चंद्रमा का नक्शा जारी किया था।

भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा बेंगलुरु में शुरू की गई

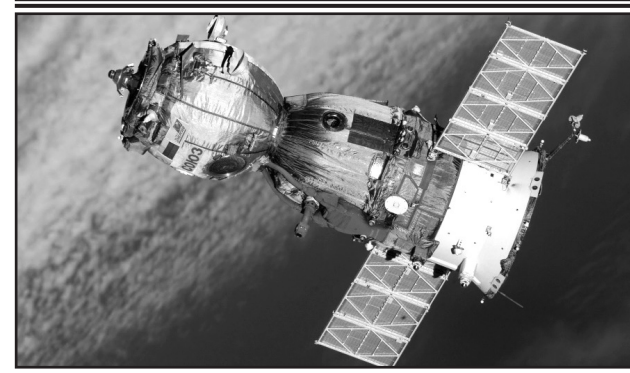

- बेंगलुरु में, भारत में अग्रणी एयरोस्पेस और रक्षा निर्माता अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी निजी अंतरिक्ष यान उत्पादन सुविधा शुरू की है।
- लॉन्च की गई अंतरिक्ष यान उत्पादन सुविधा भारत में निजी अंतरिक्ष यान निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी।

- 15,000 वर्गमीटर की सुविधा के भीतर मौजूद चार स्वतंत्र मॉड्यूल के साथ एक ही समय में चार अंतरिक्ष यान को असेंबल, एकीकृत और परीक्षण किया जा सकता है।
- यह सुविधा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के एयरोस्पेस पार्क में स्थित है।
- सुविधा के चार घटक स्व-निहित हैं और चार अलग-अलग अंतरिक्ष यान वर्गों में एंड-टू-एंड प्रक्रिया एकीकरण को पूरा करने में सक्षम हैं।

अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड:

- 1992 में, एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अनंत की स्थापना की गई थी।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।
- इसके अध्यक्ष और एमडी डॉ. सुब्बा राव पावुलुरी हैं।

भारत में एक नई टेलिस्कोप सुविधा सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्रग्रह जैसी वस्तुओं की पहचान करने में मदद करेगी

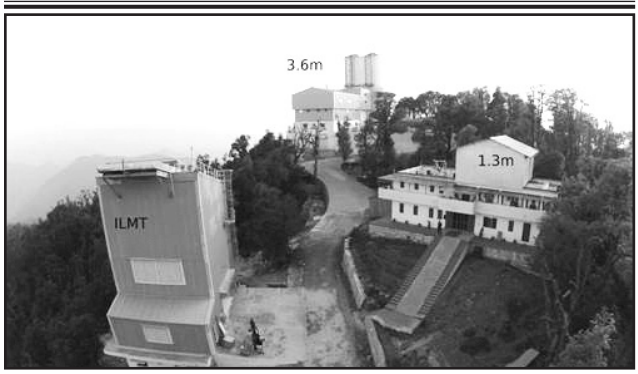

- टेलिस्कोप उत्तराखंड की एक पहाड़ी देवस्थल में लगाया गया है।
- यह भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर (तरल दर्पण) टेलिस्कोप है।
- इसे भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों ने बनाया है।
- इसमें एक 4-मीटर-व्यास का घूर्णन दर्पण लगा हुआ है, जो प्रकाश को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए तरल पारा की एक पतली फिल्म से बना हुआ है।
- तरल पारा दर्पण एक पतली माइलर फिल्म से ढका होता है। मायलर की एक पतली पारदर्शी फिल्म पारा को हवा से बचाती है।
- इंटरनेशनल लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप (आईएलएमटी) उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के देवस्थल वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
- आईएलएमटी को बेल्जियम में एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स (एएमओएस) कॉर्पोरेशन और सेंटर स्पैटियल डी लीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था।
- एएमओएस अक्टूबर 2022 में पूर्ण पैमाने पर वैज्ञानिक संचालन शुरू करने के लिए तैयार होगा।

दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना 'फ्रंटियर'

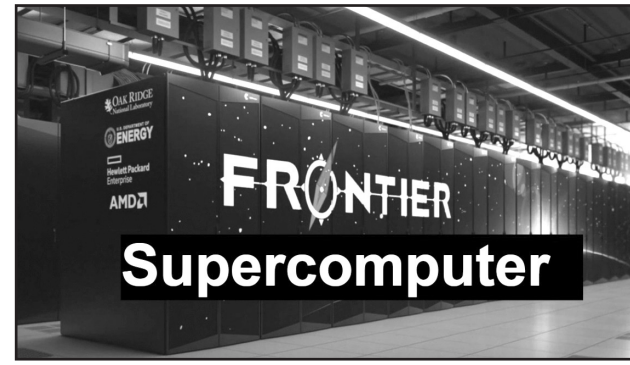

- यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया 'फ्रंटियर' सुपरकंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर बन गया है।
- इसने रिकेन और फुजित्सु लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर 'फुगाकू' की जगह ली है।
- फ्रंटियर सुपरकंप्यूटर हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज (एचपीई) आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है और उन्नत माइक्रो डिवाइस (एएमडी) प्रोसेसर से लैस है।
- यह एक अभूतपूर्व स्तर के कंप्यूटिंग प्रदर्शन को हासिल करने वाला पहला है जिसे एक्सास्केल के रूप में जाना जाता है।
- फ्रंटियर सुपरकंप्यूटर 1.1 एक्साफ्लॉप प्रदर्शन के साथ दुनिया में सबसे तेज है।
- सुपर कंप्यूटर सबसे पहले कोड क्रैक करने और हथियार डिजाइन करने के लिए बनाए गए थे। इसने टीके विकसित करने, कार डिजाइनों के परीक्षण और जलवायु परिवर्तन के मॉडलिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए जैव विविधता नीति

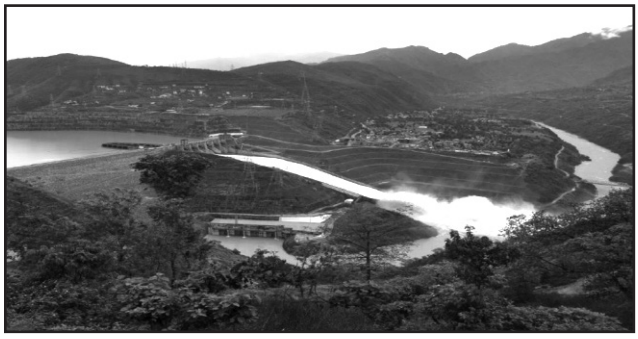

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी ने जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए जैव विविधता नीति जारी की।

जैव विविधता नीति 2022

- यह जैव विविधता नीति एनटीपीसी की पर्यावरण नीति का एक अभिन्न अंग है।
- यह जैव विविधता के संरक्षण, उद्धार और वृद्धि के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने में सहायक होगा।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण और स्थिरता नीतियों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, इस नीति को एनटीपीसी समूह के सभी पेशेवरों को इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करने में मदद करने के लिए भी तैयार किया गया है।
- इसके अलावा इस नीति को एनटीपीसी समूह के सभी पेशेवरों को इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करने में मदद करने के लिए भी तैयार किया गया है।

पृष्ठभूमि

- प्रमुख ऊर्जा उत्पादक एनटीपीसी का उद्देश्य अपनी मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्यधारा में लाना है।
- यह एनटीपीसी की व्यावसायिक इकाइयों और उसके आस-पास पृथ्वी की विविधता को सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन के लिए एक सार्थक और प्रभावी दृष्टिकोण को आत्मसात करना है।
- इस नीति का उद्देश्य कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों से अलग हटकर जैव विविधता के लिए स्थानीय खतरों के व्यवस्थित विचार को अपनाना भी है।
- एनटीपीसी 2018 में जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम था। उसी वर्ष एनटीपीसी, भारत व्यापार और जैव विविधता पहल (आईबीबीआई) का सदस्य बन गया था।
- एनटीपीसी अपनी क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, विशेषज्ञों के सहयोग से परियोजना-विशिष्ट और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के माध्यम से जैव विविधता के बारे में स्थानीय समुदायों, कर्मचारियों और इसके सहयोगियों के बीच जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है।
- एनटीपीसी जैव विविधता के क्षेत्र में स्थानीय समुदायों, संगठनों, नियामक एजेंसियों और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अनुसंधान संस्थानों के साथ भी सहयोग कर रहा है।
- इसके अलावा, एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के दौरान पर्यावरण, वन, वन्यजीव, तटीय क्षेत्र और हरित क्षेत्र से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करके जैव विविधता के संबंध में कानूनी अनुपालन का पालन करेगा।
- एनटीपीसी द्वारा की गई एक बड़ी पहल में कम्पनी ने आंध्र प्रदेश के समुद्र तट में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ पांच वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 4.6 करोड़ रुपये के वित्तीय योगदान और समुदाय की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ एनटीपीसी के हस्तक्षेप के बाद से समुद्र के पानी में हैचिंग की संख्या में लगभग 2.25 गुना वृद्धि हुई है।

भारत व्यापार और जैव विविधता पहल (आईबीबीआई)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार ने वर्ष 2014 को जर्मन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (GIZ) के समर्थन से भारत व्यापार और जैव विविधता पहल (IBBI) की शुरूआत की थी।
- यह जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा "जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDB)" के रूप में मनाया जाता है।
- आईबीबीआई को व्यापार, सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों को शामिल करते हुए एक व्यापक-आधारित बहु-हितधारक पहल के रूप में संरचित किया गया है।
- व्यापार के नेतृत्व वाली यह पहल व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है, यह सीखने को बढ़ावा देने के लिए और अंतत: व्यापार द्वारा जैविक विविधता के स्थायी प्रबंधन को मुख्य धारा में ले जाएगी।
- आईबीबीआई की शुरुआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) , भारत सरकार द्वारा की गई थी
- भारतीय व्यापार संगठनों को जैव विविधता संरक्षण और उनके संचालन से संबंधित सतत उपयोग में, उनकी मूल्य श्रृंखला में और भारत की जैव विविधता के संरक्षण के प्रति संवेदनशील, मार्गदर्शन और सलाह देना है।

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को लेकर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और अनिरुद्ध बोस की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश

दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम से कम एक किमी तक का क्षेत्र अनिवार्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) होना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- यह निर्णय तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वन भूमि की सुरक्षा के लिए दायर एक याचिका पर आया है। इसके बाद, उस रिट याचिका का दायरा अदालत द्वारा बढ़ा दिया गया, ताकि पूरे देश में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके।
- यह निर्णय टीएन गोदावर्मन थिरुमलपद मामले में दायर आवेदनों के संदर्भ में दिया गया।
- आवेदनों का वर्तमान सेट केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी जिसे 2002 में न्यायालय द्वारा गठित किया गया था) द्वारा नवंबर 2003 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ। यह रिपोर्ट विशेष रूप से जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है।
- 20 सितंबर 2012 को सीईसी द्वारा दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें जमुआ रामगढ़ अभयारण्य से आगे निकल गईं और पूरे देश में संरक्षित वनों के आस-पास सुरक्षा क्षेत्रों की पहचान और घोषणा के निर्माण से संबंधित थीं।
- 9 फरवरी 2011 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) की घोषणा के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया गया था

निर्णय

- खनिकों द्वारा दायर आवेदनों के एक सेट में पारित वर्तमान आदेश में, न्यायालय ने कहा कि 9 फरवरी, 2011 को जारी दिशा-निर्देश "उचित" हैं।
- निर्देशों की एक श्रृंखला में, न्यायालय ने कहा कि यदि किसी राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित वन में पहले से ही एक किमी से अधिक का बफर ज़ोन है, तो वह मान्य होगा।
- वहीं यदि बफर जोन की सीमा का प्रश्न वैधानिक निर्णय के लिए लंबित था, तो कानून के तहत अंतिम निर्णय आने तक एक किलोमीटर के सुरक्षा क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अदालत का निर्देश लागू होगा।
- अदालत ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इसने निर्णय के अनुपालन के लिए राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और राज्यों के गृह सचिवों को जिम्मेदार ठहराया।
- प्रत्येक राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य संरक्षक को भी ईएसजेड के भीतर विद्यमान संरचनाओं की एक सूची बनाने और तीन महीने में शीर्ष अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

सतत विकास

- राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करना होगा, ताकि दीर्घकालिक विकास को प्राप्त किया जा सके।
- निर्णय में पीठ ने कहा कि राज्य की इस तरह की भूमिका इतिहास में किसी भी समय संभवतः ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न होने वाली जलवायु तबाही के खतरे के मुकाबले वर्तमान में अधिक प्रासंगिक है।

इको-सेंसिटिव जोन क्या हैं?

- इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र एमओईएफसीसी द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास अधिसूचित क्षेत्र हैं।

उद्देश्य

- ईएसजेड घोषित करने का उद्देश्य क्षेत्र के आस-पास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संरक्षण प्रदान करता है।
- इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने वाले संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
- यह उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

ईएसजेड की सीमा

- वन्यजीव संरक्षण रणनीति, 2002 के अनुरूप ईएसजेड संरक्षित क्षेत्र के आस-पास 10 किलोमीटर की सीमा तक जा सकता है।
- एक विशेष संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में ईएसजेड के एक क्षेत्र का वितरण और विनियमन की सीमा चारों ओर एक समान नहीं हो सकती है और यह परिवर्तनीय चौड़ाई की हो सकती है।

ईएसजेड का महत्व

- ईएसजेड घोषित किए गए क्षेत्र शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करेंगे ।
- यह संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के मूल और बफर मॉडल पर आधारित होते हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय क्षेत्र समुदायों को भी संरक्षित और लाभान्वित किया जाता है।
- यह ईएसजेड इन-सीटू संरक्षण में मदद करते हैं, जो अपने प्राकृतिक आवास में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, उदाहरण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम के एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण।
- इको-सेंसिटिव जोन वनों की कमी और मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं।

ईएसजेड के तहत अनुमति प्राप्त गतिविधियां

- बागवानी प्रथाएँ, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।

निषिद्ध गतिविधियाँ

- वाणिज्यिक खनन, आरा मिल, प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग (वायु, पानी, मिट्टी, शोर आदि), प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं (HEP) की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, अपशिष्टों का निर्वहन या कोई ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन ।

नियमन के तहत गतिविधियाँ

- पेड़ों की कटाई, होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि प्रणाली में व्यापक बदलाव, जैसे उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाना, कीटनाशक का उपयोग आदि।

वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है

- कैरेबियन में एक मैंग्रोव दलदल में विचित्र जीवाणु पाया गया है।
- अजीबोगरीब थियोमार्गरीटा मैग्निफा जीवाणु, जो लगभग 1 सेमी लंबा और किसी भी पहले से ज्ञात विशालकाय बैक्टीरिया से लगभग 50 गुना बड़ा है। नग्न आंखों को दिखाई देने वाला पहला जीवाणु है।
- यह सफेद तंतु के रूप में मानव पलकों के आकार का होता है।
- उथले उष्णकटिबंधीय समुद्री दलदलों में, इन जीवाणुओं को मैंग्रोव पत्तियों के सड़ने की सतह पर खोजा गया।
- इस जीव की खोज यूनिवर्सिटी डेस एंटिल्स में समुद्री जीव विज्ञान के प्रोफेसर ओलिवियर ग्रोस ने की है।

वैज्ञानिकों ने भारतीय जल में पहली बार अजूक्सैन्थेलेट कोरल (azooxanthellate coral) की चार प्रजातियों की खोज की

- ट्रंकैटोफ्लैबेलम क्रैसम, टी इनक्रस्टैटम, टी एक्यूलेटू और टी इरीगुलारे अंडमान और निकोबार द्वीप के पानी में पाए गए अजूक्सैन्थेलेट कोरल (प्रवालभित्तियाँ) की प्रजातियों के नाम हैं।
- अजूक्सैन्थेलेट कोरल अंधेरे स्थानों में पाए जाते हैं और इनमें ज़ोक्सांथेला नहीं होते हैं। ज़ोक्सांथेला एक सूक्ष्म शैवाल है, जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- यह अध्ययन हाल ही में 'थलासस: एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मरीन साइंसेज' में प्रकाशित हुआ था।
- अध्ययन ने फ्लैबेलिड्स की चार प्रजातियों के वैश्विक मानचित्रण के साथ-साथ रूपात्मक विशेषताओं की व्याख्या की है।
- ये सभी चार प्रजातियां जापान से लेकर फिलीपींस तक के पानी में और ऑस्ट्रेलियाई पानी में पाई गईं है।
- इंस्टिट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल रिसर्च एंड सोशल एजुकेशन द्वारा 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, हिंद महासागर क्षेत्र से अजूक्सैन्थेलेट स्क्लेरैक्टिनियन कोरल की 227 प्रजातियों की सूचना मिली है।

भारत में कोरल (प्रवालभित्तियाँ)

- यह सामान्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जलसंधि और लक्षद्वीप द्वीपों में पाया जाता है।
- केरल के कोल्लम से लेकर तमिलनाडु के एनायम पुथेनथुरई तक हर्माटाइपिक कोरल पाए जाते हैं।
- भारत में प्रवाल भित्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,790 वर्ग किमी है।

मंगोलिया के खुव्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया

- मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 34वें सत्र के दौरान खुव्सगुल झील को बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क में जोड़ने का निर्णय लिया गया।
- खुव्सगुल झील मंगोलिया के खुव्सगुल प्रांत में रूसी सीमा के पास स्थित है।
- इसमें मंगोलिया का लगभग 70 प्रतिशत ताजा पानी है और यह समुद्र तल से 1,645 मीटर ऊपर है। यह 136 किमी लंबा और 262 मीटर गहरा है।
- मंगोलिया में कुल नौ स्थल बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के अंतर्गत हैं।

बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क

- यह नामित संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है।
- यह ज्ञान साझा करने, अनुभवों का आदान-प्रदान करने, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड (MSBWL) ने 12 नए संरक्षण रिजर्व और तीन वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी

- वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के लिए महाराष्ट्र में 12 नए संरक्षण रिजर्व और तीन वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी गई है।

- इन संरक्षित क्षेत्रों में लगभग 1,000 वर्ग किमी (संरक्षण रिजर्व के लिए लगभग 692.74 वर्ग किमी और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए 303 वर्ग किमी) शामिल हैं।

12 नए संरक्षण रिजर्व इस प्रकार हैं:

- धुले में चिवटीबावरी और अलादरी
- नासिक में कलवान और मुरगाद
- रायगढ़ जिले में रायगढ़ और रोहा
- पुणे में भोर
- सतारा में डरे खुर्द (महादरे)
- कोल्हापुर में मसाई पठार
- नागपुर में मोगारकासा
- नासिक में त्रयंबकेश्वर
- नासिक में इगतपुरी
- लोनार वन्यजीव अभयारण्य (0.8694 वर्ग किमी), गढ़चिरौली में कोलामार्का (180.72 वर्ग किमी) और जलगांव में मुक्ताई भवानी (122.74 वर्ग किमी) नए वन्यजीव अभयारण्य हैं।
- महाराष्ट्र में कुल 27 संरक्षण रिजर्व हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसार, राज्य में किसी भी संरक्षण क्षेत्र को अधिसूचित करने से पहले वन्यजीव बोर्ड की सहमति आवश्यक है।

मेघालय के री भोई जिले में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है।

- यह नई प्रजाति नोंगखिलेम वन्यजीव अभयारण्य के जंगल में मिली है।
- नई पाई गई प्रजाति का नाम 'ग्लिस्क्रोपस मेघलायनस' रखा गया है।
- यह पहली बार है जब दक्षिण एशिया में मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ मिले है।
- मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ ग्लिस्क्रोपस जीनस के हैं। नई खोजी गई प्रजाति आकार में छोटी है और इसका रंग गहरा भूरा है।
- बाँस में रहने वाले चमगादड़ बाँस के इंटर्नोड्स में रहते हैं।
- भारत में चमगादड़ों की कुल 131 प्रजातियाँ जानी जाती हैं। मेघालय में भारत में चमगादड़ों की विविधता सबसे अधिक है।

अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान सबसे नीचे

- भारत अपनी खराब नीतियों और इसके कार्यान्वयन के कारण पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वें स्थान पर है।
- डेनमार्क सूचकांक में शीर्ष पर है और सबसे सतत देश के रूप में उभर रहा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका सूचकांक में 43वें स्थान पर है।
- सूचकांक ने भविष्यवाणी की कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2050 में चार सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक में से एक होगा। चीन, भारत और रूस अन्य तीन देश होंगे।
- यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क 2050 तक अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर हैं।

TOP 8

Country	Rank	Score	10-yr change
Denmark	1	77.90	14.90
UK	2	77.70	23.00
Finland	3	76.50	21.00
Malta	4	75.20	25.40
Sweden	5	72.70	15.80
Luxembourg	6	72.30	13.50
Slovenia	7	67.30	8.60
Austria	8	66.50	7.20

BOTTOM 8

Country	Rank	Score	10-yr change
Haiti	173	26.10	2.40
Liberia	174	24.90	-4.00
Papua New Guinea	175	24.80	0.20
Pakistan	176	24.60	1.40
Bangladesh	177	23.10	-1.90
Vietnam	178	20.10	-0.60
Myanmar	179	19.40	-3.80
India	**180**	**18.90**	**-0.60**

- येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 40 संकेतकों पर 180 देशों को रैंकिंग देता है।
- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता आदि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मापदंडों में से एक हैं।

दुनिया की पहली फिशिंग कैट की जनगणना चिल्का में हुई

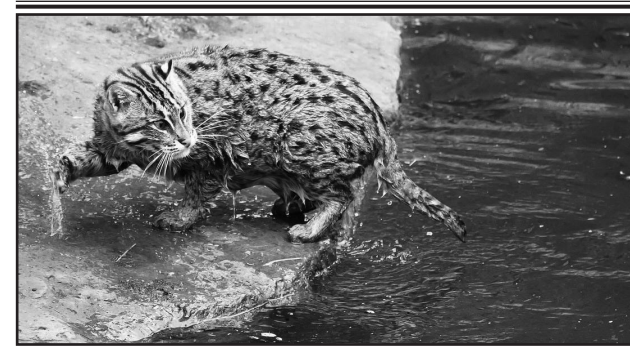

- यह जनगणना चिल्का विकास प्राधिकरण (सीडीए) द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट (टीएफसीपी) के सहयोग से आयोजित की गई है।
- चिल्का झील में 176 फिशिंग कैट हैं और यह फिशिंग कैट की आबादी का पहला अनुमान है।
- चिल्का विकास प्राधिकरण (सीडीए) के अनुसार, जनगणना दो चरणों में आयोजित की गई थी।
- चरण-I का आयोजन 2021 में चिल्का के उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग में किया गया था। दूसरा चरण 2022 में चिल्का के तटीय द्वीपों के किनारे आयोजित किया गया था।

- डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्पैटियल एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर (एसईसीआर) पद्धति का उपयोग किया गया है।
- फिशिंग कैट को विश्व स्तर पर खतरा है और आमतौर पर दलदली भूमि, मैंग्रोव और बाढ़ वाले जंगलों जैसे आर्द्रभूमि में पाई जाती हैं।
- यह पाकिस्तान में सिंधु से लेकर वियतनाम में मेकांग तक 10 एशियाई देशों की प्रमुख नदियों में पाया जाता है।
- द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) जल्द ही फिशिंग कैट एक्शन प्लान लॉन्च करेगी।

पीएम मोदी ने 5 जून 2022 को एक वैश्विक पहल 'पर्यावरणीय जीवनशैली-लाइफ अभियान' की शुरुआत की

- प्रधानमंत्री ने कहा कि 'लाइफ' की परिकल्पना एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए।
- 'लाइफ' का विचार पिछले साल ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-26) के समय पीएम मोदी द्वारा पेश किया गया था।

- यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है जो 'नासमझ और फिजूलखर्ची' के बजाय 'सावधान और जानबूझकर उपयोग' पर केंद्रित है।
- नज थ्योरी के लेखक प्रो. कैस सनस्टीन ने कार्यक्रम में भाग लिया।
- प्रो. कैस सनस्टीन ने व्यवहार परिवर्तन के इएएसटी (EAST) फ्रेमवर्क के बारे में बताया।
- इएएसटी का मतलब इजी (आसान), अट्रैक्टिव (आकर्षक), सोसिअल (सामाजिक) और टाइमली है। उन्होंने इसे एफइएएसटी बनाने के लिए फ्रेमवर्क में एक नया अक्षर 'एफ' जोड़ा। यहाँ एफ से आशय फन (मनोरंजन) से है।

दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया

- विशाल समुद्री घास, एक समुद्री फूल वाला पौधा, जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर खोजा गया।
- इसकी लंबाई 180 किमी है और यह 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह शार्क बे में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा खोजा गया है।

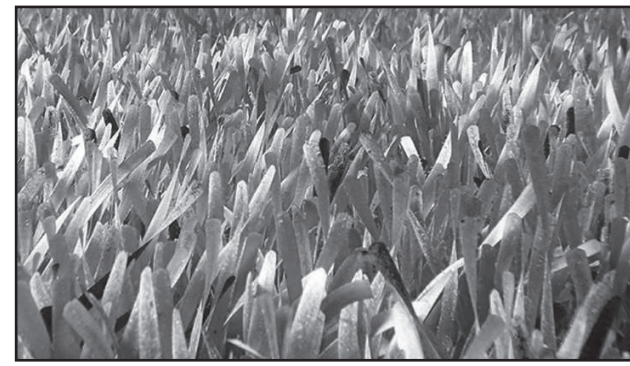

- इन शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि यह पौधा 4,500 साल पुराना है और यह अस्थिर वातावरण में भी जीवित रह सकता है।
- यह इतना बड़ा है, क्योंकि यह स्वयं को क्लोन करता है और आनुवंशिक रूप से समान शाखाएं बनाता है। इसमें समान पौधों की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है।
- हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन में विशाल बरगद भारत का सबसे बड़ा पेड़ है।

2017 में पाए गए एक गेको (छिपकली) की अब एक नई प्रजाति के रूप में पहचान की गई

- इवोल्यूशनरी सिस्टेमैटिक्स जर्नल में 'यूबलफेरिस पिक्टस' नाम की एक गेको (छिपकली) प्रजाति का वर्णन किया गया था।
- 'यूबलफेरिस पिक्टस' को पेंटेड लेपर्ड गेको के नाम से भी जाना जाता है, जो 2017 में विशाखापत्तनम में पाया गया था।
- शोधकर्ता जीशान ए मिर्जा और सी ज्ञानेश्वर ने शुरुआत में इस प्रजाति की पहचान की थी।
- अब, एक फ़ाइलोजेनेटिक अध्ययन और रूपात्मक तुलना में इसे एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया है।
- यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में पाया जाता है।
- गेको जीनस यूबलफेरिस की अब 7 प्रजातियां हैं। यह नई प्रजाति ई हार्डविकी को छोड़कर यूबलफेरिस जीनस के सभी सदस्यों से अलग है।

एनटीपीसी ने नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की

- यह जैव विविधता नीति एनटीपीसी की पर्यावरण नीति के हिस्से के रूप में जारी की गई है।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, बहाली और वृद्धि के लिए एक व्यापक ढांचा और मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करना है।

- नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) 2018 में जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था।
- एनटीपीसी ने ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 2018 में, एनटीपीसी इंडिया बिजनेस एंड बायोडायवर्सिटी इनिशिएटिव (IBBI) का सदस्य बना था।
- एनटीपीसी वर्तमान में संचालित सभी साइटों पर जैव विविधता का 'कोई शुद्ध नुकसान नहीं' प्राप्त करने के अपने प्रयास को सुदृढ़ करेगा।
- एनटीपीसी विशेषज्ञों के सहयोग से उचित प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय समुदायों, कर्मचारियों और उसके सहयोगियों के बीच जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है।

एनटीपीसी

- यह बिजली उत्पादन में शामिल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक वैधानिक निगम है।
- गुरदीप सिंह एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना

- दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा 1 जून से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा पर स्विच हो गया है।
- यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो अपनी सभी खपत जरूरतों के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करता है।
- इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा ऊर्जा की आवश्यकता का 6 प्रतिशत सौर ऊर्जा से पूरा करता है जबकि शेष 94 प्रतिशत ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों से आती है।
- अक्षय ऊर्जा के उपयोग से हवाई अड्डे को प्रति वर्ष 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
- दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डा 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
- दिल्ली हवाईअड्डा 2020 में एसीआई के हवाईअड्डा कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत 'स्तर 4+' प्राप्त करने वाला एशिया-प्रशांत क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा था।
- कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'लीडर इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट' कार्यक्रम की शुरुआत की

- राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) तथा विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) भारत ने संयुक्त रूप से 'लीडर इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट (LCCM)' कार्यक्रम शुरू किया।
- इसका मुख्य उद्देश्य शहरी पेशेवरों के बीच जलवायु कार्रवाई पहल का नेतृत्व करने की क्षमता का निर्माण करना है।
- प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई), मैसूर ने इस फेस टू फेस लर्निंग कार्यक्रम के लिए एनआईयूए और डब्ल्यूआरआई भारत के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- एलसीसीएम कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) की साझेदारी में डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है।
- ऑनलाइन लर्निंग को नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (NULP) पर होस्ट किया जाएगा। एलसीसीएम कार्यक्रम के चार चरण हैं।

डब्ल्यूआरआई भारत

- यह एक स्वतंत्र धर्मार्थ संगठन है, जो कानूनी रूप से इंडिया रिसोर्स ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है।
- यह टिकाऊ और रहने योग्य शहरों के निर्माण और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में काम करने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान

- यह भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय थिंक टैंकों में से एक है।
- यह भारत के शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है और शहरों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रैटजी फॉर सस्टेनेबिल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिल ट्रैवलर शुरू की है

- नई दिल्ली में, मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबिल टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया (आरटीएसओआई) के सहयोग से नेशनल समिट ऑन डेवलपमेंट सस्टेनेबिल एंड रिस्पान्सिबिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आयोजन किया।
- इस रणनीतिक दस्तावेज में पर्यावरण स्थायित्व को प्रोत्साहन, जैव विविधता को संरक्षण, आर्थिक स्थायित्व को प्रोत्साहन, आदि के लिए रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है।
- पर्यटकों को एक अनुभव प्रदान करने के लक्ष्य के साथ, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना शुरू की, जिसने वर्तमान में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
- मंत्रालय ने अब स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया है।
- स्वदेश दर्शन 2.0 का उद्देश्य स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दृष्टि से समग्र विकास करना है। स्वदेश दर्शन योजना 2014-2015 में शुरू की गई थी।

कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर

- आरईएन21 की रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट (जीएसआर) के अनुसार, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी है।
- भारत ने 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 15.4 गीगावाट (जीडब्ल्यू) जोड़ा। चीन ने 136 गीगावॉट जोड़ा। यूएस ने 43 गीगावॉट जोड़ा।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 843 मेगावाट पनबिजली क्षमता जोड़ी है। इससे कुल क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावॉट हो गई।
- एशिया में, भारत नई सौर फोटोवोल्टिक क्षमता के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। यह वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार था।
- भारत ने पहली बार जर्मनी को पछाड़ा। पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
- रिपोर्ट इस बात का सबूत देती है कि दुनिया की अंतिम ऊर्जा खपत में अक्षय ऊर्जा का कुल हिस्सा स्थिर हो गया है।
- यह 2009 में कम से कम 10.6% से बढ़कर 2019 में 11.7% हो गया है।
- अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि 6% की बिजली खपत में समग्र वृद्धि को पूरा नहीं कर सका।
- हीटिंग और कूलिंग में, अंतिम ऊर्जा खपत में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।
- पहली बार, जीएसआर 2022 में देश द्वारा अक्षय ऊर्जा हिस्सेदारी का वैश्विक मानचित्र शामिल है, साथ ही प्रमुख देशों में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।
- आरईएन21 की अक्षय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट (जीएसआर) अक्षय ऊर्जा पर दुनिया की एकमात्र क्राउड-सोर्स रिपोर्ट है। 2022 की रिपोर्ट 17वां संस्करण है।

विद्युत मंत्रालय ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 को अधिसूचित किया

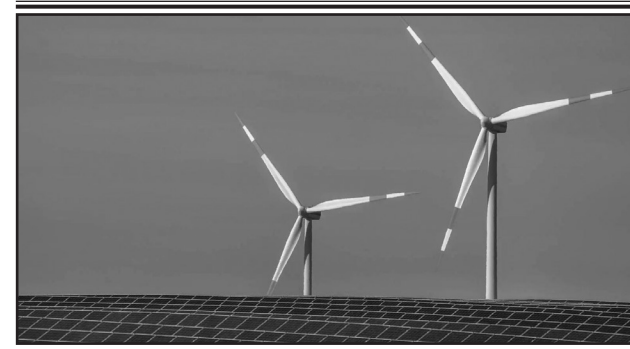

- इन नियमों को हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। यह हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुंच की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
- ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, और टिकाऊ ग्रीन ऊर्जा सुनिश्चित करना है।
- अब उपभोक्ता डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) से हरित ऊर्जा की मांग कर सकते हैं।
- नियमों के अनुसार हरित ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस लेनदेन की सीमा 1 मेगावाट (मेगावाट) से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है। यह छोटे उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा खरीदने में मदद करेगा।
- ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 ओपन एक्सेस एप्लिकेशन की स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा। अब 15 दिन के अंदर मंजूरी मिल जाएगी।
- हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ़ एक आयोग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।

एशियन कप क्वालीफिकेशन के बाद भारत फीफा रैंकिंग में दो पायदान ऊपर

- फीफा की ताजा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर पहुंच गई है।
- एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत की रैंकिंग 19वें स्थान पर रही।
- एशियाई कप क्वालीफिकेशन में भारतीय फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने तीनों लीग मैच जीते और 24 टीमों के फाइनल में जगह बनाई।
- फीफा रैंकिंग में ब्राजील शीर्ष पर रहा। बेल्जियम और अर्जेंटीना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

2026 फीफा विश्व कप तीन अलग-अलग देशों द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला विश्व कप होगा

- 2026 पुरुष विश्व कप 48 टीमों को शामिल करने वाला पहला विश्व कप होगा। इसका आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा।
- फीफा ने घोषणा की कि 2026 विश्व कप 11 अमेरिकी शहरों में आयोजित किया जाएगा। यह मैक्सिको में तीन और कनाडा में दो मेजबान स्थलों पर आयोजित किया जाएगा।
- अमेरिका दूसरी बार विश्व कप की मेजबानी करेगा। मेक्सिको तीसरी बार मेजबानी करेगा।
- यह पहली बार होगा जब कनाडा में पुरुषों का विश्व कप मैच आयोजित किया गया है। इसने 2015 में महिला विश्व कप की मेजबानी की।
- 2022 फीफा विश्व कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। यह 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा।

नीरज चोपड़ा ने फ़िनलैंड में 2022 कुओर्टेन खेलों में स्वर्ण पदक जीता

- नीरज चोपड़ा ने फ़िनलैंड में 2022 कुओर्टेन खेलों में 86.69 मीटर के एक और शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता।
- त्रिनिदाद के केशोर्न वालकॉट ने 86.64 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जबकि एंडरसन पीटर्स ने 84.75 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता।
- भारत के संदीप चौधरी 60.35 मीटर के थ्रो के साथ स्टैंडिंग में आठवें स्थान पर रहे।
- इस महीने की शुरुआत में नीरज ने फिनलैंड में हुए पावो नूरमी गेम्स में हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने रजत पदक जीता और 89.30 मीटर के थ्रो के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंडमास्टर बनें

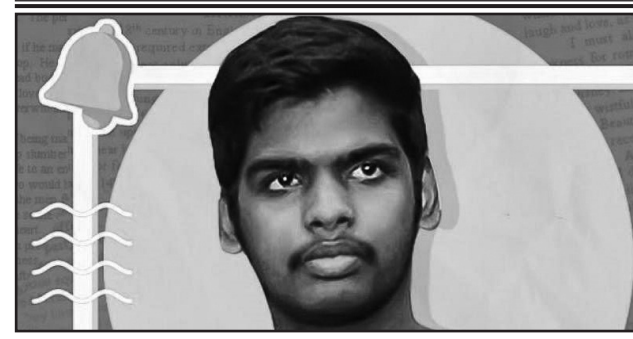

- इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान, तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी. लाइव एफआईडीई रेटिंग में 2500 (एलो पॉइंट) की बाधा को तोड़कर भारत के 74वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं।
- कैटोलिका इवेंट में ग्रैंडमास्टर लेवन पंतसुलिया के खिलाफ अपने 8वें दौर के खेल को ड्रॉ करने के बाद, 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव 2500 एलो लाइव रेटिंग अंक तक पहुंच गए।
- श्रीवास्तव ने पहले ही पांच जीएम बेंचमार्क हासिल कर लिए थे और जब उन्होंने 2500 की रेटिंग सीमा को पार किया तो उन्होंने यह खिताब जीता।
- एक खिलाड़ी को जीएम बनने के लिए तीन जीएम मानदंड और 2,500 एलो अंक की लाइव रेटिंग प्राप्त करनी होती है।
- जनवरी 2022 में भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें ग्रैंडमास्टर बने थे।
- महान विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे।

चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर

- चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है।
- समापन समारोह पंचकुला के इन्द्रधनुष स्टेडियम में आयोजित किया गया।
- खेल पांच स्थानों - पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली और शाहबाद में आयोजित किए गए।

रैंक	विजेता	पदक
पहली	हरियाणा	122 पदक- 43 स्वर्ण, 36 रजत और 43 कांस्य
दूसरी	महाराष्ट्र	112 पदक- 43 स्वर्ण, 36 रजत और 33 कांस्य
तीसरी	कर्नाटक	64 पदक- 22 स्वर्ण, 17 रजत और 25 कांस्य
चौथी	केरल	54 पदक- 17 स्वर्ण, 19 रजत और 18 कांस्य
पाँचवी	मणिपुर	25 पदक- 17 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य
छठी	दिल्ली	72 पदक- 14 स्वर्ण, 14 रजत और 44 कांस्य

खेलो इंडिया यूथ गेम्स

- 31 जनवरी 2018 को पीएम मोदी ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया। बाद में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर था, उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का स्थान था।
- 2019 में, खेलों इंडिया के दूसरे संस्करण की मेजबानी पुणे द्वारा की गई थी। पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर था, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली का स्थान था।
- 27 फरवरी 2019 को, पीएम मोदी ने खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया।
- 2020 में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कटक, ओडिशा में आयोजित किया गया था।
- 2020 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली का स्थान था।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांचवां संस्करण भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।

अवनि लेखारा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता

- उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में 250.6 स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 249.6 का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।
- एमिलिया बाबस्का ने 247.6 के कुल स्कोर के साथ रजत पदक जीता और अन्ना नॉर्मन ने 225.6 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता।
- उन्होंने 2024 पेरिस पैरालिंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।
- श्रीहर्ष देवरद्दी रामकृष्ण ने मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल एसएच2 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।
- भारत के 13 पैरा निशानेबाज फ्रांस के चेटौरौक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं।

भारत ने कजाखस्तान के अल्माटी में बोलाट तुर्लिखानोव कप में दूसरा स्थान हासिल किया

- भारत ने छह स्वर्ण, एक रजत और पांच कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते।
- छह स्वर्ण पदकों में से पांच महिलाओं ने जीते। ईरान ने सर्वाधिक पदक (14) जीते।

- सरिता मोर ने 59 किग्रा में 2022 सीज़न का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। मनीषा ने 65 किग्रा में सीनियर्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।
- 2022 बोलाट तुर्लिखानोव कप के सभी भारतीय पदक विजेता अगली तालिका में सूचीबद्ध हैं।

पदक	विजेता (महिला)	विजेता (पुरुष)
स्वर्ण	सरिता मोर (59 किग्रा), मनीषा (65 किग्रा), मानसी अहलावत (57 किग्रा), साक्षी मलिक (62 किग्रा), दिव्या काकरान (68 किग्रा)	अमन सहरावत (57 किग्रा)
रजत	बिपाशा (72 किग्रा)	-
कांस्य	पूजा सिहाग (76 किग्रा), सुषमा शौकीन (55 किग्रा)	बजरंग पुनिया (65 किग्रा), मोहित ग्रेवाल (125 किग्रा), नीरज (63 किग्रा)

- 2022 बोलाट तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता है। यह 2 और 5 जून 2022 के बीच कजाखस्तान के अल्माटी में आयोजित किया गया था।

फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने पुरुषों का खिताब जीता और इगा स्विएटेक ने महिलाओं का खिताब जीता

- स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन का 14वां एकल खिताब जीता है।
- 36 साल के नडाल इस जीत के साथ रोलैंड गैरोस के सबसे उम्रदराज चैंपियन बन गए हैं। यह उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है।

- विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने अमेरिकी खिलाड़ी कोको गौफ को हराकर पेरिस में महिला एकल का खिताब जीता।
- इस 21 वर्षीय पोलिश खिलाड़ी ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।

भारत ने फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराकर पहली बार आयोजित एफआईएच हॉकी 5एस चैंपियनशिप जीती

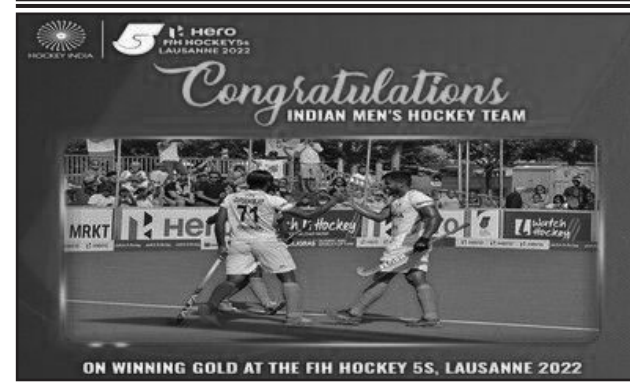

- भारत ने 04 जून 2022 को स्विट्जरलैंड के लुसान में एफआईएच हॉकी 5एस चैंपियनशिप जीती।
- भारत के राहील मोहम्मद टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर थे।
- उन्हें हॉकी 5एस लुसान 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भारतीय महिला टीम फाइनल में जगह नहीं बना पाई। हॉकी 5एस हॉकी का एक छोटा प्रारूप है।
- 2014 में नानजिंग युवा ओलिंपिक खेलों में पहली बार हॉकी 5एस मुकाबला खेला गया था।
- हॉकी 5एस लुसान 2022 दो दिवसीय टूर्नामेंट था। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) द्वारा आयोजित पहली आधिकारिक सीनियर हॉकी 5एस प्रतियोगिता थी।

साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने बोलट तुर्लिखानोव कप में स्वर्ण पदक जीते

- बोलट तुर्लिखानोव कप कुश्ती टूर्नामेंट में साक्षी मलिक ने पांच वर्षों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता।
- साक्षी मलिक ने अपना आखिरी स्वर्ण पदक 2017 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता था। उन्होंने 2020 और 2022 में एशियाई चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीते थे।

- मानसी ने 57 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एम्मा टिसिना के खिलाफ अपना स्वर्ण पदक जीता। दिव्या ने 68 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
- ग्रीको-रोमन पहलवान नीरज ने 63 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत अब तक कुल चार पदक जीत चुका है।

बोलट तुर्लिखानोव कप:

- बोलट तुर्लिखानोव कप 2022, 2 से 5 जून तक कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित एक कुश्ती टूर्नामेंट है।
- यह संयुक्त विश्व कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में दूसरा है।

भारत ने जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता

- राजकुमार पाल के शुरुआती गोल और कुछ बेहतरीन डिफेंस ने खेल में जापान को हराने में काफी मदद की।
- अपने मजबूत रक्षात्मक कार्य के लिए, भारत के कप्तान बीरेंद्र लाकड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
- दक्षिण कोरिया ने फाइनल मैच में मलेशिया पर 2-1 से जीत के साथ पांचवीं बार एशिया कप 2022 जीता।

पुरुष हॉकी एशिया कप

- एशियाई हॉकी महासंघ पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करता है।
- विजेता टीम एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई करती है और एशिया की चैंपियन बन जाती है।
- इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी।
- दक्षिण कोरिया ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा पांच खिताब जीते हैं।

भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता

- इलावेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता भारतीय महिला निशानेबाजी टीम का हिस्सा थीं।
- बाकू में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में यह भारत का पहला पदक है।
- भारतीय तिकड़ी ने स्वर्ण पदक प्रतियोगिता में डेनमार्क की अन्ना नीलसन, एम्मा कोच और रिक्के मेंग इबसेन को 17-5 से हराया।
- पोलैंड ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
- क्रोएशिया ने कांस्य पदक के मैच में भारतीय पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल को हराया।
- भारत पदक तालिका में पांचवें स्थान पर है जबकि सर्बिया कुल चार पदकों के साथ शीर्ष पर है।

मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना

- प्रधानमंत्री 800 करोड़ रुपये के परिव्यय से गुजरात में मातृ पोषण पर एक योजना की शुरुआत की है।
- मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के तहत गुजरात के आंगनबाडी केंद्रों से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हर महीने 2 किलो चना, 1 किलो अरहर की दाल और 1 किलो खाद्य तेल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
- एमएमवाई योजना का उद्देश्य गर्भवती और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके नवजात बच्चों को शुरुआती 1,000 दिनों के दौरान पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
- इस योजना से अनुमानित 1.36 लाख महिलाओं को लाभ होगा।

महत्व

- ज्ञातव्य है कि गर्भावस्था के दौरान कुपोषण और खून की कमी भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है और शिशु के खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती है। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार यह योजना लेकर आयी है।
- किसी महिला के लिए, जिस दिन से वह गर्भधारण करती है, उससे लेकर 270वें दिन तक और एक बच्चे के लिए गर्भधारण से लेकर पहले दो वर्ष या 730 दिन तक की अवधि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
- इसके अनुसार यह योजना बच्चों का ठीक तरह से विकास नहीं होना और समय से पहले प्रसव के मामलों को कम करेगी।
- बेहतर पोषण से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलती है।

प्रधानमंत्री आदिवासी-केंद्रित पोषण सुधा योजना

- प्रधानमंत्री आदिवासी-केंद्रित पोषण सुधा योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिसे पहली बार पांच आदिवासी बहुल जिलों - दाहोद, वलसाड, महिसागर, छोटा उदयपुर और नर्मदा के 10 तालुकों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू किया गया है।
- इसकी सफलता के बाद, सरकार 106 तालुका वाले 14 आदिवासी बहुल जिलों में इस योजना का विस्तार कर रही है।
- इस योजना के तहत आंगनवाड़ी में पंजीकृत गर्भवती एवं बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं को पूर्ण पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा, आयरन और कैल्शियम की गोलियों के साथ-साथ स्वास्थ्य और पोषण पर शिक्षा भी दी जाती है।

गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना

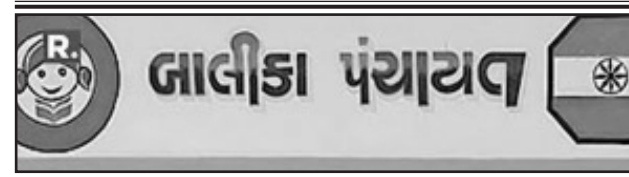

- गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है।
- बालिका पंचायत का संचालन 11-21 आयु वर्ग की बालिकाएं करती हैं।
- बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है।
- यह 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अभियान के तहत गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की एक पहल है।
- कच्छ जिले के 4 गांवों में करीब एक साल पहले बालिका पंचायत की पहल शुरू की गई थी। ये गांव कुनारिया, मस्का, मोटागुआ और वडसर हैं।

पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित

- यह विधेयक राज्यपाल की जगह सीएम ममता बनर्जी को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करता है।
- विधेयक को 294 सदस्यीय विधानसभा में वोट के साथ पारित किया गया जहां 182 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और 40 ने इसके खिलाफ मतदान किया।

- विधेयक को राज्य के शिक्षा मंत्री ने पेश किया था। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालय- विश्व भारती के चांसलर हैं तो सीएम राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर क्यों नहीं हो सकते?
- पश्चिम बंगाल विधान सभा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की एकसदनीय विधायिका है। इसमें 294 सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी हैं।

हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया

- मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 'हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022' को मंजूरी दी है।
- यह मुख्य रूप से ड्रोन-सक्षम प्रौद्योगिकी बनाने, प्रशिक्षण स्कूलों के माध्यम से जनशक्ति के निर्माण और स्टार्टअप और नवाचार योजनाओं पर केंद्रित है।
- यह रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन-सक्षम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा।
- ड्रोन निर्माण उद्योग अगले तीन वर्षों में राज्य में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर सकता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्रोन का उपयोग करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईटीआई शाहपुर को नामित किया है।
- राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने स्काई एयर और टेकईगल जैसी ड्रोन कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को अपने आधिकारिक राज्य तितली के रूप में घोषित किया

- 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 'ब्लू ड्यूक' को राज्य तितली घोषित किया।
- वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में, सिक्किम में पाई जाने वाली तितलियों की 720 प्रजातियों में से एक, ब्लू ड्यूक को 57 प्रतिशत वोट के साथ राज्य तितली के रूप में चुना गया है।
- ब्लू ड्यूक, जिसे वैज्ञानिक रूप से बासरोना दुर्गा के रूप में जाना जाता है, केवल सिक्किम और पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। यह राज्य में 1858 में खोजा गया था।
- ब्लू ड्यूक हिमालय में संरक्षित प्रजाति है, जिसे 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है।
- ऑनलाइन पोल में कृष्णा पीकॉक (पैपिलियो कृष्णा) को 43 फीसदी वोट मिले और दूसरा स्थान हासिल किया।
- मुख्यमंत्री ने 2021 में नई तितली प्रजाति की खोज के लिए सोनम वांगचुक लेप्चा को भी सम्मानित किया।
- नई तितली प्रजाति को ज़ोग्राफेटस ज़ोंगुएन्सिस कहा जाता है और इसे चॉकलेट-बॉर्डर फ्लटर के रूप में भी जाना जाता है।

ओडिशा में एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव 'सीतल षष्ठी' मनाया जा रहा

- 'सीतल षष्ठी' ओडिशा में एक हिंदू त्योहार है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है।
- यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है।
- सबसे प्रसिद्ध शीतला षष्ठी यात्रा पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर में निकाली जाती है।
- 'सीतल षष्ठी' हर साल एक भव्य कार्निवल के रूप में मनाया जाता है। उत्सव में ओडिशा के साथ-साथ अन्य राज्यों के 6,000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया।

ओडिशा के प्रसिद्ध त्योहार:

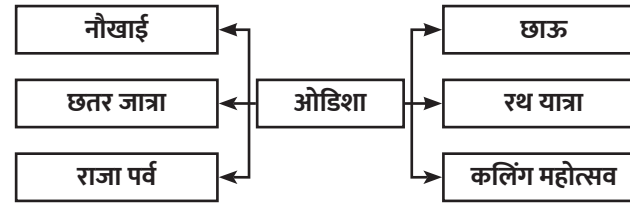

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया

- उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है।

- मगहर में कबीर के समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
- उन्होंने कहा कि जब भारत विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर रहा था, उस समय कबीर ने प्रेम, भक्ति और सद्भाव का संदेश फैलाया।

संत कबीर

- उनका जन्म 15वीं शताब्दी में काशी (वाराणसी, उ.प्र.) में हुआ था।
- उनकी रचनाएँ हिंदी भाषा में लिखी गईं।
- अपने काम के माध्यम से भक्ति आंदोलन पर उनका जबरदस्त प्रभाव था।
- उनके दो पंक्तियों के दोहे 'कबीर के दोहे' के नाम से जाने जाते हैं।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की घोषणा की

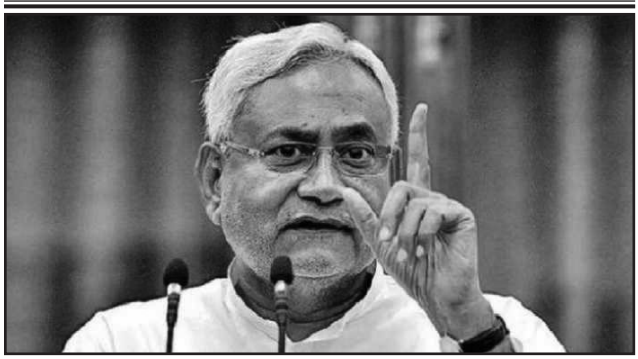

- बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन सभी दलों ने भाग लिया, जिनका बिहार विधायिका में प्रतिनिधित्व है।
- बैठक में सहमति बनी और जाति के आधार पर जनगणना शुरू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
- तीन दलों (विकासशील इंसान पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी) ने बैठक में भाग नहीं लिया, क्योंकि उनका विधायिका में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
- सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
- उन्होंने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट का निर्णय लिया जाएगा और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।
- जाति आधारित जनगणना एक समयबद्ध प्रक्रिया होगी। बिहार विधायिका इससे पहले जाति आधारित जनगणना के लिए दो बार प्रस्ताव पारित कर चुकी है।
- पहली दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी, इसमें जाति के आंकड़े शामिल थे। 1931 सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना अंतिम जाति जनगणना डेटा था, जो सार्वजनिक किया गया था।

स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया

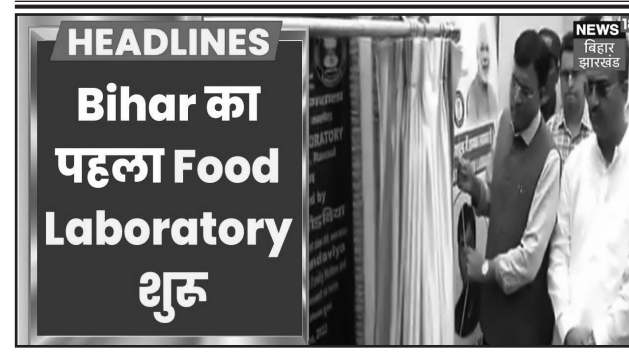

- बिहार के रक्सौल में फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया।
- इस प्रयोगशाला का निर्माण भारत और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर किया गया था, ताकि नेपाल से रक्सौल में आयातित खाद्य नमूनों का मूल्यांकन करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके।
- यह कम परीक्षण समय और आयातित नमूनों के लिए तेजी से रिपोर्ट निर्माण के माध्यम से नेपाल के साथ सीमा पार व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा।
- पहले, सभी आयातित नमूने कानूनी वैधता के साथ परीक्षण के लिए कोलकाता में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजे जाते थे।
- मंत्री ने पटना में एम्स सभागार और सीजीएचएस भवन का भी उद्घाटन किया।

तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस (डब्ल्यूएनटीडी) पुरस्कार मिला

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयास के लिए झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस (WNTD) पुरस्कार-2022 दिया।
- स्वास्थ्य विभाग के राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल ने नई दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरस्कार प्राप्त किया।
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) झारखंड में 2012 में शुरू किया गया था।
- ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस)-1 की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में झारखंड में तंबाकू की व्यापकता दर 51.1 फीसदी थी।
- 2018 में प्रकाशित गैट्स-2 रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर 38.9 फीसदी हो गई है।
- झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू की खपत को कम करने के लिए 2018 और 2022 के बीच कई पहल शुरू कीं।

महत्वपूर्ण दिवस

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022: 23 जून

- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है।
- यह खेल खेलने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
- डॉक्टर ग्रस ने 1948 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 41वें सत्र में विश्व ओलंपिक दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 1948 में मनाया गया था।
- 'टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड' इस साल के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का विषय है।
- ओलंपिक खेल हर चार साल पर आयोजित किए जाते हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने खेल आयोजनों में से एक है।

विश्व वर्षावन दिवस: 22 जून

- विश्व वर्षावन दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है।
- इसे रेनफॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस वर्ष के विश्व वर्षावन दिवस की थीम 'द टाइम इज नाउ' है।
- पहली बार विश्व वर्षावन दिवस 22 जून 2017 को मनाया गया था।
- विभिन्न संगठन, पर्यावरण के प्रति उत्साही और गैर सरकारी संगठन वर्षावनों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करके इस दिन को मनाते हैं।
- अमेज़ॅन वर्षावन, कांगो वर्षावन, सुंदरलैंड, अटलांटिक वन और पश्चिम अफ्रीका के गिनीयन वन दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण वर्षावन हैं।
- वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% को कवर करते हैं, लेकिन इसमें पेड़ों की 750 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की 400 प्रजातियां और तितलियों की 150 प्रजातियां हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: 21 जून

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को योग अभ्यास के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था।
- 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया गया था।
- "मानवता के लिए योग" अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय है।
- 21 जून को इसलिए चुना गया, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है।
- उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ से अधिक लोग योग अभ्यास में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे।

योग के लाभ

- तनाव और चिंता से राहत
- बेहतर पाचन
- इम्युनिटी बढ़ाता है
- दिल की बीमारियों का कम खतरा
- बेहतर एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है
- वजन घटाने में एड्स
- नींद की गुणवत्ता में सुधार
- लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है।

विश्व शरणार्थी दिवस 2022: 20 जून

- हर साल 20 जून को दुनिया भर के शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है।
- यह दिन शरणार्थियों की दुर्दशा को समझने और उनके जीवन के निर्माण में उनकी प्रतिरोधक्षमता को पहचानने का एक प्रयास है।
- विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम: "जो कोई भी। जहां कहीं भी। जब भी। सभी को सुरक्षा मांगने का अधिकार है।"
- सुरक्षा मांगना एक मानव अधिकार है और इसका अर्थ है शरण लेने का अधिकार, सुरक्षित पहुंच (खुली सीमाएं), अपने देश लौटने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं, सीमाओं पर कोई भेदभाव नहीं, मानवीय व्यवहार।

- यह दिन पहली बार 20 जून 2001 को 1951 के शरणार्थी सम्मेलन, जो शरणार्थियों की रक्षा में मदद करता है, की 50 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था।
- इसे मूल रूप से अफ्रीका शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाता था। लेकिन दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मान्यता दिए जाने के बाद इसे विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाने लगा।
- भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है और भारत के पास राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण ढांचा भी नहीं है।

विश्व महासागर दिवस 2022: 8 जून

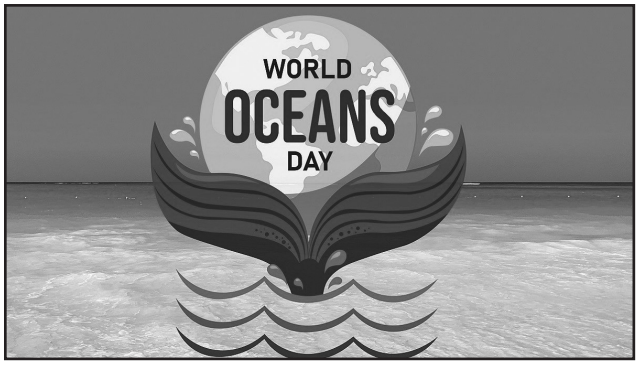

- हर साल 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है।
- पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों की भूमिका को उजागर करने और इसे संरक्षित करने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
- विश्व महासागर दिवस 2022 का विषय 'पुनरोद्धार: महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई' है।
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 2008 में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया था।
- विश्व महासागर दिवस मनाने का विचार पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) में प्रस्तावित किया गया था।
- 1973 में जहाजों से प्रदूषण, समुद्र में कचरा और जहाजों से वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन किया गया था।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस: 7 जून

- असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन की घोषणा की थी।
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम 'सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य' है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, हर साल खाद्य जनित बीमारियों के 600 मिलियन से अधिक मामले सामने आते हैं।
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 'आयुर्वेद आहार' का लोगो लॉन्च किया।
- उन्होंने खाद्य सुरक्षा के पांच मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए एफएसएसएआई चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) भी जारी किया।

विश्व पर्यावरण दिवस: 5 जून

- विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है।
- यह पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हमारे लिए प्रकृति के महत्व का वर्णन करने के लिए मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की। यह पहली बार वर्ष 1974 में मनाया गया था।
- 2022 में, स्वीडन विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 'केवल एक पृथ्वी' है।
- इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मिट्टी बचाओ आंदोलन' पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

- इस दिन का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों की ओर सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का ध्यान आकर्षित करना है।
- एसडीजी लक्ष्य 13: जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

नियुक्ति

दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
- वह वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 31 मार्च 2024 तक की गई है।
- वह कुलदीप सिंह से कार्यभार संभालेंगे, जिन्हें मई 2021 में एनआईए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
- स्वगर दास को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

- यह एक केंद्रीय एजेंसी है, जो देश भर में आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच करती है।
- इसका गठन 2008 में एनआईए अधिनियम 2008 के प्रावधान के तहत किया गया था।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

लिसा स्टालेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनीं

- ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को 'फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।
- वह इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर विक्रम सोलंकी की जगह लेंगी।
- उन्हें स्विट्जरलैंड के न्योन में एफआईसीए कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान नियुक्त किया गया है।
- लिसा स्टालेकर ने 187 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 2010 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

प्रमोद के मित्तल 2022-23 के लिए सीओएआई के नए अध्यक्ष बने

- इससे पहले, वह सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के उपाध्यक्ष थे।
- उन्होंने सीओएआई के अध्यक्ष के रूप में अजय पुरी की जगह ली है। पी बालाजी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होंगे।
- पी बालाजी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मुख्य नियामक और कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी हैं।
- वह एसोचैम नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI)

- यह 1995 में एक पंजीकृत, गैर-सरकारी समाज के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो दूरसंचार उद्योग पर केंद्रित है।

सरकार ने रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में नामित किया

- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज हैं।
- वह न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद की जगह लेंगी।
- भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति तीन सदस्यीय चयन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के अध्यक्ष औरपीसीआई के एक सदस्य को शामिल किया जाता है, जिसे इसके सदस्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए चुना जाता है।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)

- यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, जिसे पहली बार 1966 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था।
- यह प्रेस का स्व-नियामक प्रहरी है, जो प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत संचालित होता है।
- न्यायमूर्ति जे आर मुधोलकर पीसीआई के पहले अध्यक्ष थे।
- परिषद में एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं।

राजदूत रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 09 जून 2022 को राजदूत फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की।
- राजदूत रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि हैं।
- वह कम से कम विकसित देशों, लैंडलॉक्ड विकासशील देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (यूएन-ओएचआरएलएलएस) के लिए एक उच्च प्रतिनिधि भी होंगी।
- वह जमैका के कर्टेने रैट्रे का स्थान लेंगी। कर्टेने रैट्रे को शेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वह इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक हैं।
- वह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत बांग्लादेश की सर्वोच्च रैंकिंग वाली अधिकारी बन गई हैं।

मयंक अग्रवाल प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त

- दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- अग्रवाल ने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया, जिन्होंने प्रसार भारती के सीईओ के रूप में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।
- प्रसार भारती का गठन नवंबर 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

एस एल थाओसेन को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया

- जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- वह दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे।
- एस एल थाओसेन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे।
- नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता हैं।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

- यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक है।
- इसका गठन 1963 में हुआ था।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- इसका आदर्श वाक्य "सेवा, सुरक्षा और भाईचारा" है।

तपन डेका आईबी के नए प्रमुख नियुक्त

- खुफिया ब्यूरो (आईबी) के विशेष निदेशक तपन डेका को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है।
- वह मौजूदा अरविंद कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है।
- उन्हें दो साल के कार्यकाल के लिए निदेशक खुफिया ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया गया है।
- रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के वर्तमान प्रमुख सामंत गोयल को उनके कार्यकाल के लिए एक और साल का विस्तार मिला है, जो 30 जून को समाप्त हो रहा है।

पुस्तकें और लेखक

प्रधानमंत्री ने 'भारतीय संविधान: अनकही कहानी' नामक पुस्तक का अनावरण किया

- 'भारतीय संविधान: अनकही कहानी' राम बहादुर राय द्वारा लिखी गई है।
- पीएम मोदी ने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक विचार और प्रतिबद्धता है।
- पुस्तक का विमोचन उस दिन (18 जून) को किया गया है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संविधान में पहले संशोधन को 1951 में अपनी स्वीकृति दी थी।

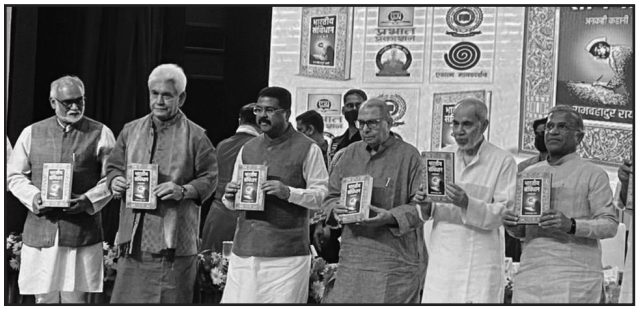

- राम बहादुर राय एक पत्रकार और हिंदी दैनिक 'जनसत्ता' के पूर्व समाचार संपादक हैं।
- मंजिल से ज्यादा सफर, शाश्वत विद्रोही राजनेता, रहवारी के सावल आदि राम बहादुर राय की कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

पुरस्कार और सम्मान

ओडिशा ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता

- ओडिशा के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने "एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022" श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- सुमित मोहंती सेफरिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर को "सेवा उद्यमिता के लिए पुरस्कार - सेवा लघु उद्यम (समग्र)"श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला।
- कालाहांडी को "एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए आकांक्षी जिलों राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022" श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला।
- राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 कुल 44 श्रेणियों में दिया गया है।
- राज्यों, केंद्र-शासित प्रदेशों और आकांक्षी जिलों को उनकीक्षेत्र-विशिष्ट नीतियों और उनके प्रदर्शन, शिकायत निवारण, क्लस्टरदृष्टिकोण के कार्यान्वयन आदि के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार दिया गया है।

सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए

- सरकार ने 23 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए।

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने 12 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए।
- भारत में निजी क्षेत्र के भीतर लॉजिस्टिक्स में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रतिवर्ष दिएजाएंगे।
- नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स (राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार) का उद्देश्य भारत में कई लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स को सम्मानित करना है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के महत्वपूर्ण विजेता नीचे दिए गए हैं:

- सर्वश्रेष्ठ रोड फ्रिट सेवा प्रदाता - डीएचएल सप्लाई चेन इंडिया पीवीटी लिमिटेड
- सर्वश्रेष्ठ रेल फ्रिट सेवा प्रदाता - अदानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
- सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह सेवा प्रदाता - डीपी वर्ल्ड
- सर्वश्रेष्ठ वेयरहाउस सेवा प्रदाता - भारतीय परिवहन निगम लिमिटेड
- सर्वश्रेष्ठ लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और सेवा प्रदाता - अदानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
- उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार - सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा

- आयुष मंत्रालय ने कहा कि पुरस्कार के लिए दो व्यक्तियों और दो संगठनों को चुना गया है। विजेताओं को नीचे दिया गया है।
- लद्दाख से भिक्खु संघसेना
- ब्राजील से मार्कस विनीसियस रोजो रोड्रिग्स
- उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी
- ब्रिटेन से ब्रिटिश व्हील आफ योग

योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार:

- 2016 में चंडीगढ़ में दूसरेअंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
- पुरस्कार के विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों में 'शेरशाह' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता

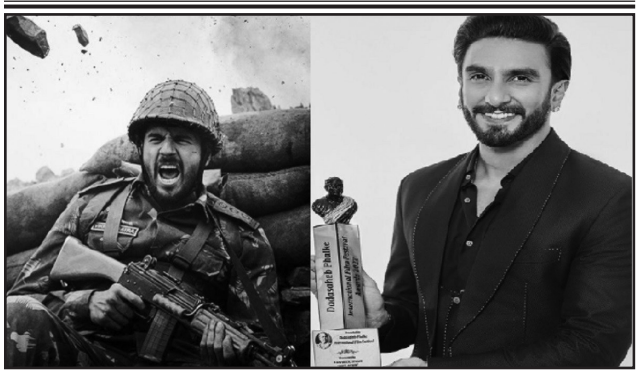

- अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार (IIFA) समारोह 3-4 जून को अबू धाबी में आयोजित किया गया।
- आईफा 2022 अवार्ड्स की मेजबानी सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने की।

महत्वपूर्ण पुरस्कार सूची नीचे दी गई है:

➲ सर्वश्रेष्ठ फिल्म	शेरशाह
➲ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष)	विक्की कौशल
➲ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला)	कृति सेनन
➲ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	विष्णुवरधन
➲ सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला	असीस कौर
➲ सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष	जुबिन नौटियाल
➲ सर्वश्रेष्ठ गीत	कौसर मुनीर

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया

- मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (एमआईएफएफ 2022) के 17 वें संस्करण में, संजीत नारवेकर को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- संजीत नार्वेकर एक फिल्म इतिहासकार, लेखक, प्रकाशक और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता हैं। उन्हें पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रकाशन और फिल्म निर्माण का अनुभव है।
- उन्होंने सिनेमा पर 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कई वृत्तचित्रों का लेखन और निर्देशन किया है।

वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

- यह महान फिल्म निर्माता वी शांताराम की याद में स्थापित किया गया है।
- इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये नकद, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

निधन

प्रसिद्ध उर्दू विद्वान गोपी चंद नारंग का निधन

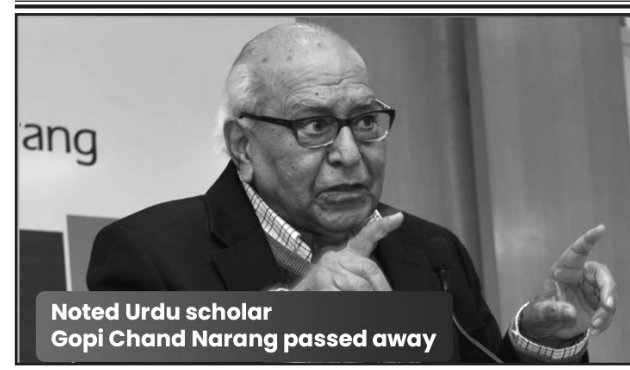

- वह एक प्रसिद्ध भाषाविद्, साहित्यिक आलोचक और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे।
- उन्हें भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों द्वारा सम्मानित किया गया था।
- वह भारत में पद्म भूषण और पाकिस्तान में सितारा-ए-इम्तियाज (स्टार ऑफ एक्सीलेंस) के प्राप्तकर्ता थे।
- उन्होंने ग़ालिब, मीर तकी मीर और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के कार्यों को समझाने पर बड़े पैमाने पर काम किया।
- उर्दू ग़ज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन-ओ तहज़ीब उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। उन्होंने अपने करियर में 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं।
- वे संस्कृत और फारसी के भी विद्वान थे।

आईएनए दिग्गज अंजलाई पोन्नुसामी का निधन

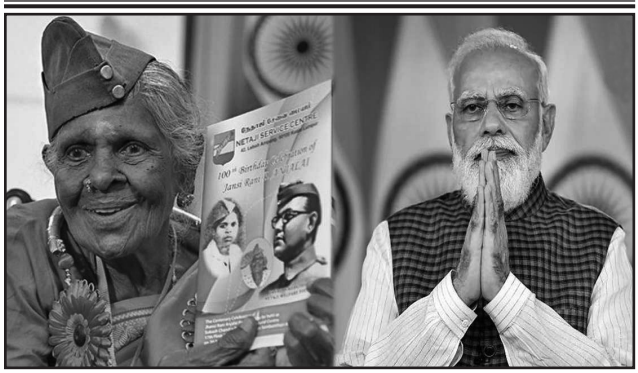

- भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की दिग्गज अंजलाई पोन्नुसामी का 102 वर्ष की आयु में मलेशिया में निधन हो गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अंजलाई आईएनए की महिला इकाई, झांसी रेजिमेंट की रानी में शामिल हो गई थी। उन्होंने अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी।
- उन्हें उनकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और निडरता के लिए याद किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए)

- इसे आजाद हिद फौज के नाम से भी जाना जाता है।
- 1942 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा इसका गठन किया गया था।
- इसका गठन शुरू में मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था।
- 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए इसे पुनर्जीवित किया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला इकाई का नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया था।

पंडित भजन सोपोरी का 02 जून 2022 को निधन

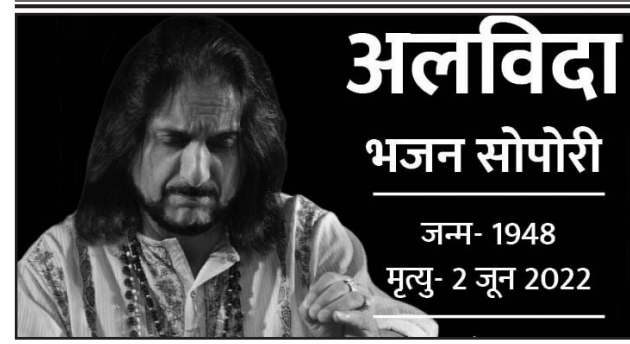

- वह एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। वह ऑल इंडिया रेडियो में संगीत के पूर्व निदेशक थे।
- उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी बड़ा योगदान दिया।
- पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ, भजन सोपोरी को कश्मीरी संगीत वाद्य यंत्र संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने का श्रेय भी दिया जाता है।
- भारतीय संतूर आमतौर पर अखरोट की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 25 ब्रिज और 100 तार होते हैं (प्रत्येक ब्रिज में 4 तार होते हैं)।
- पंडित भजन सोपोरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने के थे। वह कश्मीर घाटी के सोपोर के रहने वाले थे।

यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

1. कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
   1. उग्रवादी पुन: कांग्रेस से सम्मिलित हुए।
   2. कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांगे स्वीकार की गयी।
   3. कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार।
   2. न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य।
   3. विधान परिषदों का बहिष्कार।

   उपर्युक्त कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन के तहत सुनिश्चित किए गए?
   (a) दिल्ली अधिवेशन 1918 (b) कलकत्ता अधिवेशन 1920
   (c) नागपुर अधिवेशन 1925 (d) कानपुर अधिवेशन 1925
3. कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. इसकी स्थापना चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की।
   2. स्वराजियों का तर्क था कि विधान परिषदों में प्रवेश से असहयोग आंदोलन की प्रगति अवरूद्ध होगी।
   3. स्वराजवादियों ने विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रेरित किया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
4. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
   1. चटगांव शस्त्रागार में लूट
   2. साण्डर्स हत्याकांड
   3. केंद्रीय विधान सभा में बम विस्फोट
   4. पुलिस मुठभेड में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
   (a) 1 – 2 – 3 - 4 (b) 3 – 4 – 2 - 1
   (c) 2 – 4 – 3 - 1 (d) 2 – 3 - 1 – 4
5. साइमन कमीशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में 'प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप' में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया।
   2. लिबरल फेडरेशन और मुस्लिम लीग ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया।
   3. कमीशन में भारतीयों को शामिल न किए जाने के पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि भारतीय सुशासन के योग्य नहीं हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी
6. सूची-I (नमक सत्याग्रह) को सूची-II (नेतृत्वकर्ता) के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

सूची-I (नमक सत्याग्रह)	सूची-II (नेतृत्वकर्ता)
A. तमिलनाडु	1. गोपाल बंधु चौधरी
B. मालाबसा	2. अम्बिका कांत सिंहा
C. उड़ीसा	3. के. केलप्पन
D. बिहार	4. सी. राजगोपालचारी

कूटः

	A	B	C	D
(a)	4	3	1	2
(b)	3	4	2	1
(c)	2	4	1	3
(d)	1	3	4	2

7. भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, सभी भारतीय प्रांतों तथा देशी रियासतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था।
   2. इसके तहत प्रांतों को स्वायत्तता एवं पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
8. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) के संदर्भ में, कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. BOD का इस्तेमाल प्रदूषण मापक के तौर पर किया जाता है।
   2. जहाँ BOD उच्च होगा, वहाँ डिजॉल्वड ऑक्सीजन (DO) कम होगा।
   3. BOD के माध्यम से जैव अपघटकों का पता लगाया जा सकता है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3
9. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. यह ओजोन विघटनकारी एवं वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
   2. इसके परिणामस्वरूप CFC का उत्पादन एवं उपभोग वर्ष 2010 से प्रतिबंधित कर दिया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

10. इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. इक्ता का प्रशासन मुक्तियों द्वारा किया जाता था।
    2. सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने इक्ता को वंशानुगत बना दिया था।
    3. भारत में इक्ता का प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

11. ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. ताम्रपाषाण काल के लोग बर्तनों के निर्माण के लिए चाक का प्रयोग करते थे।
    2. इस काल के लोग प्राय पक्की ईंटों से बने मकानों में निवास करते थे।
    3. ताम्रपाषाण कालीन लोग घोड़ों से परिचित थे परंतु शायद ही उसका प्रयोग घुड़सवारी के लिए करते थे।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

12. हड़प्पा सभ्यता के शिल्प और तकनीकी ज्ञान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. औजारों और उपकरणों का निर्माण प्रायः कांसे से होता था, जिसके लिए कच्चा माल उन्हें आस-पास के क्षेत्रों से आसानी से प्राप्त हो जाता था।
    2. हड़प्पा सभ्यता के शिल्पियों में कसेरों का महत्वपूर्ण स्थान था।
    3. हड़प्पावासियों द्वारा वस्त्र निर्माण के लिए सूत की कताई तकलियों द्वारा की जाती थी।

    उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

13. ऋग्वैदिक युग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. नियमित व्यापार में धातु से बने सिक्कों का प्रयोग व्यापक तौर पर होने लगा था।
    2. वैदिक जन मुख्यत: शहरों में निवास करते थे।
    3. इस युग के लोहे से बनी वस्तु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

14. जैन धर्म के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. जैन संघ में स्त्री एवं पुरूष दोनों को प्रवेश की अनुमति थी।
    2. जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है।
    3. जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद के सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है।
    4. जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की घोर निंदा करता है।

    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
    (c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

15. गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. नागरिक और आपराधिक कानूनों को पहली बार स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था।
    2. शिल्पकारों और व्यापारियों और अन्य लोगों के समाज, उनके अपने कानूनों द्वारा शासित होते थे।
    3. गुप्तकालीन नौकरशाही, मौर्यकालीन नौकरशाही की तुलना में अधिक विस्तृत थी।

    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

16. फाह्यान की यात्रा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था।
    2. उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की भूमि को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों को एकत्रित करना था।
    3. उसे राजनीतिक मामलों में कोई रूचि नहीं थी।

    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

17. गोदावरी नदी तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन/से कथन सही हैं?
    1. गोदावरी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
    2. गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है।
    3. इस नदी द्रोणी का सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में स्थित है।
    4. कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा एवं दूध गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।

    नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
    (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 4

18. निम्नलिखित में से कौन से शहर गोमती नदी के किनारे पर बसे हैं?
    1. लखनऊ 2. जौनपुर
    3. गाजीपुर 4. बलिया

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
    (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 3
    (c) केवल 1, 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 4

19. भारत में जनांकिकी संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    1. 1921 ई. तक जन्मदर एवं मृत्युदर दोनों के उच्च रहने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न रही।
    2. 1921 ई. से 1991 ई. के मध्य तीव्र जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण मृत्यदर में कमी आना था।
    3. ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में भारत 2021 ई. से ही जनांकिकी संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है।

    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

20. उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उष्णकटिबंधीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है।
2. इन चक्रवातों का व्यास सामान्यतः 80 से 300 किमी होता है।
3. उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निरंतर पूर्व से पश्चिम दिशा में गतिशील रहते है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

21. भारतीय उपमहाद्वीप में ऊपरी वायु परिसंचरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए:
1. अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) के उत्तर की ओर स्थानांतरित होने के साथ ही पश्चिमी जेट धारा उत्तर भारतीय मैदानों से पीछे हट जाती है।
2. ग्रीष्म ऋतु के दौरान पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर प्रवाहित होती है।
3. पूर्वी जेट धाराएं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर ले आती हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

22. ज्वारनदमुख को विश्व के सर्वाधिक उत्पादक जल निकायों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कारण इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है?
1. मीठे जल और खारे जल के क्षेत्र का मिश्रण
2. तरंग क्रियाओं से ज्यादा संपर्क
3. ज्वारीय बोर की उपस्थिति

कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

23. तटीय प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में तटीय प्रवाल भित्तियों सर्वाधिक सघन एवं सतत रूप में पाई जाती हैं।
2. तटीय प्रवाल भित्तियाँ न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में अनुवात (Leeside) पार्श्व में बनती हैं।
3. स्थायी तटीय प्रवाल भित्तियाँ सामान्यतः हवाई द्वीप और अन्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की सीमाओं के निकट पाई जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

24. पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में, कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. ये पूर्वी सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवातीय अवदाब हैं।
2. रात के सामान्य तापमान में अचानक गिरावट भारत में इनके आगमन का संकेत देती है।
3. ये उत्तरी भारत में रबी की फसलों हेतु अत्यधिक लाभप्रद होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

25. निम्नलिखित प्लेट सीमांतों में से किस/किन पर नई भूपर्पटी का निर्माण होता है?
1. अभिसरण सीमा 2. अपसारी सीमा
3. रूपांतर सीमा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

26. महासागरीय धाराओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं।
2. हिंद महासागर के द्विध्रुव के कारण ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के मध्य उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं का पूर्ण रूप से व्युक्रमण होता है।
3. ठंडे एवं गर्म महासागरीय धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 1 और 3

27. ताप की विलोमता (Inversion of Temperature) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सामान्य पर्यावरणीय ह्रास दर के अनुरूप एक सीमित ऊँचाई के बाद वायु के तापमान में कमी देखी जाती है।
2. धरातलीय विलोमता की स्थिति प्रायः तब बनाती है जब शीत ऋतु में रात्रि में विकिरण द्वारा धरातल से ऊष्मा का तीव्रता से ह्रास होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

28. आग्नेय शैलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आग्नेय शैलों का निर्माण उच्च तापक्रम गलित अवस्था में खनिज पदार्थों के संपीडित होने से हुआ है।
2. ग्रेनाइट आग्नेय शैलों का सामान्य प्रकार है।
3. बेसाल्ट, गेब्रो, डायोराइट इत्यादि आग्नेय शैलों के मुख्य प्रकार हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1और 3 (d) उपर्युक्त सभी

29. निम्नलिखित में से कौन से भूकम्प की उत्पत्ति के कारण हैं?
1. ज्वालामुखी उद्भेदन 2. वलन तथा भ्रंशन
3. प्लेट विवर्तनिक क्रियाएँ 4. मानवीय क्रियाएँ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

30. कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, निम्नलिखित में सही है/हैं-
1. कोपेन ने 5 जलवायु समूह निर्धारित किए हैं जिनमें से 4 तापमान पर और एक वर्षण पर आधारित है।
2. शुष्कता वाले मौसमों को स्मॉल अंग्रेजी अक्षर से निरूपित किया गया है।
3. शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

31. एस्ट्रोसैट के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह भारत का 6वीं पीढ़ी का खगोलीय मिशन है।
2. एस्ट्रोसैट, एक ही उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलिय पिंडों का अध्ययन करने में सक्षम है।
3. बाइनरी स्टार सिस्टम जिसमें न्यूट्रॉन तारे एवं ब्लैक होल होते हैं का अध्ययन भी एस्ट्रोसैट के माध्यम से किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

32. भारतीय संघवाद में 'विविधाता में एकता' को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है?
1. अंतरराज्य परिषद 2. नीति आयोग
3. एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं

कूट:
(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1
(c) केवल 1 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तेजस सब सोनिक लड़ाकू विमान इंजन धारित करता है।
2. भारत की अवाक्स राडार प्रणाली भारत, इजराइल तथा रूस के मध्य समझौते का परिणाम है।
3. हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग सैटेलाइट एक भू-अवलोकन उपग्रह है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त और शार्टवेव अवरक्त क्षेत्रों के पास दृश्यमान किरणों से पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जनहित याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
2. संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अन्य पिछडा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया गया है।
3. राज्यपाल के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 2 और 3

35. जब विनियम दर 1$ =Rs.60 से परिवर्तित होकर 1$ = Rs.58 हो जाती है, तो इसका अभिप्राय है:
1. रूपया अधिमूल्यित हो गया है।
2. डॉलर का मूल्य घट गया है।
3. डॉलर अधिमूल्यित हो गया है।

कूट:
(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 3

36. नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है, जबकि नाभिकीय संलयन में क्रिया को प्रारम्भ करने के लिए साधारण ताप की जरूरत होती है।
2. नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रियाए होती हैं वही नाभिकीय संलयन में श्रृंखला अभिक्रियाए नहीं होती है।
3. परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) केवल 2 और 3

37. सामाजिक वानिकी के पूर्णतया सफल न होने के क्या कारण थे?
1. नीम के वृक्ष द्वारा उर्वरता में ह्रास हुआ।
2. गरीब किसानों को ईधन व चारे की उपलब्धि न मिल सकी।
3. भूमिहीन कृषकों की साझेदारी का अभाव रहा।

कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मरक्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग मलहम, सिंदूर तथा जहर बनाने में किया जाता है।
2. जिंक क्लोराइट का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है।
3. सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग तथा जल की कठोरता हटाने में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) केवल 1 और 3

39. मुंबई-पूणे औद्योगिक प्रदेश के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1869 में स्वेज नहर मार्ग खुलने से मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला।
2. मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश में स्थित होने और नम जलवायु के कारण सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ।
3. पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत के विकास ने उद्योगों की प्रगति को सुनिश्चित किया।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आदित्य L1 मिशन सूर्य के प्रभामंडल का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है।
2. आदित्य L1 एस्ट्रोसैट के बाद इसरों का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोलीय विज्ञान मिशन है।
3. इसरो द्वारा आदित्य L1 को GSLV-XL से प्रक्षेपित किया जायेगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

41. लेजर तथा मेसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लॉइट एम्पिलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एक ऐसी युक्ति है, जिसमें विकिरण प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एकवर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है।
2. माइक्रोवेव एम्पिलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्द्धन होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 21(क) के अनुसरण में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009, 1 अप्रैल 2010 से देशभर में लागू हुआ।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 वाली स्कूली शिक्षा को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जो 2+3+3+4 पर आधारित है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में द्वि-भाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

43. रेडियोएक्टिविटी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रेडियोएक्टिव पदार्थ की उस मात्रा को एक बेकुरल कहा जाता है जो प्रति सेकेंड एक विघटन या विकिरण का उत्सर्जन करती है।
2. मैडम क्यूरी ने रेडियोएक्टिव तत्व को शीशे के प्रकोष्ठ में रखकर निकलने वाली किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजार कर निकलने वाली किरणों का अध्ययन किया, इन्हें अल्फा, बीटा और गामा नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

44. सामाजिक वानिकी ग्रामीणों के विकास हेतु सहायक है-
1. हरियाली मे विस्तार तथा परिस्थितिकी संतुलन की सुरक्षा करके।
2. फलों के उत्पादन में वृद्धि करके देश के खाद्य संसाधनों में वृद्धि करके।
3. मवेशियों के चारे की व्यवस्था करके।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

45. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं?
1. देश में, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधुनिक आधार संरचना उपलब्ध करवाना।
2. कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करना।
3. 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' के आधार पर किसानों को कच्चे माल की आपूर्ति हेतु भूमि उपलब्ध करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

46. 'भारतीय अंतरिक्ष विजन 2025' के संदर्भ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 90वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2003, बंगलुरु में 'भारतीय अंतरिक्ष विजन 2025' प्रस्तुत किया गया।
2. सौर प्रणाली और ब्रह्मांड की समझ को परिष्कृत करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान मिशन को विकास करना।
3. पुनर्प्रयोज्य विमोचन यान-तकनीक का विकास करना।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से भारतीय अंतरिक्ष विजन 2025 के संदर्भ में सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

47. लाइकेन से लाभ हैं-
1. लाइकेन का प्रयोग भोजन के रूप में नहीं होता है।
2. कुछ लाइकेनों का प्रयोग चट्टानों से खनिज लवणों को प्राप्त करने में किया जाता है।
3. कुछ लाइकेन कपड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं को रंगने के काम में प्रयुक्त किये जाते हैं।

कूट:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1 और 2

48. भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है।
2. इनसैट प्रणाली की पहली पीढी के उपग्रहों का निर्माण रूस में किया गया था।
3. संचार क्षेत्र के उपग्रहों से दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना हुई, साथ ही Ku बैंड के ट्रांसपोंडरों के माध्यम से DTH सुविधा भी शुरू की गई।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

49. चन्द्रयान II के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चन्द्रयान II मिशन का उद्देश्य केवल चंद्रमा के एक क्षेत्र का अध्ययन करना है।

2. इस मिशन के लिए स्वदेशी प्रेक्षपण यान GSLV MK-III का प्रयोग किया गया, जो भी भारत का सबसे अधिक भार ले जाने वाला प्रक्षेपण यान है।
3. चन्द्रयान II के रोवर का नाम विक्रम था, जिसका कार्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना था।

उपर्युक्त कथनों कौन-सा/से सही है/है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अर्थव्यवस्था का चतुर्थ क्षेत्र शिक्षा, खोज, अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियों के नाम से जाना जाता है।
2. किसी अर्थव्यवस्था के सभी निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचम क्षेत्र में रखा जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

51. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ऐसा कोई देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, भी महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का एक पक्ष बनाया जा सकता है, जो इसके परामर्श क्षेत्राधिकार के क्षेत्र का विषय है।
2. ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत महासभा अथवा सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

52. विटामिन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विटामिन A की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है।
2. पेन्टाथोनिक एसिड, उपापचय में महत्वपूर्ण सहएंजाइम है।
3. विटामिन सी का कार्य कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचयन है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

53. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह परिषद मानवाधिकारों के सम्मान और मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित करती है।
2. यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित मामलों पर अध्ययन की पहल करने के साथ उन पर रिपोर्ट तैयार करती है।
3. यह आपसी बातचीत के द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

54. प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रोकैरियोटिक कोशिकांए अर्द्धविकसित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक विकसित होती हैं।
2. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता।
3. प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्राय: जीवाणु व नील हरित शैवालों में पायी जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका सभी जंतुओं व पौधों में पायी जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) केवल 1 और 2

55. ट्रांसफैट के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये संतृप्त वसा की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते है, क्योंकि इनके सेवन से LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि होती है।
2. ट्रांस फैट, वसा का सबसे हानिकारक रूप होता है।
3. यह मधुमेह, मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध, उपापचय सिंड्रोम, बांझपन तथा कुछ प्रकार के कैंसर हेतु मुख्य कारक है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

56. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के उद्देश्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा विश्वभर में बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करने व उसके उपयोग को प्रोत्साहन देना है।
2. बौद्धिक संपदा का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के सरलीकरण तथा साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के प्रसार द्वारा बौद्धिक संपदा का विस्तार करना है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

57. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला तथा कोशिकांग की सुरक्षा करती है।
2. माइट्रोकान्ड्रिया में श्वसनीय एंजाइम पाये जाते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन स्थनान्तरित होते हैं।
3. लाइसोसोम का मुख्य कार्य अंतः कोशिकीय पाचन कोशिकीय विभाजन है, इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 2 और 3

58. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. साइकस का पेड़ आवृतबीजी का उदाहरण है जिससे साबूदाना बनता है।
2. अनावृतबीजी में बीज आवरण नहीं पाया जाता है।
3. आवृत बीजी पौधे एकबीजपत्री एवं द्विबीजपत्री वर्गों में बांटे जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

59. चुनावी बॉण्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम एक फीसदी मत प्राप्त किया हो, चुनावी बॉण्ड के जरिए चंदा ले सकता।
2. सरकार ने चुनावी बॉण्ड को जारी करने के लिए आरबीआई को अधिकृत किया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

60. स्पॉट एक्सचेंज के लाभ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्ष कीमत निर्धारण क्योंकि कीमतों का निर्धारण परम्परागत मंडी, जहां कीमतों का निर्धारण केवल स्थानीय भागीदारी से तय होता था, के विपरीत पूरे देश के विस्तृत भागों एवं भिन्न लोगों द्वारा होता है।
2. स्पॉट एक्सचेंज कीमत निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
3. स्पॉट एक्सचेंज, रूर्टेलाइजेशन और वस्तु बाजार में प्रचलित इस प्रकार की अन्य अस्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1

61. बौलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र की विशेषता है-
1. राकेट इंजन प्रक्षेपास्त्र को आरंभिक चरण में प्रणोदित करता है, इसके बाद प्रक्षेपण मार्ग गुरूत्वाकर्षण द्वारा निर्धारित होता है।
2. बैलिस्टिक मिसाइल के दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये मिसाइल ईधन का वहन स्वयं नहीं करती।
3. इनका प्रक्षेपण मार्ग परवलयी आकार का होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

62. वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद के लक्ष्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय स्थायित्व बनाए रखने की प्रणाली को मजबूत और संस्थागत करना।
2. अंतर नियामक सहयोग को विस्तार देना।
3. वित्तीय क्षेत्र विकास को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

63. एक जिला, एक उत्पाद योजना की विशेषताएं हैं-
1. सामान्य/सार्वजनिक प्रसंस्करण एवं अन्य अधिसंरचनाओं, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग आदि आस्तियों की स्थापना।
2. स्वयं सहायता समूहों के बीजक पूंजी एवं छोटे उपकरणों की खरीद के लिए 40,000 रुपया सहायता।
3. ब्रांडिंग एवं विपणन कार्यों के लिए लागत का 50% अनुदान।

कूट:
(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

64. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. डीमेट खाते बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं तथा इन्हें नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिट्री लिमिटेड में जमा रखा जाता है।
2. जब कोई देश मुक्त मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत अपनी विनिमय दर में जोड़-तोड़ करके विदेशी व्यापार का लाभ उठा सके तो यह डर्टी फ्लोट कहलाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

65. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य है-
1. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन देना।
2. विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था।
3. भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता की उपलब्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा तथा उनकी अवधि में कमी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

66. गांधी-इरविन समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस समझौते द्वारा सभी बंदियों, जिनके विरूद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, को रिहा करने का आदेश दिया गया।
2. समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति प्राप्त हुई।
3. कांग्रेस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

67. फेसलेस पेनल्टी स्कीम 2021 के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना, दंडात्मक कार्यवाही के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर, क्षेत्रीय पेनल्टी सेंटर, पेनल्टी यूनिट और रिव्यू यूनिट की स्थापना का प्रावधान करती है।
2. यूनिट और निर्धारिती के बीच सभी संचार या तो मोबाइल ऐप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे।
3. भौतिक सुनवाई की अनुमति केवल सीबीडीटी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

68. बैंकों के निजीकरण के मुख्य लाभ हो सकते हैं:
    1. उच्च वित्तीय विकास एवं संवृद्धि।
    2. वित्तीय समावेशन में घतांकीय वृद्धि होगी।
    3. सरकार पर वित्तीय भार कम होगा, NPA कम होगा।

    नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए:
    (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

69. केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरणों के अधीन भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट 1988 के अंतर्गत आरोपित किसी लोक सेवक के विरूद्ध केंद्र सरकार की अनुशंसा पर उस लोक सेवक के विरूद्ध मामले की छानबीन करना।
    2. भ्रष्ट्राचार निरोधक अधिनियम 1988 के अधीन किये गये अपराध के लिए आरोपों की जांच हेतु दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापन द्वारा की गई जांच पड़ताल की प्रगति की समीक्षा करना।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

70. मार्ले-मिटों सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. मुसलमानों के लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद् में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया।
    2. गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।
    3. केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि तथा निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था।

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

71. ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित स्रोतों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें-
    1. थर्मल 2. जलविद्युत
    3. परमाणु 4. नवीकरणीय
    5. गैस आधारित ऊर्जा

    नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए:
    (a) 1 > 2 > 4 > 3 > 5 (b) 1 > 4 > 2 > 5 > 3
    (c) 4 > 1 > 2 > 3 > 5 (d) 4 > 2 > 1 > 5 > 3

72. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के विषय में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. यह कृषि मंत्रालय की योजना है।
    2. यह दीनदयाल अत्योंदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक भाग है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) केवल 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

73. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
    1. अधिशेष आय का अभाव
    2. आवश्यक दस्तावेजों की कमी
    3. उत्पाद के बारे में जागरूकता का अभाव
    4. सिस्टम में विश्वास की कमी
    5. प्रदान की गई सेवाओं की ख़राब गुणवत्ता

    भारत में वित्तीय अपवर्जन के उपर्युक्त में से कौन-से कारण हैं?
    (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2, 3 और 5
    (c) केवल 2, 4 और 5 (d) उपर्युक्त सभी

74. 'ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल' योजना के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. यह योजना पायलट आधार पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने चलाई है।
    2. इस योजना के अंतर्गत किसान रेल से अधिसूचित फल और सब्जियों की ढुलाई पर किराये का 50% सब्सिडी दी जा रही है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

75. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
    (a) भारत के राष्ट्रपति द्वारा
    (b) संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके
    (c) संसद द्वारा विधि बनाकर
    (d) भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा

76. विश्व में चावल के उत्पादन के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. एशिया महाद्वीप विश्व के कुल चावल उत्पादन में 90% से ज्यादा का योगदान करता है।
    2. चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा भारत का दूसरा स्थान है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

77. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. उस शेयर की बिक्री करना, जिसकी विक्रेता के पास उपस्थिति/स्वामित्व नहीं हो 'शार्ट सेलिंग' कहलाता है।
    2. जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए बार-बार की जाती है, तो इसे प्रारंभिक आम निर्गम कहते हैं।
    3. वे शेयर जो कंपनी द्वारा अपने पुराने शेयर धारको को मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं, स्क्रिप शेयर कहलाते हैं?

    उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

78. मिशन शक्ति के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. मिशन शक्ति, इसरो द्वारा विकसित एक तकनीकी प्रदर्शक मिशन है, जिसका उद्देश्य भारत की एंटी सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन करना था।
    2. एंटी सैटेलाइट परीक्षण तकनीकी केवल अमेरिका और भारत के पास है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

79. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इनकी स्थापना वर्ष 1975 में एक अध्यादेश के माध्यम से की गई थी।
2. वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें तरलता समायोजन सुविधा (LAF) और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के उपयोग की सुविधा नहीं दी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

80. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी स्वतंत्रता दी गई है?
1. सामाजिक स्वतंत्रता 2. आर्थिक स्वतंत्रता
3. राजनीतिक स्वतंत्रता 4. धार्मिक स्वतंत्रता
5. विश्वास की स्वतंत्रता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 4 और 5
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 1, 2, 3 और 4

81. 'भारत का संघ' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'भारत का संघ' के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है।
2. इसके क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय (भविष्य में) भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

82. भारत सरकार विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्डहोल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का निम्नलिखित में से किन स्थितियों में पंजीकरण रद्द कर सकती है?
1. यदि OCI कार्डहोल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है।
2. यदि पंजीकरण रद्द करना किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं सामान्य जनता के हित में हो।
3. यदि OCI कार्डहोल्डर को पंजीकरण के पांच वर्षों के भीतर दो वर्षों से कम की कैद की सजा हुई है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

83. मूल अधिकारों के विभिन्न उपबंधों में प्रयुक्त 'राज्य' शब्द के अंतर्गत शामिल हैं:
1. नगर पालिकाएं
2. जिलाबोर्ड सुधार न्यास
3. गैर-संविधानिक प्राधिकरण
4. सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (PSU)

कूट:

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

84. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधियों का समान संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित है/हैं:
1. विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता।
2. साधारण विधि न्यायालय के तहत् सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार।
3. बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार।

कूट:

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

85. साधारण कानून के तहत् हिरासत के लिए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से अधिकार प्राप्त हैं?
1. मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में पेश होने का अधिकार, जिसमें यात्रा का समय सम्मिलित नहीं है।
2. दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार।
3. विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

86. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्तमान में केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि उच्चतम न्यायालय उचित समझे तो किसी अन्य न्यायालय को भी यह अधिकार दे सकता है।
2. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

87. निम्नलिखित में से कौन-सा/से राज्य के नीति निदेशक तत्व उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं?
1. राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा (अनुच्छेद 42)।
2. उद्योगों के प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा (अनुच्छेद 43।)।
3. कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना (अनुच्छेद 48)।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए-

(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

88. निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए:
    1. राजभाषा का प्रयोग
    2. केंद्रशासित प्रदेश
    3. संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन
    4. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व

    उपर्युक्त में से कौन से उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
    (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

89. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी सम्पत्ति विश्व में कही भी हो, पर लागू होता है।
    2. असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को स्वायत्त जिलों में प्रयोज्य न कर या विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

90. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. 101वां संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार व शक्ति प्रदान करता है।
    2. राज्य विधायिका को आयात एवं निर्यात के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

91. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए:
    1. राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने संबंधित सभी प्रस्ताव संसद सामान्य बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए।
    2. इसको समाप्त करने के लिए लोकसभा से इसकी घोषणा वापस लेने हेतु प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है।
    3. यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नही करता है।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

92. प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण (PEM) शिशुओं एवं बच्चों को प्रभावित करता है, जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें से मरास्मस (Marasmus) भी एक है। मरास्मस (Marasmus) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. यह प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की एक साथ अल्पता से उत्पन्न होता है।
    2. यह 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में पाया जाता है।
    3. इसका मुख्य कारण प्राय: कम अंतराल में पुन: गर्भधारण अथवा शिशु का जन्म होना है।
    4. इसमें मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास बहुत अधिक मंद हो जाता है।

    उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
    (c) केवल 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

93. संविधान की नौवीं अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. इसे प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया।
    2. नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों को अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है।
    3. यह केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

94. दिल्ली के लिए विशेष उपबंध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. दिल्ली पूर्णतया केंद्र द्वारा शासित प्रदेश है और अंतिम अधिकार केंद्र के जरिए राष्ट्रपति के पास है।
    2. विधानसभा होने के बावजूद दिल्ली के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी उपराज्यपाल को दी गयी है।
    3. 69वां संविधान संशोधन इस बात की पुष्टि करता है कि इस पर केंद्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

    उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
    (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

95. व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट (2014) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. यह एक्ट ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं, उनकी पहचान को गोपनीय रखने की एक विधि प्रस्तुत करता है।
    2. कंपनी अधिनियम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के गवर्नेंस मानदण्डों द्वारा इन प्रावधानों को अपनाया गया है।

    उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
    (a) केवल 1 (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

96. निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:
    1. कृषि आय पर कर 2. विद्युत के उपभोग पर कर
    3. अंतर्देशीय तीर्थ यात्राएं 4. संविदाएं

    उपर्युक्त में से कौन से विषय राज्य सूची से संबंधित हैं?
    (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
    (c) केवल 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

97. सूची-I (प्राचीन विश्वविद्यालय) को सूची-II (अवस्थिति) के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

सूची-I (प्राचीन विश्वविद्यालय)	सूची-II (अवस्थिति)
A. ओदंतपुरी	1. बंगाल
B. जगद्दल	2. कर्नाटक
C. शारदापीठ	3. कश्मीर
D. मान्यखेत	4. बिहार

कूटः

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	4	3	1	2
(c)	2	1	4	3
(d)	4	1	3	2

98. भित्ति चित्रकला के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह ठोस संरचना वाली दीवारों पर निर्मित की जाती है।
2. इस कला के चित्रों में सबसे आम विषय हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म है।
3. प्राचीन काल में इस चित्रकला का प्रयोग किसी लौकिक भवन का अलंकरण करने के लिए किया जाता था।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

99. रागमाला चित्रकला के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह प्राचीन भारत के संगम युग से संबंधित चित्रकला की शृंखला है।
2. इन चित्रों में प्रत्येक राग का एक विशेष भाव में नायक और नायिका कहानी का वर्णन करने वाले रंग से वैक्तिकरण किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

100. बोधिसत्व मंजुश्री का चित्र कहां की सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारियों में से एक है?

(a) अजंता (b) एलोरा
(c) चित्तानवासल (d) बादामी

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(b)	3.	(a)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(a)	7.	(b)	8.	(d)	9.	(a)	10.	(c)
11.	(a)	12.	(b)	13.	(a)	14.	(a)	15.	(a)	16.	(d)	17.	(b)	18.	(b)	19.	(b)	20.	(b)
21.	(d)	22.	(b)	23.	(c)	24.	(c)	25.	(a)	26.	(d)	27.	(b)	28.	(d)	29.	(d)	30.	(d)
31.	(c)	32.	(d)	33.	(b)	34.	(a)	35.	(b)	36.	(a)	37.	(b)	38.	(c)	39.	(d)	40.	(b)
41.	(c)	42.	(d)	43.	(a)	44.	(d)	45.	(a)	46.	(d)	47.	(b)	48.	(a)	49.	(b)	50.	(c)
51.	(d)	52.	(b)	53.	(d)	54.	(a)	55.	(d)	56.	(c)	57.	(b)	58.	(c)	59.	(a)	60.	(b)
61.	(a)	62.	(d)	63.	(d)	64.	(c)	65.	(d)	66.	(b)	67.	(d)	68.	(a)	69.	(c)	70.	(d)
71.	(b)	72.	(b)	73.	(d)	74.	(c)	75.	(c)	76.	(c)	77.	(b)	78.	(a)	79.	(a)	80.	(b)
81.	(d)	82.	(d)	83.	(d)	84.	(b)	85.	(c)	86.	(d)	87.	(a)	88.	(d)	89.	(c)	90.	(c)
91.	(c)	92.	(d)	93.	(c)	94.	(d)	95.	(c)	96.	(c)	97.	(d)	98.	(d)	99.	(b)	100.	(a)

भव्य शुभारंभ **10 जुलाई 2022** को भोपाल में

IAS दीक्षांत Education Centre PCS

18 वर्षों से ईमानदार प्रयास

Speaker Dr. S.S. Pandey
Founder Dikshant IAS and
Best Sociologist of India

OPEN SEMINAR

10 JULY
11:00 AM

Dr. Anil Kumar Upadhyay
MP Head

UPSC / MPPSC ADMISSION OPEN

शुरु के 100 बच्चों को **50%** Discount

OFFLINE **सामान्य अध्ययन** ONLINE

CSE RESULT - 2021 Top 5 in Top 10

भोपाल ब्रांच

प्लॉट नं. 48, 3rd फ्लोर, सरगम टॉकीज के पीछे, जोन-2, एमपी नगर, भोपाल

Cont.: 9301110498, 8982208515

दीक्षांत
Education Centre

UPSC CSE RESULT - 2021

CONGRATULATIONS

Our 200+ Successful Candidates of UPSC Civil Service Examination - 2021-22

1 Rank — SHRUTI SHARMA — Roll No. - 0803237

3 Rank — GAMINI SINGLA — Roll No. - 3524519

4 Rank — AISHWARYA VERMA — Roll No. - 5401266

6 Rank — YAKSH CHAUDHARY — Roll No. - 0834409

9 Rank — PREETAM KUMAR — Roll No. - 1118762

24 Rank — SAHITYA PUSAPATI — Roll No. - 5110593

31 Rank — AVINASH — Roll No. - 0323860

33 Rank — JASPINDER SINGH — Roll No. - 3516855

35 Rank — KARTIKEYA JAISWAL — Roll No. - 0413129

43 Rank — SHUBHAM SHUKLA — Roll No. - 0623772

44 Rank — ANJALI SHROTRIYA — Roll No. - 7808206

50 Rank — ABHIJEET RAY — Roll No. - 8101939

53 Rank — ARPIT SANGAL — Roll No. - 0835485

54 Rank — ARPIT GUPTA — Roll No. - 6000943

57 Rank — ALFRED OV — Roll No. - 1903199

60 Rank — SHRADDHA GOME — Roll No. - 7806666

62 Rank — TIRUMANI S POOJA — Roll No. - 6206389

71 Rank — SHREYA SHREE — Roll No. - 6808285

73 Rank — NAMRATA CHOUBEY — Roll No. - 4103715

93 Rank — DEEPESH KUMARI — Roll No. - 0879483

96 Rank — MINI SHUKLA — Roll No. - 6903989

200 + Results

289, DHAKA JOHAR, NEAR DUSSEHRA GROUND, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09 ✆ 7428092240